The House reassembled after lunch at two minutes past two of the clock, MR. CHAIRMAN in the Chair.

## DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE

MR. CHAIRMAN: Shri Rama Shanker Kaushik.

**श्री रमा शंकर कौशिक** (उत्तर प्रदेश) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि कृषि मंत्रालय के कार्यकरण पर, कृषि जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा आरम्भ करने का मुझे अवसर मिला। श्रीमन्, हमारे देश में हमारी आर्थिक व्यवस्था के मामले में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान हमेशा से रहा है और सदियों से हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता रहा है। हमारी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, हमारे त्योहार, हमारा रहन-सहन, हमारी विचार शैली - इन सबका ताल्लुक कृषि से रहा है। लेकिन आज हमारे देश में कृषि के संबंध में जो स्थिति है, वह बहुत ही दुखद होती चली जा रही है। महोदय, कृषि मंत्रालय का कार्य है कि कृषि की उपज को बढ़ाए। दूसरा है कि जो कृषक हैं, जो खेती पर निर्भर हैं, उनकी उपज का उनको लाभप्रद मूल्य मिले और तीसरा उनकी माली हैसियत बढ़े। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कृषि मंत्रालय के द्वारा इन तीनों ही बातों में पूरी तरह से उपेक्षा बरती गयी है। हम यह मानकर चलते थे, योजना आयोग यह मानकर चलता है कि अगर हमें अपनी विकास दर, पूरे देश की विकास दर को आठ प्रतिशत तक ले जाना है तो निश्चित रूप से कृषि की विकास दर को बढ़ाना पड़ेगा। यह केवल कहने की ही बात नहीं है, पिछला अनुभव भी यह बताता है कि जब जब कृषि की विकास दर बढ़ी है, तब तब हमारे सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर भी बढ़ी है। हमारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था यह तकादा अवश्य करती है कि हमारी कृषि की विकास दर बढ़नी चाहिए। वैसे, कृषि मंत्रालय ही नहीं, हर मंत्रालय एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। किसी भी एक मंत्रालय को हम यह नहीं कह सकते कि वह निरपेक्ष है। ज़िंदगी के अन्य सारे पहलू जैसे एक-दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, उसी प्रकार से हर मंत्रालय एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है, लेकिन जहां तक कृषि मंत्रालय का सवाल है, वह तो अनेक विभागों से बहुत ही निकटता के साथ जुड़ा हुआ है। वह रासायनिक मंत्रालय के साथ पूरे तरीके से जुड़ा हुआ है, उद्योग मंत्रालय के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। वाणिज्य मंत्रालय से उसका रिश्ता अब और गहरा होता चला जा रहा है, वह पहले भी था लेकिन हमारी उदारीकरण और आयात-निर्यात की नीति के कारण वह आज और भी गहरा हो गया है। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि कृषि मंत्रालय की आवाज़ इन मंत्रालयों में बहुत ही कम है जिसकी वजह से कृषकों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। कृषि मंत्रालय को भी जो उनके लक्ष्य हैं, उनका जो मकसद है, उसे हासिल करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए पहली मांग तो श्रीमन्, मैं आपकी मार्फत से सरकार से यह करना चाहूंगा कि कृषि मंत्रालय में कुछ ऐसी शक्ति निहित की जानी चाहिए जिससे कृषकों की भलाई के लिए और हमारी कृषि की विकास दर को बढ़ाने के लिए कृषि मंत्रालय दूसरे विभागों में दखल दे सके। हम देखते हैं कि गन्ना कृषि मंत्रालय का विषय है लेकिन चीनी की नीति दूसरा विभाग बनाता है। इसी प्रकार से और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें दाम तय किए जाते हैं - चाहे गन्ने की कीमतों के मामले में हो या जो सपोर्टिंग प्राइस होता है, उसके मामले में हो - उसमें भी कृषि मंत्रालय की आवाज़ वैसी नहीं है जैसी होनी

चाहिए। इसलिए सबसे पहली मांग तो मैं सरकार से यही करूंगा कि कृषि मंत्रालय का पुनर्गठन इस प्रकार से हो कि सभी संबंधित मंत्रालयों में, जिसका रिश्ता कृषि विभाग से बहुत अधिक है, उसकी आवाज की कुछ कीमत होनी चाहिए।

श्रीमन्, हमारे देश का हर किसान चाहे वह गन्ना बोता है, चाहे गेहूं बोता है, चाहे कपास बोता है या आलू पैदा करता है, वह आज परेशान है। उसको कीमतें नहीं मिलतीं। उसको उसकी उपज का उचित मूल्य ही नहीं मिलता, लाभप्रद मूल्य की बात तो हम क्या करें! माननीय मंत्री जी ने गन्ना किसानों की दुर्दशा के संबंध में बड़ी साफ बात कही थी कि सरकार, मिल-मालिक और न्यायालय किसानों की, विशेष रूप से गन्ना किसानों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार हैं। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं लेकिन इसमें भी अगर श्रीमन्, आप मूल रूप से जाएंगे तो पाएंगे कि निश्चित रूप से केवल सरकार और सरकार ही जिम्मेदार है। सरकार इस ढंग से कानून क्यों बनाती है कि न्यायालय उसमें दखल दे सके या मिल-मालिक उसका फायदा उठा सके? सरकार ही दोषी है, इस प्रकार के कानून बनाकर सरकार जो ambiguity पैदा करती है, जो विषमताएं पैदा करती है, उन विषमताओं के लिए सरकार ही जिम्मेदार है और सरकार के कारण ही यह हो रहा है।

श्रीमन्, आज कृषकों की हालत बहुत ही खराब है। हम यह देखते हैं कि हमारे सकल घरेलू उत्पाद मे आज़ादी के समय हमारी कृषि का हिस्सा साठ प्रतिशत होता था, आज वह हिस्सा बाईस प्रतिशत, तेईस प्रतिशत रह गया है। बाईस, तेईस प्रतिशत अपने में महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं कि जैसे-जैसे विकास की स्थिति बढ़ेगी, जैसे-जैसे और उद्योग बढ़ेंगे, जैसे-जैसे और नए पहलू उजागर होंगे, हमारी कृषि का हिस्सा सकल घरेलू उत्पाद में कम होता चला जाएगा। लेकिन यह बाईस प्रतिशत, तेईस प्रतिशत महत्वपूर्ण नहीं है, आज़ादी के समय के साठ प्रतिशत का इसलिए महत्व ज्यादा है क्योंकि तब भी हमारे यहां खेती के ऊपर निर्भर रहने वाले लोगों की तादाद 75 फीसदी थी और आज भी 75 फीसदी है। अगर हम विकसित देशों की ओर देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि कृषि का हिस्सा उनके सकल घरेलू उत्पाद मे बहुत ही कम है। केवल तीन प्रतिशत है। जो पूरे तरीके से विकसित देश हैं उन देशों में सकल घरेलू उत्पाद में उनकी कृषि का हिस्सा केवल तीन प्रतिशत है। लेकिन खेती पर निर्भर रहने वाले लोगों की तादाद भी केवल एक प्रतिशत है। मैं तो यह मानता हूं कि इस ढंग से सकल घरेलू उत्पाद मे जिस वर्ग का, जिस समूह का, जितना हिस्सा होता है उसको उसी अनुपात से मिलता है। इसलिए अगर हमें कृषि के ऊपर आधारित रहना है, अगर हमारी 75 फीसदी जनता को कृषि के ऊपर रहना है तो हमारी कृषि का जो हिस्सा सकल घरेलू उत्पाद में होना चाहिए, वह बहुत ज्यादा होना चाहिए। अगर कृषि में हमारा सकल घरेलू उत्पाद का हिस्सा कम होता चला जाता है तो निश्चितरूप से कृषि पर निर्भर लोगों की संख्या कम होनी चाहिए। तब जाकर हमारा किसान आगे बढ़ पाएगा अन्यथा जो आज दयनीय स्थिति है,वही रहेगी। यह बात भी साफ है कि हमारे देश में संपूर्ण विकास की स्थिति तब तक नहीं आ सकती जब तक हमारे देश का किसान जो खेती के ऊपर आधारित है। जब तक इन 75 फीसदी लोगों की तरक्की नहीं होगी तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। श्रीमन्, योजना आयोग ने फैसला लिया था कि हम कृषि की उपज को चार प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ाएं। योजना आयोग का यह भी कहना है कि जब तक हम कृषि के विकास की दर चार प्रतिशत नहीं करेंगे

आठ प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद की हमारी विकास दर हासिल नहीं हो सकती। यह भी योजना आयोग का कहना है। लेकिन वही योजना आयोग, कृषि मंत्रालय द्वारा जब पच्चीस हजार करोड़ रुपए की मांग की जाती है तो उनकी मांग को घटाकर केवल तेरह हजार दो सौ करोड़ रुपया देता है। बावन फीसदी-इतनी बड़ी कटौती? पच्चीस हजार करोड़ रुपए की मांग और पूर्ति केवल तेरह हजार दो सौ करोड़ रुपए की। यह कैसा व्यवहार है? किस प्रकार से हम चार प्रतिशत की रफ्तार से प्रतिवर्ष अपनी कृषि की दर को बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ जाएगी? श्रीमन्, अस्सी और नब्बे के दशक में हमारे देश ने कृषि के मामले में तरक्की की है और प्रतिवर्ष हमने तीन प्रतिशत से ज्यादा की विकास दर हासिल की। तब हमारा सकल घरेलू उत्पाद भी 5.62 परसेंट बढ़ा था। लेकिन नब्बे से जो दशक शुरू हुआ है तब से हमारी कृषि गिरती चली जा रही है। उसकी विकास दर में कमी आती चली जा रही है और आज स्थिति यह है कि हमारी कृषि की प्रतिवर्ष विकास दर 1.7 प्रतिशत है और हमारी आबादी 1.9 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ रही है। हम इस बात से बड़े संतुष्ट हैं कि हमारे भंडार भरे पड़े हैं। हम इसका यह अंदाजा लगाते हैं कि हमारे देश में कोई भूखा नहीं मर रहा है। श्रीमन्, यह बिल्कुल गलत आंकलन है। हमारे देश में लोग भूखों मर रहे हैं। यूएनओ की रिपोर्ट है कि बीस प्रतिशत लोग कुपोषण के शिकार हैं। ये लोग कौन हैं? कैसे कुपोषण हो रहा है? क्या उपलब्धता है हमारी? प्रति व्यक्ति उपलब्धता क्या है? हम दुनिया के सब देशों से ज्यादा जमीन पर खेती करते हैं। अमरीका केवल 21 प्रतिशत अपनी भूमि पर खेती करता है और हम 57 प्रतिशत पर खेती करते हैं। चाइना और भी कम करता है। जापान 12 प्रतिशत भूमि पर खेती करता है। हम 57 प्रतिशत पर खेती कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी हमारे यहां अन्न की उपलब्धता क्या है, प्रति व्यक्ति 176 किलोग्राम प्रतिवर्ष। चाइना में 370 किलोग्राम प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति। केवल पेट भरने का ही सवाल नहीं है। इसका मतलब और भी होता है, इसका मतलब कपड़ा भी होता है, इसका मतलब रहन-सहन भी होता है। वैसे भी अगर पेट भरने का हिसाब लगाया जाए तो आधा किलो प्रतिदिन का हिसाब बैठता है और चीन ने 370 किलोग्राम उपलब्धता हासिल करने के बाद भी वह अपने यहां इसको कम मानता है। वह इसको बढ़ाना चाहता है। चूंकि वह जानता है इस बात को। वे भी कृषि के ऊपर इस कदर निर्भर हैं, वे चाहते हैं कि उसके यहां कृषकों की स्थिति सुधरे। हम लोग इस बात पर विचार नहीं कर रहे हैं । अगर अन्न की उपलब्धता का प्रति व्यक्ति हिसाब लगाया जाए, तब इस प्रकार की स्थिति है । हमारा निवेश घटता चला जा रहा है । जहां तक कृषि का मामला संबद्ध है तो पूंजी का हमारे यहां पहले जितना खर्च होता है, कुल पूंजी में से होता था, उस पूंजी के हिसाब से भी आज हमारी स्थिति बहुत ही कमजोर होती चली जा रही है । यह बात सही है कि हमने राष्ट्रीय आय को बढ़ाया है । हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है लेकिन यह भी सही है कि हमारी राष्ट्रीय आय का केवल चौदह प्रतिशत हिस्सा कृषि पर आधारित लोगों को मिलता है । छियासी प्रतिशत दूसरे लोगों को मिलता है । कृषि पर पचहत्तर फीसदी लोग आधारित हैं । उन्हें राष्ट्रीय आय का केवल चौदह प्रतिशत हिस्सा मिलता है । हालांकि हमने राष्ट्रीय आय बढ़ाई है लेकिन किसानों की हैसियत को हम न तो बढ़ा पाए हैं और न ही उनके लिए कुछ कर पाए हैं । सभापति जी, ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि जब तक हम अपनी पूंजी नहीं बढ़ाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा । अस्सी के दशक में जो हमारी कुल पूंजी लगी थी, उसमें से पंद्रह प्रतिशत कृषि क्षेत्र में लगाया गया था लेकिन आज यह स्थिति हो गई है कि कुल पूंजी में से केवल आठ प्रतिशत हम कृषि पर खर्च कर रहे हैं । अगर फिर भी हमारा कृषि मंत्रालय यह सोचता है कि किसान अपने अनाज को निर्यात करें तो कृषकों की स्थिति सुधर जाएगी तब मैं पूछना चाहता हूं

कि वह अपने गेहूं का निर्यात कैसे करेगा ? वह कौन सा तरीका है जिससे वह दुनिया के देशों से कम्पीटीशन कर ले ? हम अपने किसान को क्या दे रहे हैं ? क्या हम समय पर पानी दे पाते हैं, क्या हम उन्हें अच्छा बीज, अच्छी खाद दे पाते हैं ? क्या हम उसे सब्सिडी के रूप में कुछ दे रहे हैं ? हम उसे नहीं दे रहे हैं । सभापति जी, आज अगर आप दुनिया की हालत देखें, जो देश कृषि पर आधारित भी नहीं हैं, जो कृषि प्रधान देश भी नहीं कहलाते हैं उन देशों में कृषि के लिए कितना कुछ किया जा रहा है । यह देखेंगे तो आपको पता चलेगा । मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं जिससे आप देखें कि किस प्रकार से किसानों की सहायता की जा रही है । आप इन्हें देखें । यूरोपीयन यूनियन में तीस देश सदस्य हैं । वे अपने यहां एक हेक्टेयर पर एक हजार इकसठ डॉलर की सब्सिडी देते हैं । जापान में एक हैक्टेयर पर छह हजार नौ सौ पंद्रह दशमलव छह डॉलर (6915.6) की सब्सिडी दी जाती है । हमारे यहां शोर मचता है कि हम अपनी सब्सिडी घटाते चले जाएंगे क्योंकि डब्ल्यू.टी.ओ. का फैसला है, डब्ल्यू.टी.ओ. के निर्देश है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्देश हैं, विश्व बैंक के निर्देश हैं, इसलिए हम अपने यहां की सब्सिडी घटाते चले जाएंगे । आज जो दे रहे हैं वह केवल 17.8 डॉलर प्रति हेक्टेयर है । कहां एक हजार इकसठ डॉलर प्रति हेक्टेयर और कहां सत्रह दशमलव आठ डॉलर प्रति हेक्टेयर । हमारा किसान किस प्रकार से कम्पीटीशन कर सकता है ? उनके जो भाव होंगे, उन भावों की तुलना हम अपने उत्पादन से कैसे कर सकते हैं ? आप क्यों सब्सिडी घटाते जा रहे हैं, किसके निर्देश पर घटा रहे हैं ? अगर सब्सिडी नहीं देंगे, उसे कोई सहायता नहीं देंगे तो वे कम्पीटीशन कैसे करेंगे ? आज भी आपने निर्यात के लिए बड़ी भारी घोषणाएं की हैं । क्या घोषणाएं की हैं ? किसान को उससे क्या मिलने वाला है ? चौबीस हजार करोड़ रुपए आपने अपने बजट में इस वर्ष किसान के लिए सब्सिडी के रूप में रखे हैं । इसमें से ज्यादा हिस्सा तो उन लोगों को चला जाएगा जो गेहूं का निर्यात करेंगे । गेहूं के निर्यात का लाभ किसान को नहीं मिलेगा । गेहूं का निर्यात करने वाले को आप केवल चार रुपए पैंसठ पैसे प्रति किलो के हिसाब से गेहूं देंगे । सारी सब्सिडी वह ले जाएगा । किसान को आप क्या देने वाले हैं ? चौबीस हजार करोड़ रुपए में से अधिक हिस्सा तो उन लोगों के पास चला जाएगा जो निर्यात करेंगे । गेहूं की कीमत आप चार रुपए पैंसठ पैसे प्रति किलो के हिसाब से देंगे । यह आप बिलो पावर्टी लाइन के लोगों को देते हैं । यह आपका फैसला है। इससे किसानों को कहां लाभ होने वाला है ? इसी प्रकार से गन्ना किसानों की स्थिति आपने देखी है । आप तो खुद मानते हैं कि इनकी दुर्दशा के लिए सरकार जिम्मेदार है । आज भी उत्तर प्रदेश में किसी भी किसान को यह नहीं मालूम है कि उसके गन्ने की उसे क्या कीमत मिलेगी । पर्ची पर लिखा नहीं जा रहा है । गन्ना तोला जा रहा है। किसान गन्ना देने के लिए मजबूर है । उसे अपना खेत खाली करना है, वरना वह सूख जाएगा । लेकिन उसको यह भी पता नहीं है कि उसको उसकी क्या कीमत मिलने वाली है । आज यह दुर्दशा हमारे किसान की है । आलू आज सड़ रहा है । उसको खरीदने के लिए आपके पास जो नॉफेड एजेंसी है वह नाकाम है और वह खरीद नहीं रही है । भंडारण की व्यवस्था नहीं है । किसान एक रुपये से कम किलो के रेट पर आलू बेचने के लिए मजबूर है। 70 और 80 रुपये क्विंटल के भाव से किसान का आलू खरीदा जा रहा है । आज यह स्थिति उसकी हो गई है । आप कहते हो कि निर्यात से उनकी स्थिति सुधरेगी । मैं यह कहता हूं कि जब तक आप किसानों को उसकी किसानी के लिए पूरा हक और पूरी सुविधा नहीं देंगे तब तक किसी भी प्रकार से आप अपने देश की स्थिति सुधार नहीं सकते हैं और न ही इस देश के किसान की स्थिति सुधर सकती है ।

श्रीमन्, अब मैं खाद के मामले में कहना चाहता हूं । इन्होंने यूरिया के पैसे बढ़ाए थे जो कि अब इन्होंने घटा दिए हैं । लेकिन फॉसफोरस पर सबसिडी नहीं है । पोटाश, आप पैदा नहीं कर रहे हैं । आप जरूर बताते होंगे, जरूर कहते होंगे, लेकिन चूंकि आपकी कोई आवाज़ नहीं है, इसलिए पोटाश, जो पोटाश धान की फसल के लिए अत्यन्त आवश्यक है, उसकी कमी के कारण धान की फसल हमारे यहां कम होती चली जा रही है, पैसा तो धान का भी नहीं मिलता है, पैसा उसे गेहूं का भी नहीं मिलता है और पैसा उसे गन्ने का भी नहीं मिलता है, लेकिन हमारी फसल चौपट हो रही है और आप कहते हैं कि हम खरीदते हैं। आप क्या खरीदते हैं ? आप केवल 25 परसेंट पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से खरीदते हैं और बाकी 75 प्रतिशत तो आप खरीदते ही नहीं हैं । चावल में भी आप लेवी लगाते हैं मिलों पर और किसी भी कीमत पर धान खरीदने की आप उसे छूट देते हैं । आप उसके ऊपर कोई भी सपोर्टिंग मिनिमम प्राइस की धारा नहीं लगाते, कोई बंदिश नहीं लगाते । वह चाहे जिस भाव से खरीदे । केवल आपको आपकी जरूरत का 50 फीसदी चावल वह दे देता है । आपको उसकी कोई परवाह नहीं है कि किसान को उसके धान की कीमत मिल रही है या नहीं मिल रही है । अभी गेहूं भी आना शुरू हो गया है लेकिन आपकी कहीं भी तोल अभी तक जारी नहीं हुई है और आगे भी कैसे हो पाएगी, यह भी हम देखते रहते हैं और देखते रहेंगे ।

श्रीमन्, अब एक बात पर और जोर दिया जा रहा है कि बागवानी करो । परंपरागत खेती छोड़ दो । गेहूं बोना छोड़ दो । हमारे देश में बहुत भंडारण है । नहीं होगा तो दूसरे देश बहुत पैदा करते हैं । हम आयात कर लेंगे । क्या यह नीति सरकार की रहेगी ? मैंने जैसे निवेदन किया कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अन्न की क्या उपलब्धता है और हमें चार प्रतिशत कृषि की विकास दर हासिल करना आवश्यक है चूंकि हम 8 प्रतिशत विकास दर सकल घरेलू उत्पाद में चाहते हैं, तो क्या इस प्रकार से हो पाएगा ? आप कह रहे हैं कि बागवानी करो । आपकी क्या स्थिति है ? कीटनाशक आपके पास है नहीं, उसके बिना बागवानी की खेती होती नहीं और उसके मामले में भी आप लोगों को जानकारी देते नहीं कि किस वक्त कौन सा कीटनाशक आवश्यक है । आपने पिछले साल फर्माया था कि हम कृषि क्लीनिक खोलेंगे और हर ब्लॉक में खोलेंगे । लेकिन अभी तक तो कहीं दिखाई नहीं देता । हमारे यहां देश में 34 कृषि विश्वविद्यालय हैं और एक सैन्ट्रल विश्वविद्यालय भी है । उनमें से 14-15 हजार स्नातक हर साल निकलते हैं । उनका हम कोई उपयोग नहीं कर रहे हैं ।

**[उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) पीठासीन हुए]**

आज आप कह रहे हो कि अनुबंधित खेती करेंगे । हमारे देश के किसानों को आप किसके सहारे छोड़ना चाहते हो ? श्रीमन्, हमारे देश का किसान बहुत छोटी-छोटी जोतों वाला किसान है । 62 फीसदी हमारे यहां एक हेक्टेयर से कम की जोतें हैं, 18 फीसदी एक हेक्टेयर और चार हेक्टेयर के बीच में हैं और उससे आगे 16 प्रतिशत हैं । तो हमारे यहां 62 फीसदी लोग एक हेक्टेयर से कम जोत वाले हैं । उनको आप चाहते हैं कि वे अनुबंधित खेती करें। वैसे यह अनुबंधित खेती वाला प्रयोग कोई नया नहीं है । यह अपने देश में काफी दिनों से चला आ रहा है । लेकिन यह भी पता चलता है कि अनुबंधित खेती के बाद जो स्थितियां होगी वे वही होगी जो निर्यात के रूप में होने जा रही हैं और विदेशी कंपनियां हमारे देश में हावी होती चली जा रही हैं ।

आज भी हमारे यहां जो अनुबंधित खेती हो रही थी, वह विदेशी कंपनियां ही कर रही थी । "पेप्सी" ने पंजाब के किसानो से कहा कि टमाटर बोओ । उन्होने टमाटर बोया, फिर पेप्सी को पता नही क्या हुआ, उस ने उसे हिंदुस्तान लीवर को बेच दिया । हिंदुस्तान लीवर भी विदेशी कंपनी है । उस ने वह काम बंद कर दिया और पंजाब का किसान झटका खा गया । इसी प्रकार से हिंदुस्तान लीवर कंपनी मध्य प्रदेश में भी गेहूं बुवा रही है । आप बड़े औद्योगिक घरानो को यह कार्य देगे और शायद शुरूआत उसी से करें । महोदय, हमारे देश का औद्योगिकीकरण भी बढ़े, हमारे उद्योग की पूंजी वहां लगे, यह सही बात है कि आप इस बात को करेंगे, लेकिन होना यही है कि विदेशी कंपनियां हावी होती चली जाएंगी । महोदय, सार्वजनिक क्षेत्र मे भी यह अनुभव किया जा रहा है कि जो हमारा बीज निगम है, वह बीज की खेती विशेष रूप से गेहूं और विशेष रूप से बीज देकर कराता है । वह ठीक है, लेकिन अगर आप इस ढंग से छोटे किसानो को जो कि पूरी जानकारी नहीं रखते हैं, उन को बड़े औद्योगिक घरानो के हवाले कर देगे और अंततोगत्वा विदेशी कंपनियों के हवाले कर देगे तो हमारे देश के किसान का क्या होगा, यह आप को विचार करना पड़ेगा । आपको इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि उन का पूरा फिर से शोषण न हो सके ।

श्रीमन्, निर्यात के मामले मे भी हम लोगों को बड़ी सतर्कता के साथ आगे बढ़ना होगा क्योकि दुनिया का जो ट्रेड चल रहा है, आप यह समझिए कि कोई भी देश, कैसा भी निर्यात करता हो, किसी भी ढंग की चीजो का निर्यात कर रहा हो, आज से 10 साल पहले विदेशी कंपनियो के हाथ में जहां केवल 10 प्रतिशत निर्यात का काम था, आज उन की हैसियत यह है कि दुनिया के पूरे-के-पूरे निर्यात का 50 प्रतिशत हिस्सा विदेशी कंपनियों के हाथ में है । आज वहां की कंपनियो के हाथ मे भी वह नही रहा, जो विदेशी मल्टी-नेशनल कंपनीज हैं, उन के हाथ मे दुनिया का 50 प्रतिशत निर्यात है । तो आपको इन सारी बातो पर विचार करना होगा और अनुबंधित खेती के मामले मे छोटे किसानो की सुरक्षा का पूरा-का-पूरा ध्यान आपको करना पड़ेगा तब जाकर आप ठीक से काम कर पाएंगे।

श्रीमन्, मैंने अभी जिक्र किया कि हमारे देश मे 34 कृषि विश्वविद्यालय हैं और एक सेट्रल विश्वविद्यालय है । अब उन में से जो 14-15 हजार विद्यार्थी निकलते हैं, उन का उपयोग किया जाय । आप ने संभवतः कृषि क्लीनिक खोलने का एलान भी किया है । आप हर ब्लाक मे कृषि क्लीनिक खोलिए जो कि कीटनाशको और अच्छे खादों की पूरी सूचना सीधे किसान को दे सके । इस से किसान का कुछ भला आप कर सकेगे ।

आपको सब्सिडी के मामले में सोचना चाहिए । जब आप दुनिया से कम्पटीशन की बात करते हैं तो जब तक आप अपने किसान की स्थिति पूरी तरह ठीक नहीं करेंगे, उस को भी उसी प्रकार से सब्सिडी नहीं देगे जिस प्रकार से विदेशों में दी जा रही है तब तक हमारा किसान कम्पटीशन करने लायक नहीं होगा ।

**उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी)** : कौशिक जी, आप समाप्त करिए । आप के 28 मिनट हो गए हैं, जल्दी समाप्त कीजिए ।

**श्री रमा शंकर कौशिक** : श्रीमन्, मैं समाप्त कर रहा हूं । हमें हमारे कृषि मंत्री जी और कृषि राज्य मंत्री जी से बहुत उम्मीद है क्योंकि दोनों ही किसान वर्ग से आते हैं, दोनों ही किसानो की समस्याओं को समझते हैं, लेकिन पता नहीं किस प्रकार की लाचारी है कि हम अपने देश मे कृषि निवेश नही बढा पा रहे हैं, कृषकों के लिए न्याय नहीं कर पा रहे हैं । उन को उन की उपज का लाभप्रद मूल्य नहीं दिलवा पा रहे हैं चाहे वह कपास का किसान हो, चाहे आलू का किसान हो या कोई और हो ।

आप परंपरागत खेती छोड़ने की बात करते हैं. लेकिन परंपरागत खेती मे तो आप की तिलहन की खेती भी आती है । आप तिलहन की खेती को बढ़ावा क्यों नहीं दे रहे हैं ? महोदय, इसी साल तिलहन की खेती में 25 प्रतिशत की कमी हुई है जबकि आप के यहां खाद्य तेल की 60 प्रतिशत की कमी रहती है और आप विदेशों से मंगवाते हैं और जिस पर हजारो करोड़ रुपए की फारेन करेंसी खर्च होती है । लेकिन तिलहन पर हम लोगों का ध्यान नही है । हमारा तिलहन का उत्पादन नही बढ़ रहा है । इस साल वह 25 प्रतिशत घटा है जिस प्रकार से अन्न हमारे यहां 13.6 प्रतिशत घटा है, तिलहन इस वर्ष 25 प्रतिशत घटा है । इस तरह परंपरागत खेती में केवल गेहूं ही नही आता है और भी फसले आती हैं। हम चाहते हैं कि जमीन के ऊपर होने वाली खेती पर निर्भर लोगों की संख्या कम हो। इसमे कोई शक नहीं कि यह संख्या कम होनी चाहिए, लेकिन कम कैसे होगी, जबकि आपकी नीतियां, सरकार की नीतियां ऐसी नही हैं, जिससे कोई दूसरे रोजगार के अवसर सृजित हो सके। आज छोटे उद्योग बंद होते चले जा रहे हैं और जब छोटे उद्योग बंद होते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से जो रोजगार के नए अवसर होते हैं वे नही निकल पाते।

इन्ही शब्दो के साथ, श्रीमन्, मैं एक बार फिर यह निवेदन करूंगा कि कृषि मंत्रालय का पुनर्गठन हो, जिससे उन विभिन्न मंत्रालयों में उसकी आवाज कुछ तेज हो सके ताकि किसानो का और हमारी खेती का भला हो सके। बहुत-बहुत धन्यवाद ।

DR. A.R. KIDWAI (NCT of Delhi): Sir, today we are discussing the working of the Ministry of Agriculture. It is a very important matter. Agriculture is the mainstay of our country's economy because 70 to 75 per cent people are dependent on agriculture and the remaining 25 per cent people are also directly or indirectly dependent on agriculture. Our industries, the sugar industry, the cotton industry, the jute industry and many other industries, are based on agricultural raw material. Their progress depends on agriculture. Therefore, this aspect of our economy is the most important aspect. Last year, when there was recession, the contribution of industrial production towards growth rate was only 3.3 per cent; whereas agriculture could maintain its position. So far as production is concerned, when India became Independent, we were producing 60 million metric tonnes of foodgrains. But today the production has gone up to 212

million tonnes which is four times more than it was earlier. The production has gone up by four times because of the hard efforts and hard work of the farmers and because of the contribution made by the scientists. But the condition of our farmers today is worse than ever before. Their income has gone down. Their purchasing power has gone down and their living condition is as bad as it was never before. Why is there no improvement in the living condition of farmers in spite of all these efforts?

India is now the second largest producer of milk with 88 million tonnes of milk. India is the second largest producer of vegetables in the world and fourth largest producer of fruits. But where are the results of production? The Agriculture Ministry, which is the nodal Ministry so far as development of agriculture is concerned and which has to look after the interests of the farmers, has to give a serious thought to what is happening to agriculture and has to see how the interests of the farmers are being sacrificed. As a result of this, we have not been able to eradicate poverty even after more than 50 years of Independence. Our Plans are lagging behind. This is a very serious responsibility. You cannot get away by saying that it is the responsibility of the State and that some other Ministry has to look into it. So far as agriculture is concerned, the primary responsibility rests with the Ministry of agriculture. As the Central Ministry, the Ministry of Agriculture has to look after the interests of farmers and agriculturists. Please let me state some of the major problems which the country is facing in agriculture, and I am happy that the Agriculture Minister is here to listen. I have great regard for him because his father was one of the greatest pioneers and real leaders of the farmers. But, how far will he be able to discharge his duties? I hope he will be able to come up to the expectations of the farmers.

Take the case of sugar industry. Sugar produced for the last two years is still unsold. It is lying in the godowns. Farmers have not been able to get their dues, as my earlier speaker has explained. Two to three years' dues are still with the mills; they have not been paid to the farmers. And, we are able neither to sell the sugar nor export it. The reason is, perhaps, the Ministry has never thought of or tried to find out why we can't export the sugar and sell it. The refined sugar produced in India does not conform to the standards of purity as required by the American and European markets, because the method of purification used in India is obsolete. Nobody in the world uses sulphur dioxide and calcium hydroxide

for the purification of sugar solutions. And, therefore, there is 20 per cent loss of sugar in the processing itself. How can this kind of industrial production of sugar lead to profitability? How can ever India compete in the international market? If we produce crude sugar, perhaps, we would have been better off. Why produce refined sugar when you cannot improve? We got the machinery about 75 years ago when the Dutch introduced sugar industry in Indonesia. The same technology is continuing even today and in spite of its criticism, they have not been able to improve. So, the fault is of the industrial technology which is being used, to which Ministry of Agriculture has not paid any attention and the farmer is at the receiving end. The farmer is suffering. The industry is suffering.

Then, take the case of cotton. Cotton is one of the most important products for this country, on which not only the yarn production, textile production, garment production and handloom production depend, but a large population is also dependent on the textile industry. In fact, this is an industry where India can be a leading exporter of cotton textiles in the world. But, because of the sad plight of the development of cotton industry, the exports are suffering and the people and the agriculturists associated with cotton industry are committing suicide. If we cannot improve and increase cotton production, then why have we got this Ministry and the Section dealing with this, if they cannot deal with such projects?

Another area is of oil. We had introduced Oil Technology Mission and we were successful as a result of the efforts of the farmers. We were able to raise our oil production up to 75 per cent of our requirements. But, because of the policy adopted for import from outside, we had a setback; the farmers have given up cultivation of oilseeds and production of oil. If this is how we are going to deal with the oil production for the country, it is a great difficulty. Whichever Ministry may be responsible, but it should have stood up to the demands of the farmers.

Then, coming to pulses, our country is a vegetarian country, and, therefore, pulses constitute the most important source of protein in diets. What is the record of success today in pulses? We have not been able to increase our pulse production. If the scientists, if the institutions, which have been set up, cannot deliver the goods, then, what is the use of their function? That means there is no such task force and plans to really deal with the important problems pertaining to agricultural production in the country.

Then, coconut, which is a source of living in many coastal areas in South India, is affected by certain pests and diseases. We have not yet found a solution. There is no solution as yet. Now, is this the way the affairs of agricultural development are going to be dealt with in this country?

India, since time immemorial, has enjoyed leadership in spices. But these are also the areas which have suffered recently. These are the areas where India should have maintained its leadership in the world in the production of spices and other crops. But what have we attained? Not only can we maintain the leadership, but today we are also victims of inefficiency in dealing with these products. So, this is the state of affairs with the major crops in agriculture. I hope the Agriculture Minister will be able to go deeply into it in consultation with the experts and find solution for these things.

Then, Sir, fisheries is an area which is totally neglected in India. In the Ninth Plan, there was a provision, say, Rs.50 lakhs a year, for a coastal engineering centre to set up harbours. This, in the Tenth Plan, has been reduced to only Rs.10 lakhs a year. There is no other provision for fisheries in the Budget of the Department of Animal Health and Husbandry. Of course, there is some provision in the Department of Agriculture Research and Education. Now, fishery is the best protein food in the world, and it gets you the highest price. India is exporting 75 per cent of its marine fisheries - 41 per cent to Japan, about 20 per cent to the U.S. and another 15 per cent to Europe. So, we are directly exporting 75 per cent of our marine fish products, and we are earning Rs.63,000 crores by way of export of 45,000 tonnes of fishes. Can not we double it or treble it? India, with its coastal line of more than 8,000 kilometres and with 29,000 running kilometres of rivers, can be the largest producer of fish in the world. Located in tropical and sub-tropical climatic conditions, the Indian Ocean, the Arabian Sea and the Bay of Bengal are the richest sources. But we have no programme for the development of marine resources. The foreign ships are poaching in our areas. But we do not care. India today produces the best prawns in the world, the tiger prawns, and the best crabs from the Sunderban area, which is a rich area for aquaculture. It has remained undeveloped. We have not even utilised one-third of our resources for fisheries development. It gets you the hard foreign exchange from exports. It is painful to note that even 55 years after Independence, the large population of fishermen represent the poorest of the poor people living in the coastal areas, who endanger their lives to go out to the sea for

fishing in their traditional boats. In this age of 21st century, the fishermen are still using the same traditional boats, to the extent of about two lakhs ! We have got only 50,000 motorised boats and about another 50,000 which are mechanised boats. That means two-thirds of boats are primitive boats with no communication system. Once they go out to the sea, they do not know whether they would come back or not. They cannot get any warning. Now, allowing this kind of thing to continue in this age, I think, requires a serious examination and consideration by this august House, whether the way we are treating some of the professions, some of the people, is correct or not. To earn their livelihood, they have to endanger their lives, risk their lives to produce products, 75 per cent of which are exported. This is the condition of the fisheries.

In order to remove poverty and help destitute women, indigent people, India has sponsored, our plans have sponsored, some schemes for self-employment, for group financing, in order to help these people to improve their quality of life and save them from poverty. The NABARD was established in 1982 to provide credit at 5 per cent, 7 per cent and 9 per cent, and there was a provision that the banks getting refinance from the NABARD will not charge more than three per cent interest on the refinance. That was reasonable. Actually, it should not be more than 1-1/2 to 2 per cent, because the operational charges are not very high. But they were allowed to charge 3 per cent. But one fine morning, in the name of liberalisation, in 1994, the Reserve Bank issued orders removing any ceiling. The banks were left free to charge any amount of interest on the money that they were getting for refinance from the NABARD at the interest rates of 5 per cent, 7 per cent and 9 per cent. They were lending the money not only at their own rates, but even at higher rates, because farmers cannot provide 'AAA' category. They were given loans at interest rates of 16 to 20 per cent in the earlier days. Now, the loans given against refinance to the farmers carry interest rates from 14 per cent to 19 per cent. The banks are provided with finance at 5.5 to 7 per cent interest for short-term loans for agricultural operations. But to the farmers they give at 11 to 14 per cent interest rates. Now, that means the advantage of refinance meant for farmers has been usurped by commercial banks and cooperative banks because they are lending money at higher rates, thus, exploiting the people and, at the same time, making use of refinance. The Reserve Bank and the Government have to explain why they are charging so much. In the name of *Grameen* Banks, Regional Rural Banks were established so that cheap credit could be made available from refinance. In the setting up of the

RRBs, the Central Bank contributed 50 per cent, the State Bank contributed 25 per cent and the commercial banks also contributed 25 per cent. We were surprised to learn that rates charged by Regional Rural Banks were 0.5 per cent higher than that charged by a commercial bank. If you go to a commercial bank, it will charge 11 per cent, but the RRB will charge 11.5 per cent. There is a conspiracy to defeat the very purpose of the Regional Rural Banks. This is a matter, which requires examination. As far as cooperative banks are concerned, the refinance come through cooperative banks; the State cooperative bank keeps for itself 3 to 3.5 per cent without giving any service and without any involvement. And the District Central Banks are left to charge more so that through the cooperatives also, the loans available are at an interest rate of 14 to 19 per cent. Is this the way to treat the farmers? This attitude is as bad as it was in the case of the rural money-lenders. The farmers are being used as a source of extraction of money.

Another thing is the role of the *mandis*. *Mandis* were established to ensure that farmers got remunerative prices for their produce. But the setting up of cartels in *Mandis* -- in league with the Government -- has deprived farmers of this advantage. Moreover, there is a rule that farmers cannot sell their produce outside the district; they must bring their produce to the *Mandi* and sell it there; if they take it outside, they will be fined. The result is that they are forced to sell their produce as per the dictates of the cartels, which pay them much less than even the Minimum Support Price. In the case of rice, when the MSP was Rs.550 per quintal, the price at which they were being forced to sell was Rs.450; Rs.100 went to the intermediary. So, this is the way the *Mandis* have been manipulated. The Finance Minister announced last year that he would try to set up an integrated national market for agriculture so that farmers could sell their produce to the industry directly, or they could sell it anywhere, at remunerative prices. This has not happened. So, *mandis* are another source of exploitation of farmers. You see, the MSPs are the first source of exploitation of the farmers. While calculating MSPs, no profit margin has escaped, as in the case of industry and other things. Moreover, they do not take into account the increase in the cost of living. So, both ways, MSP is the cost price which is even below the cost of production. So, these are some of the handicaps.

Sir, the last point I would like to make is this. However much agricultural production there may be, unless it is sold, unless it is given to the industries for proper use, the farmer cannot get the profit, the return of

3.00 P.M.

his labour. Because of the lack of arrangement for marketing, lack of food processing industries, today we are not able to utilise 150 million metric tonnes of vegetables and fruits. So, while this country is a vegetarian country where we should ensure that adequate supplies of these commodities at reasonable costs are made available to the people, why do they go unutilised? I may point out that if they had followed the model of Dairy Development Corporation, in the same way, they could sell fruits and agricultural produce by organising primary cooperatives in the rural areas and making vegetables and fruits available at the milk depots in the cities and towns at a very reasonable price. This is something they should do. If they cannot do it, then they should involve the Dairy Development Corporation itself to do it with their own experience of milk or set up a separate board for them. The NAFED and APEDA have merely played the role of a commission agent. They have not contributed to the proper marketing. Marketing should also be linked with the food processing industries so that whatever cannot be utilised in the market can be processed and preserved for sale. Then only the farmer can get return for his produce. So, these are some of the suggestions. I think the Ministry would wake up to the problems which the farmers are facing, try to understand the reasons and try to correct them as soon as possible. Otherwise, this situation cannot continue for long. The farmers are in a state of revolt today, I can tell you. If the Government do not listen, then they will face the consequences.

**प्रो. रामबख्श सिंह वर्मा** (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, मैं कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगो के संबंध में अपने कुछ विचारों को व्यक्त कर रहा हूं। अभी मुझसे पूर्व मेरे दो विद्वान वरिष्ठ सहयोगियो ने कृषि के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं एक सीमा तक अपने आपको उनके विचारो से सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, यह देश कृषि प्रधान देश है और मैं समझता हूं कि सभ्यता की शुरुआत से हमारे देश का जो आर्थिक ढांचा है, वह कृषि पर निर्भर रहा है और यही कारण है कि हमने पृथ्वी को माता के स्वरूप में माना है। अथर्ववेद में एक मंत्र आता है -

"माता पृथ्वी, पुत्रो अहम् पृथव्यैः।
नमो मातृ पृथव्यैः नमो मातृ पृथव्यैः।।"

कृषि प्रधान देश होने के कारण ही एक कवि ने कहा है - 'हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नही किन्तु तुमने मिट्टी से किया प्यार'। यह हमारी कृषि संस्कृति है जिसके कारण अपने देश मे जो हमारे मुख्य पर्व हैं जैसे उत्तर भारत की होली हो अथवा दिवाली हो, चाहे

दक्षिण भारत का पोगल हो, चाहे पंजाब की बैशाखी हो, चाहे गुजरात का डांडिया हो और चाहे आसाम का बिहू हो, ये सारे त्यौहार कृषि पर आधारित हैं। जब फसल घर मे आती है तो हम इन त्यौहारो को मनाते हैं। इससे भी यह सिद्ध होता है कि कृषि संस्कृति हमारे जनजीवन मे किस तरह से व्याप्त है। इसलिए शायद बहुत पहले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत गांवो का देश है। भारत को अगर उन्नत होना है तो इस देश के गांवों को उन्नत करना पड़ेगा। जिस समय देश आजाद हआ, आदरणीय कौशिक जी कह रहे थे कि उस समय सकल घरेलू उत्पाद का 60 फीसदी कृषि से होता था। लेकिन जो मैंने पढ़ा है उसके अनुसार शायद 50 प्रतिशत कंट्रीब्यूशन कृषि का था। यह कोई साधारण कंट्रीब्यूशन नहीं था। यह शनै-शनै घटकर 24 फीसदी रह गया है। लेकिन जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय कृषि पर निर्भर रहने वाली आबादी 80 फीसदी थी। अब यह घट कर केवल 67 फीसदी तक पहुंच गई है। जिस तरह से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन घटा है उसी तरह से कृषि पर निर्भरता घटनी चाहिए थी अर्थात उसी तरह से आबादी का 40 फीसदी कृषि पर निर्भर रहना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज देश की 66-67 फीसदी आबादी का हिस्सा कृषि पर निर्भर है। यह भी एक कारण है कि हम विश्व मे एक उन्नत राष्ट्र के रूप मे आगे नहीं पहुंच सके हैं। आदरणीय कौशिक जी ने बिल्कुल सही कहा है कि हमारा 67 फीसदी हिस्सा कृषि पर निर्भर करता है । कई ऐसे देश हैं जहां एक फीसदी हिस्सा कृषि पर निर्भर करता है। कई ऐसे देश हैं जहां दो फीसदी हिस्सा कृषि पर निर्भर करता है। अमरीका में केवल दो फीसदी लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। अगर अमरीका में खेती मे किसी व्यवधान के कारण किसानों की आर्थिक माली हालत खराब होती है तो अमरीका उन्हे सब तरह से सब्सिडी देता है। सुना तो यहां तक गया है कि अगर बाजार में मूल्य गिरने लगे तो अमरीकन सरकार वहां के किसानो से कृषि उत्पादनो को खरीदकर, अगर विश्व में मार्किट कहीं मांग नही है तो उसे समुद्र में फैंक देती है जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहे। जहां तक कृषि उत्पादकता का प्रश्न है, निश्चितरूप से भारत ने काफी तरक्की की है, चाहे फूडग्रेन का प्रश्न हो, चाहे दूसरे सीरियल्स का प्रश्न हो। पल्सेस मे हमारी स्थिति ठीक नही है और वृद्धि ठीक नहीं हुई है। लेकिन राइस के मामले में, व्हीट के मामले में, मक्का के मामले मे, बाजरा के मामले मे, आयल सीड्स के मामले में और तिलहन के मामले में हमारी उत्पादकता बढ़ी है। दलहन के मामले मे हमारी उत्पादकता नहीं बढ़ सकी है। मान्यवर, यह विडम्बना है कि अगर किसान ज्यादा पैदा करता है तो मुसीबत में पड़ता है और अगर कम पैदा करता है तो मुसीबत मे पड़ता है। कर्नाटक के किसानो ने एक बार बहुत टमाटर पैदा किया। उसको कोई खरीदने वाला नहीं मिला और टमाटर सड़कों पर फैंकना पड़ा। वहां के किसानों ने दोबारा मक्का पैदा किया सरकार ने सपोर्ट प्राइस भी घोषित किया।

लेकिन बाद मे सरकार द्वारा कह दिया गया कि गोदामों में जगह नही है । मक्का की खरीद बंद हो गई । इस तरह से कृषि के क्षेत्र में जो माफिया हैं उन्होंने औने-पौने दाम मे मक्का को खरीदा । आंध्र प्रदेश में इसी तरह से एक बार धान बहुत पैदा हुआ । सपोर्ट प्राइज अपनी जगह बनी रही । लेकिन उस धान को कोई खरीदने वाला नहीं था । मजबूरी में किसानो को अपने धान को औने-पौने दाम पर बेचना पड़ा । सरकार की नीति सपोर्ट प्राइज घोषित कर किसानो को उचित मूल्य दिलाने की है । जिन फसलों का समर्थन मूल्य घोषित नहीं हो सकता है, अगर मार्किट में भाव गिर जाए, तब मार्किट इंटरवेंशन के द्वारा किसान को उचित मूल्य मिले, यह भी सरकार समय-समय पर करती रही है । प्रश्न चाहे समर्थन मूल्य का हो, चाहे मार्किटिंग

इंटरवेंशन का मामला हो, देखा यह गया है कि किसानों को अभी तक उचित फायदा नहीं मिला है । उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, मैं समझता हूं कि यह बात उनके संज्ञान में है क्योंकि वे न केवल किसान के बेटे हैं बल्कि किसानों और कृषि से संबंधित उन्होंने तमाम प्रयत्न किए हैं । उन्होंने कृषि से संबंधित तमाम अच्छी घोषणाएं भी की हैं । मैं समझता हूं कि यह उनकी जानकारी में है लेकिन सरकार की मजबूरी क्या है, इसका कारण समझ में नहीं आता है । सपोर्ट प्राइज घोषित कर दिया जाता है लेकिन किसानों के उत्पाद को खरीदा नहीं जाता है । केवल घोषणा करने से किसान को उसका मूल्य नहीं मिलता है । परचेजिंग सैंटर स्थापित नहीं होते । अगर क्रय केंद्र स्थापित होंगे तो उस समय स्थापित होंगे जब किसान अपने उत्पाद को बेच चुका होगा । जब उसका उत्पाद मार्किट में जा चुका होगा । अगर उस समय परचेजिंग सैंटर खोलेंगे तो मैं समझता हूं कि उसका फायदा केवल बिचौलिए को मिलेगा । जहां तक मार्किटिंग इंटरवेंशन की बात है तो मैं एक उदाहरण आपके माध्यम से मंत्री जी के संज्ञान मे ला रहा हूं कि इस साल आलू बहुत पैदा हो रहा है । एक बार आलू कम पैदा हुआ तो यहां हमारे दिल्ली के रहने वाले निवासियों को बीस, पच्चीस और तीस रुपए किलो में आलू उपलब्ध हुआ था । इसका परिणाम यह हुआ कि यहां के लोग नाराज हो गए और उन्होंने सरकार बदल दी । इस साल आलू बहुत पैदा हुआ है । क्या सरकार को जानकारी नहीं थी कि इस साल कितना आलू पैदा होने वाला है ? मण्डियों में उसका भाव गिरकर केवल पचास रुपए, पचपन रुपए प्रति क्विंटल रह गया । मैंने यह मामला पहले भी उठाया था । इसी माननीय राज्य सभा में उठाया था । मैंने सरकार का ध्यान दूसरी तरह से भी उठाया और मालूम हुआ कि सरकार मार्किटिंग इंटरवेंशन के माध्यम से आलू खरीदने वाली है । एक सौ नब्बे रुपये प्रति क्विंटल की दर से एक अप्रैल से खरीदने वाली है । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे जानकारी लेकर हम लोगों को बताएं कि इस तरह से मार्किटिंग इंटरवेंशन के द्वारा अब तक कितना आलू खरीदा गया है ? एक सौ नब्बे रुपए प्रति क्विंटल की दर का भाव तो आज भी कहीं उपलब्ध नहीं है। आज भी किसान सौ रुपए से लेकर सत्तर रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आलू बेचने के लिए विवश है । अगर इंटरवेंशन समय पर नहीं होगा - फरवरी और मार्च में भाव गिर गए थे, अब आपने एक अप्रैल से आलू खरीदने का निश्चय किया है । इस तरह से किसानों की हालत को सुधारा नहीं जा सकता है । मैं समझता हूं कि इसमें कहीं न कहीं परिवर्तन लाना पड़ेगा । चाहे तो सपोर्ट प्राइज के माध्यम से आप किसान को फायदा पहुंचाना चाहते हो, चाहे मार्किटिंग इंटरवेंशन के माध्यम से किसान को फायदा पहुंचाना चाहते हो, आपको इन नीतियों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है । अगर समय पर इंटरवेंशन हो और समय पर किसान का माल खरीदा जाए तभी उसे बिचौलियों से बचाया जा सकेगा नहीं तो उसे बिचौलियों से नहीं बचाया जा सकता है । खेत में जब फसल होती है, खेत में फसल लहलहाती है तो किसान को लगता है कि इस साल हम अपनी बेटी या बहिन के हाथ पीले कर देंगे, अपना नया छप्पर डाल लेंगे । उसे लगता है कि हम बैलों की एक नई जोड़ी खरीद लेंगे या इस वर्ष अपने बच्चे का एडमिशन अगली कक्षा में करा देंगे । लेकिन अगर फसल ज्यादा पैदा हो गई तब भी भाव नही मिलता है और फसल किसी कारण चौपट हो गई तो भी किसान बर्बाद है । कितनी आपदाएं किसान झेलते हैं । कीटनॉशक मिलते नही हैं । फर्टिलाइज़र की कीमतें बढ़ रही हैं और समय पर उपलब्ध नहीं होता है । किसान ने फसल को पैदा किया और कहावत है कि "काले फूल न पाया पानी, धान मरा भरी जवानी" । तीन पानी देने के बाद, जिस समय फ्लावरिंग होती है उस समय अगर धान में पानी नहीं मिलता है तो समझो धान खत्म । अभी उत्तर प्रदेश

की नहरों से पानी नहीं मिला । पानी न मिलने की वजह से गेहूं की एक-तिहाई फसल समाप्त हो गई है । एक-तिहाई उत्पादन कम हो जाएगा । सारा इन्वेस्टमेंट हुआ है, किसान ने रात-दिन मेहनत की है, केवल पानी के अभाव से किसान को फायदा मिलने वाला नहीं है । आज भी हम इन्द्र देवता पर निर्भर हैं । आज भी केवल 36 फीसदी भूमि को हम सिंचाई योग्य भूमि बना सके हैं । वैसे इस देश में पानी का कोई अभाव नहीं है । नदियों का पानी व्यर्थ मे समुद्र मे बह कर चला जाता है । जल संचयन या जल संरक्षण की दिशा में जो कदम उठाए जा रहे हैं, माननीय उपसभाध्यक्ष जी, वे बहुत ही नाकाफी हैं । आपने वॉटरशैड प्रोग्राम चला रखे हैं लेकिन कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं । माननीय कृषि मंत्री जी मैं आपकी मजबूरी समझता हूं । आप तो केवल टैक्नोलोजिकल नो हाउ या फाइनांशियल असिस्टेंस राज्य सरकारों को देते हैं, क्योंकि यह राज्य का विषय है । इसलिए हम आपकी मजबूरी को भी समझते हैं, लेकिन समन्वित प्रयत्न करने की आवश्यकता है । आदरणीय रमा शंकर कौशिक जी की बात से मैं पूर्णत: सहमत हूं कि कई ऐसे विभाग हैं, कई ऐसे मंत्रालय हैं जिनके बीच में प्रोपर कोआर्डिनेशन होना चाहिए जैसे जल संसाधन मंत्रालय है या फूड प्रोसैसिंग मंत्रालय है । मेरा तो अपना यह विचार है कि अगर इस देश को समुन्नत बनाना है, 2020 तक वास्तव में देश को एक उन्नत राष्ट्र बनाना है और अगर हम ज्यादा नहीं कर सकते तो हम दो-तीन प्रयत्न ही कर लें अर्थात् अगर हम किसान को पानी उपलब्ध करा दें, उसकी खेती की सिंचाई के लिए पानी हम समय पर दे दें और

**[उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) पीठासीन हुए]**

मान्यवर, जैसा कि अभी हमारे आदरणीय किदवई साहब कह रहे थे कि इस देश मे नील क्रांति की बड़ी संभावना है, न केवल समुद्र मे, बल्कि तमाम ऐसे प्रदेश हैं जहां पुराने तालाब हैं, जोहड़ हैं, जहां पानी का संचयन किया जा सकता है और फिशरीज को बढ़ावा दिया जा सकता है । जब हम कहते हैं एम्पॉवरमेंट आफ् द विलेजर्ज एंड एम्पॉवरमेंट आफ् द विमेन तो अगर हम केवल दो काम कर दें, अगर हम मत्स्य पालन के लिए उचित वातावरण बना दें और समय पर सहायता दे दें और दूसरे डेयरी के लिए, पशु पालन के लिए अगर हम उचित व्यवस्था कर दें तो न केवल इस देश की महिलाओं का सशक्तिकरण हो जाएगा बल्कि इस देश के किसानों का भी सशक्तिकरण हो जाएगा और गांवो मे रहने वाले लोगो का भी सशक्तिकरण हो जाएगा । जब इस पैसे का ठीक से बंटवारा होगा और जब विषमता कम होगी तभी वास्तव में यह राष्ट्र अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा ।

मान्यवर, यह भी एक विडंबना है कि हमारे देश मे अन्न के भंडार भरे हुए हैं लेकिन फिर भी अन्न की वजह से इस देश मे मौतें होती हैं । मैं समझता हूं कि कृषि मंत्री जी, इसमे आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन इसमें भी समन्वित प्रयत्न करने की आवश्यकता है । माननीय प्रधान मंत्री जी ने इसी सदन मे अपनी चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि इस दिशा में मिल करके कदम उठाने की आवश्यकता है । अन्न भंडारण सुविधा की कमी की वजह से सरकार चाहते हुए भी किसानों से अन्न नहीं खरीद पाती है । देहाती क्षेत्रों मे, गांवों में अन्न भंडारण के लिए गोदाम बनाने की आवश्यकता है । इसके लिए अगर निजी क्षेत्र का भी आप उपयोग करें, गोदाम बनाने के लिए गांवों मे रहने वाले लोगो को अगर आप कम ब्याज पर धन उपलब्ध करा दें तो यह समस्या हल हो सकती है । जहां तक ऋण की बात है, क्रेडिट कॉर्ड की बात है, जो क्रेडिट कार्ड आपने किसानो को दिए इससे बड़ा फायदा हुआ है । इसके लिए मैं सरकार की

सराहना करता हूं और बधाई देता हूं । लेकिन यह क्रेडिट कार्ड देने में बैंकों ने बहुत इसमें हेरा-फेरी की है । बिना रुपये लिए किसानों को क्रेडिट कार्ड नहीं दिए गए । यह मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि कहीं भी बिना रिश्वत के उन्हें क्रेडिट कार्ड नहीं मिले हैं। महोदय, किसानों के हित के लिए जो संपूर्ण फसल बीमा योजना लागू की गयी है, इसका मैं स्वागत करता हूं । लेकिन मैं आप के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इस की यूनिट एरिया की प्रणाली से किसानों का फायदा नहीं हो रहा है । जिस तरह से कोई आम बीमा धारक बीमा में अपना शेयर देता है और बीमा का फायदा उठाता है, उसी तरह से जो किसान अपना शेयर देता है, अपना प्रीमियम अदा करता है और फिर किसी कारण से अगर उस की फसल ओलवृष्टि या कीड़ों के प्रकोप के कारण चौपट हो जाती है तो किसान को उस की भरपाई मिलनी चाहिए । अभी आप ने यूनिट एरिया का आधार एक ब्लाक ले लिया है जिस में ब्लाक में 60 फीसदी नुकसान होने पर उसे फायदा मिलेगा । मान्यवर, इस में तो पूरे एफ ब्लॉक में 10-15 गांव बर्बाद हो जाएंगे और उन को एक पैसा नहीं मिलेगा । इसलिए इस योजना पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है । माननीय कृषि मंत्री जी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं । आप ने बड़ी हिम्मत और बहादुरी के साथ यह घोषणा की है कि किसान पर आय कर नहीं लगना चाहिए । महोदय, किसान और आय कर तो समझने वाली बात ही नहीं है । महोदय, जो गर्मी से जूझे, जो सर्दी और वर्षा से जूझे क्योंकि अगर वर्षा ज्यादा हो जाय तो वह मुश्किल में, अगर सूखा पड़ जाय तो मुश्किल में, अगर कीड़े फसल खा जाएं या जब उस की फसल खलिहान में आ गयी और आग लगने से सारी फसल चौपट हो गयी तो ऐसे किसानों पर इनकम टैक्स लगाने की बात ही बेमानी है । लेकिन जहां काला धन है, जहां लोगों ने काले धन के द्वारा शहरों के किनारे बड़े-बड़े कृषि फार्म स्थापित कर लिए हैं, उन के काले धन पर अंकुश लगाया जाना चाहिए । महोदय, ऐसे लोगों ने अपने काले धन को इनकम टैक्स से बचाने के लिए शहरों के किनारे कृषि फार्म स्थापित कर लिए हैं, उन पर जरूर विचार किया जाना चाहिए ।

महोदय, भारत में किसानो को मिलने वाले सब्सिडी को बढ़ाया जाना चाहिए। महोदय, जो उन्नत राष्ट्र हैं या वर्ल्ड बैंक और आई.एम.एफ. द्वारा अभी इस प्रकार के प्रयत्न किए जा रहे हैं कि भारत के किसानो को दी जाने वाली सब्सिडी कम होनी चाहिए । महोदय, अभी आप ने स्वयं आंकड़े देकर बताया कि विकसित राष्ट्र किस प्रकार से अपने किसानों को सब्सिडी देते हैं और हमारे देश के किसानों को मिलने वाली सब्सिडी के खिलाफ एक प्रकार से विश्वव्यापी वातावरण बनाया जा रहा है जब कि भारत के किसानों को आज भी सब से कम सब्सिडी दी जा रही है । खास बात यह है कि इस सब्सिडी से किसानों को सीधा फायदा नहीं मिल पा रहा है । उस का फायदा बिचौलियों के पास जा रहा है । यह फायदा उर्वरक बनाने वाले कारखाने और गेहूं का निर्यात करने वाले व्यापारियों के हिस्से में ज्यादा जा रहा है । आप ने जो कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किए हैं, वे अभी सभी जिलों में स्थापित नहीं हो पाए हैं । उन का फायदा सभी जिलों के किसानों को नहीं मिल पा रहा है। महोदय, इस सरकार के द्वारा जो एक बड़ा प्रयत्न किया जा रहा है, मैं उस के लिए इस सरकार को बधाई देना चाहूंगा । यह देश की नदियों को जोड़ने की 5 लाख 65 हजार करोड़ रुपए की एक बड़ी महात्वाकांक्षी योजना है । मैं समझता हूं कि ऐसी योजना आज तक भारत सरकार ने अपने हाथ में नहीं ली थी । महोदय, जिस दिन यह योजना साकार होगी, उस दिन न बाढ़ रहेगी और न सूखा रहेगा । उस दिन भारत जल परिवहन के क्षेत्र में भी बड़ी तरक्की करेगा । मैं तो भगवान से कामना करता हूं कि यह योजना जल्दी-से-जल्दी साकार रूप ग्रहण करे ।

मान्यवर, प्रायोरिटी सेक्टर में फाइनेंसियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा ऋण उपलब्ध कराने की जो सरकारी योजना है, उस का पूरा फायदा अभी किसान को नहीं मिला है । उन्हें कैसा लाभ मिला है, यह आदरणीय किदवई साहब बता रहे थे । हमें यह विचार करना होगा कि "नाबार्ड" कितने प्रतिशत ब्याज पर फाइनेंसियल इंस्टीट्यूशंस से धन लेकर उसे किसानों को उपलब्ध कराता है । महोदय, आज एक कार खरीदने वाले व्यक्ति को 10 प्रतिशत ब्याज पर किसी भी फाइनेंसियल इंस्टीट्यूशन से धन उपलब्ध हो जाता है, लेकिन किसान अपनी फसल के लिए जब ऋण लेता है तो उसे 16-17 प्रतिशत ब्याज पर ऋण मिलता है।

यह भी एक मजाक है कि अगर मोटर गाड़ी खरीदी जाए तो उसके ऋण पर 10 फीसदी ब्याज देना होगा और अगर फसल उगाने के लिए ऋण लिया जाए तो उस पर 15 फीसदी ब्याज देना होगा। यह एक विडंबना है, जिस पर सरकार को विचार करना चाहिए। माननीय कृषि मंत्री जी, नाबार्ड द्वारा लिया गया धन और किसानों को उपलब्ध कराया गया धन, इन दोनों का जो इंटरेस्ट है, उसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। इस गेप को कम किया जाना चाहिए।

मान्यवर, कृषि को उपयोगी बनाने के लिए जैविक खादों का अधिकतम इस्तेमाल हो, आर्गेनिक मैन्यूर का अधिकतम इस्तेमाल हो, इस दिशा में प्रयत्न करने की आवश्यकता है। आपने कहा है कि हम कृषि सूचना का एक जाल बिछाएंगे, एक नेटवर्क खड़ा करेंगे, लेकिन अभी तक यह नेटवर्क खड़ा नहीं हुआ है। वास्तव में अगर किसान को समय पर कृषि संबंधी सूचना मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि कृषि के क्षेत्र में एक कायाकल्प हो सकता है और किसानों को काफी फायदा मिल सकता है। आपने कहा है कि हम कृषि को बढ़ावा देने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट स्कीम के तहत जो राज्य सरकारों की 27 योजनाएं हैं उनको समन्वित करेंगे, राज्य सरकारों को कांपलीमेंट करेंगे, सप्लीमेंट करेंगे। मैं जानना चाहूंगा कि वे कौन कौन सी योजनाएं हैं, जिनको समन्वित करके आप राज्य सरकारों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं? यह भी देखने की बात है कि राज्य सरकारों को जो पैसा आप किसानों के लिए उपलब्ध करा रहे हैं, वह पैसा किसानों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है या उस पैसे का कहीं मिसएप्रोप्रिएशन हो रहा है? इस बारे में भी मैं आपसे जानकारी चाहूंगा।

मान्यवर, एक फाउंडेशन है, जिसका नाम है मोरारका फाउंडेशन । इस मोरारका फाउंडेशन ने राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में एक एक्सपेरीमेंट किया है कि जो लोग अपनी खेती में जैविक खादों का इस्तेमाल करेंगे अर्थात खेती में केचुआ डालकर क्योंकि केचुआ खाद बनाने का काम करता है, जो डाइकोट्स हैं, जैसे दलहन है, उनकी जड़ों में बैक्टेरिया होते हैं और जो नाइट्रोजन के फिक्सेशन का काम करते हैं, इस तरह से जैविक खादों का उत्पादन होता है और जैविक खादों से उत्पादित जो कृषि उत्पाद होंगे, मार्केट में उस उत्पाद की जो कीमत होगी उससे बीस फीसदी ज्यादा पर वह क्रय करेंगे। क्या भारत सरकार इस तरह की कोई योजना बना रही है? इसको वृहत रूप में लागू करने पर कोई विचार कर रही है? ताकि किसान जैविक खादों का इस्तेमाल करे या केवल आर्गेनिक मैन्यूर का उपयोग करे क्योंकि रसायनिक खादों के बढ़ते उपयोग के कारण, कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग के कारण भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वह घटी है, कम हुई है, इससे उत्पादकता घट रही है। इस ओर सरकार ध्यान देगी ताकि जो फूडग्रेन्स की क्वालिटी है, कृषि-उत्पादों की क्वालिटी है, वह क्वालिटी मेण्टेन रहे, कृषि

उत्पादकता भी बनी रहे, फर्टिलिटि भी बनी रहे और जो उत्पाद हो उसकी क्वालिटी अच्छी हो, किसानो को उसका उचित मूल्य मिले।

**(उपसभापति पीठासीन हुईं )**

उपसभापति महोदया, मैंने सुना है कि मध्य प्रदेश मे कुछ ऐसे लोग हैं, जो केवल आर्गेनिक मैन्यूर का इस्तेमाल करते हैं और जो मार्केट मे उस कृषि उत्पाद का मूल्य है उससे ठीक दुगुनी कीमत उन्हे प्राप्त होती है। अगर हम इसके लिए व्यापक जानकारी पूरे देश को दे सके, इसके लिए जो परचेजिग सेटर हैं, जो क्रय केन्द्र हैं, उनकी स्थापना कर सके, और इस तरह की जानकारी का एक संजाल फैला सके, एक नेटवर्क स्थापित कर सके तो मेरा ख्याल है कि जो कैमिकल फर्टिलाइजर हैं या पेस्टीसाइड्स हैं उनसे किसान मुक्त होगा और जो वह माल उत्पादित करेगा उसे उसके माल की बाजार में अच्छी कीमत भी मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि कृषि मंत्रालय इस पर विचार करे और इस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करे।

महोदया, वास्तव मे किसान हम सबका अन्नदाता है। किसान जो है, इसका सबसे ज्यादा एक्सप्लायटेशन होता है, सबसे ज्यादा शोषण होता है क्योंकि किसान इग्नोरेंट है, उसे पूरी जानकारी नही है। वह सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक एक चक्रवात मे फंसा रहता है। एक तो उसे अखबार नही मिलता, अगर मिल भी जाय तो उसके पास पढ़ने का समय नहीं होता, टेलीविजन भी देखने का समय नहीं होता। सुबह से लेकर शाम तक अर्थात हर समय उसे काम करना पड़ता है। उसकी हालत बहुत खराब है।

इस संबंध मे मैथिली शरण गुप्त ने किसानों की दशा का वर्णन किया है। मैं उनकी एक कविता को उद्धृत करना चाहता हूं। माननीय कृषि मंत्री जी क्योकि किसान के बेटे हैं, स्वयं भी किसान हैं, भले ही वे कम्प्यूटर इंजीनियर हो, लेकिन वे किसानों की पीड़ा को समझते हैं। इसलिए मैं यह कविता उनके सामने कहना चाहता हूं कि क्या हालत है किसानों की, क्या हालत थी किसानों की और अभी भी उस हालत मे कोई विशेष परिवर्तन आने वाला नहीं है। बहुत पहले मैथिली शरण गुप्त ने कहा था :-

बरसा रहा है रवि अनल, भूतल तबाह सा जल रहा
है चल रहा सन-सन पवन, तन पर पसीना ढल रहा
तो भी कृषक निज खेत पर हल तथापि चला रहे
किस लोभ से, इस आंच में भी निज शरीर जला रहे।
मध्याह्न उनकी स्त्रियां ले रोटियां पहुंची वहीं
हैं रोटियां रूखी, खबर है शाक की उनको नही
संतोष से खाकर उन्हे वह काम मे फिर लग गए
भरपेट भोजन पा गए तो भाग्य मानो जग गए।

घनघोर वर्षा हो रही है, गगन गर्जन कर रहा
घर से निकलने को कड़ककर वज्र वर्जन कर रहा
तो भी कृषक निज खेत पर करते निरंतर काम हैं
किस लोभ से वे आज तक लेते नही विश्राम हैं।
घर से निकलना मौत है, आंधी-अंधेरी रात है
हा शीत कैसा पड़ रहा, है थरथराता गात है
तो भी कृषक ईंधन जलाकर खेत पर हैं जागते
यह लाभ कैसा, है न जिसका लोभ अब तक त्यागते।

महोदया, यह दशा किसान की रही है, यह दशा आज भी है। माननीय कृषि मंत्री जी, आप इस दशा में अवश्य सुधार करेंगे। मैं समझता हूं कि आपके हाथ बहुत बंधे हुए हैं। बहुत कुछ राज्य सरकारों पर भी निर्भर है लेकिन आप समन्वय बिठाने की कोशिश करेंगे, राज्य सरकारों को भी कांफिडेंस में लेंगे और अन्य जो विभाग हैं, चाहे फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्री से संबंधित विभाग हो, चाहे जल संसाधन मंत्रालय का विभाग हो या जो भी अन्य संबंधित विभाग हैं, उन सबके साथ मिल-जुलकर ऐसी योजनाएं बनाएंगे क्योंकि अगर इस देश को समुन्नत राष्ट्र बनना है, अगर 2020 तक हमें संसार के सामने इस राष्ट्र को आत्मनिर्भर होकर सम्मान के साथ खड़ा करना है तो फिर और कोई दूसरा अन्य तरीका नही है। किसान को मजबूत बनाना पड़ेगा, गांव को उठाना पड़ेगा और इसके लिए इस देश में पोटेंशियल की कोई कमी नही है। इससे ज्यादा उर्वरक जमीन और कहीं नही है, जल संसाधन की कमी नही है, केवल जल प्रबंधन की कमी है। क्योंकि आपके पास एक कल्पना है, क्षमता है, शक्ति है और मैंने आपके साथ रहकर काम किया है इसलिए मैं जानता हूं और इसीलिए मैं आपसे जरूर आग्रह करूंगा कि एक समन्वय बिठाकर किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की आप निश्चित रूप से योजना बनाएं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। उपसभापति महोदया, मुझे समय दिया गया अपनी बात रखने का उसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं।

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY (Andhra Pradesh): Thank you, Madam. As the discussion on the working of the Ministry of Agriculture is taking place in this august House, about 14 States are reeling under severe drought including my own State Andhra Pradesh. The farmers are in real distress and they are looking at the Government for a helping hand. We are aware that agriculture is one sector that is contributing a lot towards employment opportunities and GSDP. Looking at the budgetary allocations, they are very meagre and inadequate to meet the demands of the farmers. Madam, public investment and private investment in agriculture are coming down year after year. When we look at the income ratio of the agriculture and non-agriculture sectors, during 1960, it was 1:2; now, according to the latest figures available, it is 1:6. The purchasing capacity

of the farming community is going down year after year. Even if you have a lot of industrial products, there should be somebody to buy them. Only then, the demand will sustain. Madam, as we hear the speeches of Members of all the political parties, cutting across party lines, everybody supports the cause of the farmers. But what is the outcome? Going by the records in this august House and various Assemblies in the country, every political party, on the floor of the House, supports farmers but when coming to the allocation, they are not only inadequate but very, very low compared to the other sectors. Madam, credit for the agriculture sector, for agriculture and allied industries, is meagre, that is, 11 per cent. Even for the loans that are taken by the farmers during this drought period, the Government of India has announced interest waiver. But, in actual terms, it is only 20 per cent they are giving interest waiver. I want that the hon. Minister should come out with a clear statement as to what exactly is the percentage of waiver of interest during this year. The private money-lenders are minting money exploiting the innocent and poor farmers of our country. For purchase of seeds, fertilizers, pesticides, etc., farmers are inevitably going to the private money-lenders and facing all the trouble. We have seen a statement of the hon. Minister, who was kind enough to visit our State, Andhra Pradesh, recently. I was rather surprised and thrilled to read the statement of the hon. Minister that if a person wants to buy a car, he is in demand and all the manufacturers and showroom people will be after him, but when a farmer wants a loan, nobody is coming forward. This was the crux of his statement made at Guntur in Andhra Pradesh during last week. I request the hon. Minister to come out wholeheartedly and support the farming community as we are aware of the problems faced by the farmers in our country. The Seed Act amendment proposal is still pending with the Government of India. Andhra Pradesh Government made a request to the Government of India to come forward with the amendment of the Seed Act whereby we have requested for strengthening the penal provision. Since we have Fertilizer Control Orders, we request the Government to look at the Bio Fertilizer Control Orders. With respect to WTO, we have not prepared the nation at all. When our Government signed the WTO agreement, the nation was totally not prepared. The people are unaware of the consequences of WTO and the unequal fight which they are going to face in the coming years since our farmers are not only economically weak but educationally they are far behind the farmers of the developed countries. Hence, the Government of India should have a campaign with regard to the quality consciousness through Doordarshan and AIR. Using whatever media

and whatever facilities are available with the Government, they should enlighten the farmers; they should enlighten the people of this country, as to the quality of the food products and competitiveness all over the world.

Another aspect is that excise duty on tractors should go. The hon. Minister was earlier kind enough to declare openly that that should be done. But as far as the farming community is concerned, they are still looking at the Government for the waiver of excise duty on tractors. Taxes are being imposed on the material for drip and sprinkler irrigation. I would request the Government to look into this aspect and waive excise duty and other taxes as far as drip irrigation and sprinkler irrigation are concerned.

Coming to export subsidy, there is a term called 'Blue Box Subsidy'. These Blue Box subsidies should be reduced in the developed countries. We should force the other countries, which are developed countries, to reduce the export subsidies, and encourage our farmers by giving more export subsidies in our country. As for standards, by virtue of WTO, there is something called Sanitary and Phyto-Sanitary Standards. The Indian farmers are in a disadvantageous position. Indian farmers are poor both in economic and educational standards. That should be taken care of. We are also very poor in water and soil management; more particularly, we are very, very poor in post-harvest management. I would request the hon. Minister to look at the post -harvest management proposals which are pending with the Government. Since we are still importing oils and pulses, we should make our farmers divert their cropping pattern, change their cropping pattern, so as to grow more pulses.

Another important aspect is power. We require water and power for agriculture. Since in our country, there are many different political parties at the helm of affairs in various States, every State has got its own power policy. I would request the Government to prevail over the other Governments to see to it that there is a National Power Tariff Policy, at least, for agriculture. I would also request the hon. Minister to advise his colleagues in the Irrigation Department to help the State Governments in going for a massive de-silting programme of small and medium tanks so as to store more water during the rainy season.

Another interesting aspect that the Government is contemplating is interlinking of rivers. It is a welcome gesture. One should feel happy that at

least now, after 50 years of Independence, they are thinking of interlinking the rivers. It is a welcome gesture on the part of the Government. The other aspect is crop insurance. It is compulsory for the loaned farmers and optional for non-loaned farmers. My request to the Government is to see to it that crop insurance is made compulsory for all the farmers. The Gram Panchayat should be taken as the unit and every farmer should be covered, with a view to giving subsidy and a helping hand to the small and marginal farmers as far as insurance premium is concerned. The Government should also sanction more funds for the proposed macro management mode of agriculture. I would request the Government to take steps to envisage a second Green Revolution to feed the growing population so as to double the farm productivity. Finally, the suggestions of the International Rice Research Institute (IRRI) should be carefully observed and implemented. With these words, I compliment the hon. Minister for his bold statement as far as the cause of the farmers in our country is concerned.

SHRI MATILAL SARKAR (Tripura) : Respected Deputy Chairperson, while speaking on the working of the Ministry of Agriculture, I cannot but indicate the aim of the agricultural policy of the NDA Government, though the presentation has been an intelligent focus on the outward show of the Budget to tactfully hide the goal, so that the people cannot instantly realise the intention of the Government.

Even then, the actual effects of the agriculture policy have come to light. The agriculture policy cannot depart from the aims and objectives of the policy of the Government at the Centre, pursued universally in all spheres. So, as it is natural, the agriculture policy suffers from the economic aggression unleashed by the imperialist forces in the name of trade and commerce, under the policy of LPG (liberalisation, privatisation and globalisation) in disguise, and the policy has been tightly caught by the clamps of IMF, World Bank and WTO, the three witching hands of the imperialist forces.

We have seen the Annual Report in agriculture for the year 2002-03. However colourful and articulated the presentation may be, whatever attempts have been made to conceal the ugly picture of the pro-WTO nature of the Budget, the offensive smell of the rotten structure is now striking our noses. The Government at the Centre cannot deny these resultant effects of the LPG-oriented policy. Can the hon. Minister disagree

with the growth rates achieved in the agricultural products in the last three successive Five Year Plans? In the Seventh Plan, the growth rate was 3.7 per cent; in the Eighth Plan, it was 3.9 per cent. In the Ninth Plan, a miserable decline of 0.2 per cent was there.

Floods and droughts are the happy visitors over our country. We see that due to the severe drought in the year 2002-03, the shortfall in the areas for paddy was 57 lakh hectares. In respect of pulses, the shortfall was 17 lakh hectares. In respect of oilseeds, it was 9 lakh hectares. What remedial measures have been taken by the Government to compensate these drought-affected people? It was estimated, if I am not wrong, that the relief requirement would amount to Rs.35,000 crores. But the assistance that had been provided in reality was not even ten per cent of the total requirement. How will these farmers survive?

Coming to the land policy of the Government, wherever the land reforms are required, we see that the NDA Government is pursuing the land reversal policy. We see that the multi-national corporations are occupying a large piece of land under the auspices of the different State Governments. This is the result of the policy followed by the NDA Government. What happens to the tribal people, who are living in the hilly areas, generation after generation? After 55 years of Independence, they do not get even the land-record documents, and now in the name of environment, they are threatened eviction! If the Forest Act is not modified, is not amended, thousands of tribal people will be evicted.

In our country, there are as many as 8 crore of tribal people living in the hilly areas. Coming to the context of the agricultural exports, we see that the export in agricultural produce in 1996 was valued at US $ 6.83 billion and in 1999, it was valued at US $ 5.67 billion. That is, within three years, there is a decline of 16 per cent in export value. The trend is still going on steadily and the main reason for this is the massive import liberalisation. What does this liberalisation speak of? The exporting countries give subsidies to their commodities. Japan gives subsidy to the extent of 72.5 per cent, Columbia gives 54 per cent, South Korea gives 61 per cent, China gives 34 per cent and USA gives 29 per cent. This is the case with other countries also. As far as India is concerned, it is only 3 per cent. As they give subsidies to their commodities, the prices of the commodities fall. Our Government is either lifting or reducing import tariffs. That is why the commodities like skimmed milk powder, edible oil, sugar, tea, coffee, coconut, silk, cotton,

etc. are flooding the Indian markets. The products of our peasantry cannot compete with these imported goods. They have to face a very tough and unequal competition. Due to the Government's lifting of the quantitative restrictions on import of agricultural products and its refusal to impose adequate import tariffs, highly subsidised imported commodities are now flooding into the Indian markets. Coming to the context of the fair price shops, which is one of the important things for our food production, we see that the Government have raised the issue price for APL families by 65 per cent for wheat and 61 per cent for rice. Not only this, the issue prices have been raised for the BPL families also. For wheat, it was 66 per cent and for rice, it was 62 per cent. So, on one side, there is heavy stock in the Government godowns; on the other, poor people are destined to starvation. This is the picture from two sides. It is because of the policy of the Government that the patent laws have been amended. Now, seed markets are going into the hands of the multi-national corporations. Fertilizer units are shutting down. The fertilizer units at Durgapur in West Bengal, Barauni in Bihar and Sindhri in Jharkhand are closing down. These fields are being captured by the multi-national corporations. So, the Government should come up with adequate assistance for giving subsidies to our farmers.

The subsidies should be in the form of increased irrigation facilities, increased technological help, etc. Though agriculture is expected to provide jobs for a large number of people in the rural areas, we see that there is a failure in this regard also. The percentage of landless agricultural labourers was like this. In 1981, it was 24.94 per cent of the rural population; in 1999, it was 26.5 per cent of the rural population; and in 2001, it was 30 per cent of the rural population. So, the percentage of landless agricultural labourers is increasing.

So far as providing jobs to the rural people is concerned, in the eighties, the average mandays was 123 and, in the 'nineties, it was 78. (*Time bell*).... Madam, I am the only speaker from my party.

THE DEPUTY CHAIRMAN: That is not the point. The point is that I have to keep the time and your party's time is over. So, you have to conclude now.

SHRI MATILAL SARKAR: Another big area in agriculture is horticulture. Madam, how many minutes were allotted to our party? I am the only speaker. I think we have got 15 minutes.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Your party has been allotted 11 minutes and you have spoken for 12 minutes.

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal) : Sometimes, your indulgence is sought, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, you have taken 13 minutes.

SHRI NILOTPAL BASU: Madam, you show some indulgence.

SHRI MATILAL SARKAR: Our country is a big country. In some parts of the country there is abundant rainfall and in some other parts of the country there is drought. The eastern zone of our country, particularly, the North-East, receives heavy rainfall. But this rainwater drains out. The water catchment programmes are very limited. The watershed management programme is not given due attention. So, the rainwater is draining out.

SHRI JIBON ROY (West Bengal) : The Minister is not listening.

THE DEPUTY CHAIRMAN: He is here.

SHRI JIBON ROY: He is talking.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You don't listen through your mouth. You listen through your ears. He has not closed his ears.

SHRI MATILAL SARKAR: We are proud that our cultivators have secured the second position in the world in respect of vegetable production. We are a large vegetable-growing country. We are second to China. China stands first in the world. In the North-East, there is heavy rainfall. If you conserve the rainwater, you can utilise it for agriculture, for growing vegetables, potatoes, pineapples and horticulture. Pineapples grow in abundance in this area. In Tripura, pineapple is called "the Queen of Tripura". It is grown there in plenty. The NARAMAAC, a Government of India undertaking, has set up a project in Tripura. Their target was 82,000 metric tons. Now, we understand that the NARAMAAC is trying to withdraw

from Tripura. I urge upon the Government of India and the Minister of Agriculture to see to it that it should not happen.

More and more cold storages are required where vegetables are grown in plenty. In our State, there are 8 cold storages. But these facilities are not utilised. The situation is the same in other States also. In our country, every State produces, at least, one product in plenty.

Somewhere there the soil suits rice and somewhere it suits potatoes or sugar, but keen attention is not given to the respective vegetables and foodgrains.

To conclude, I would like to point out one important thing to the hon. Minister. We have seen so many agricultural revolts in our country. A few years back, the onion growers came to a point of revolt. Some years ago, the sugarcane growers also came to a point of revolt because if their urges, wants or demands are not considered, they will not be silent. Cultivators, farmers, peasantry are reeling all over the country. They are fighting militantly against the onslaughts of WTO, against the onslaughts of LPG. If the farmers are on the move and the Government fails to understand the significance of their movement, then it will be a blunder on its part. I invite the attention of the hon. Minister to these aspects and say that the policy should be revised.

We are going high in technology. It is good because if we prosper in science and technology; if we invite our scientists to come in the picture to make researches, definitely, it will be to our help. But, at the same time, orientation among the lakhs and crores of peasants is required. If we advance in one side in terms of technology only and do not look to the ground realities as to where our farmers stand; what is the condition of our peasantry; are they having land, are they having credit, whether the banks are providing loans; whether the cultivators are getting financial benefits and other related issues, the advancement will not be of much help. National Horticulture Board provides loans to the private bodies only. They do not provide loans to the State Governments. If loans are provided to the private bodies, those private bodies will not go to the north-east because there is transportation problem. Infrastructural drawbacks are there. How the

4.00 P.M.

progress will be made there? The case is so for other parts of the country also.

So, all these things are to be looked into. The Government has to revise the policy. They are to withdraw from the wrong policy of serving the multi-nationals and the imperialist forces. The Government should turn away from these forces and must see that our peasants, our farmers are not detached from the land and the agricultural production.

**श्री सुरेश पचौरी** (मध्य प्रदेश) : उपसभापति महोदया, इससे पहले कि मैं कृषि मंत्रालय की चर्चा पर विस्तार से अपनी बात कहूं, वर्तमान सरकार के कृषि मंत्री और कृषि राज्य मंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान जो वक्तव्य दिए हैं, मैं वहां से अपनी बात आरंभ करना चाहता हूं। माननीय कृषि मंत्री जी ने मौजूदा कृषि संबंधी नीतियों के बारे मे एक वक्तव्य दिया है। यह दैनिक जागरण मे 16 अप्रैल, 2003 को छपा था। कृषि संबंधी नीतियों के बारे मे जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या खोट नजर आता है तो उन्होंने उत्तर देते समय कहा था कि खोट यही है कि नीतियां बनाते वक्त केंद्र मे किसान नही होता बल्कि वह वर्ग रहता है जिसकी लॉबिंग मजबूत है।

आगे वह कहते हैं कि जिसकी जितनी लॉबिंग मजबूत होगी उसको उतनी ही हिस्सेदारी मिलेगी । उससे आगे कहते हैं, सरकार गेहूं के निर्यात पर भी तो हजारो करोड़ रुपये की सबसिडी दे रही है, यही किसानो को दूसरी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए क्यों नही देती है। यह मानसिक स्थिति हमारे देश के आदरणीय कृषि मंत्री जी की है। ...(**व्यवधान**)... अब बात आती है कि कृषि राज्य मंत्री जी की क्या मानसिक स्थिति है। कृषि राज्य मंत्री जी, हिन्दुस्तान समाचार में 5 मार्च, 2003 को छपा है, उसमे हुक्मदेव कहते हैं कि बजट मे किसानों को कोई राहत नही । हुक्मदेव जी आगे कहते हैं कि इस बजट ने किसानो को दुविधा मे डाल दिया है । किसानों को तो दुविधा में डाल दिया लेकिन ये दोनों मंत्री सुविधा मे रहते हुए मंत्रिमण्डल मे आज भी बरकरार हैं और दूसरी तरफ हम कृषि मंत्रालय पर चर्चा कर रहे हैं । कैसे इनसे आशा और अपेक्षा की जाए कि जो खुद दोष इनको नजर आ रहा उसमे ये कोई सुधार कर पायेंगे? यह बहुत गंभीर विषय है । महोदया, प्रश्न इस बात का है कि जब ...(**व्यवधान**)... कुछ कहना चाह रहे हैं अजित सिंह जी, मैं मानता हूं अब आप अजित सिंह जी नही रहे, अब आप असहाय सिंह हो गए हैं । मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूं । महोदया, सीमा पर जब जवान और खेत पर जब किसान के चेहरे पर चिंता की लकीर हो जाती है तो यह मान कर चलना चाहिए कि देश के सामने भयंकर चुनौती आ गई है । आज स्थिति यह है कि आधुनिकता की जो आंधी है, पारंपरिक तालाब, कुएं आदि को लील चुकी है । जो पुराना एक सिस्टम था, पूर्वजों या पुरखो का दिया हुआ कि जब जल संचय करने की बात होती थी तो गांव मे बावड़ी बनाई जाती थी, तालाब बनाए जाते थे, टैंक बनाए जाते थे, कुएं खोदे जाते थे और जल संचय किया जाता था । मैं पूर्व वक्ताओ की बातों की पुनरावृत्ति नही करना चाहूंगा । लेकिन जब जल संचय की बात को लेकर हम चलते हैं तो यह माना जाना चाहिए कि आखिर उसमे क्या

खोट है । कृषि से संबंधित जो लघु-मध्यम परियोजनाएं हैं, आज उनकी यह स्थिति है कि वे बजट के अभाव मे लटकी हुई हैं । कृषि क्षेत्र में स्थिति यह है, जो स्वयं माननीय मंत्री जी ने स्वीकारा है कि योजना आयोग से पर्याप्त पैसा नही मिल पा रहा है । लगभग 25 हजार करोड़ रुपये इन्होने मांगे थे और 13 हजार करोड़ रुपये ही मिले हैं । स्थिति यह है । इस सरकार द्वारा जो प्रस्तुत इकोनोमिक सर्वे है उसमें जो कृषि उत्पादन है उस कृषि उत्पादन तक का शॉर्टफाल हुआ है । वह 212 मिलियन टन से घट कर 183.6 मिलियन टन हो गया है । यह स्थिति 1996-97 के बाद हमारे देश मे इस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के मामले में कभी नहीं हुई । आयल सीड्ज़ का जो उत्पादन है वह 20.6 मिलियन टन से घट कर 15.4 मिलियन टन हो गया है । शूगरकेन प्रोडक्शन की बात है तो वह 300.2 मिलियन टन से घट कर 285.4 मिलियन टन हो गया है । यही स्थिति चावल और गेहूं की है । 93.1 मिलियन टन से घट कर 77.1 मिलियन टन राइस की स्थिति हो गई है और गेहूं की स्थिति यह है कि 71.8 मिलियन टन से घट कर इसका उत्पादन 68.9 मिलियन टन रह गया है । तो सवाल यह है कि हम किस क्षेत्र में तरक्की कर रहे हैं ? एक्सपोर्ट के क्षेत्र की बात यह है कि देश में जिन चीजों का उत्पादन हो रहा है उनका एक्सपोर्ट बुला रहे हैं । यह स्थिति है । दूसरी स्थिति यह है, बजट में जो निश्चित रूप से आपसे संबंधित नहीं है कि डीज़ल के दामो में वृद्धि होती जा रही है, खाद के दामों में वृद्धि होती जा रही है, कृषि में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वह 18 प्रतिशत से घट कर 9 प्रतिशत हो गया है । यह स्थिति है । कृषि विकास दर 1.3 प्रतिशत रह गई है, जबकि लक्ष्य 4.5 प्रतिशत था । ये सारी स्थितियां हैं । मैं सोचता हूं कि यह स्थिति इसलिए है कि किसानों के लिए जो नीति निर्धारक थे वे ऐसे हैं जिनको किसानों के दर्द और समस्याओं का न तो आभास है, न ज्ञान है और न उस दर्द का एहसास करने वाले लोग हैं । दर्द का जिक्र करने वाले लोग तो हैं, लेकिन उस पीड़ा को दूर करने वाले लोग जब संबंधित स्थानों पर न बैठें... ।

तो यह देश के किसानो के लिए असहाय स्थिति हो जाती है । महोदया, हम एक तरफ कहते हैं देश के 75 प्रतिशत से अधिक किसान गरीब हैं तो जब इन 75 प्रतिशत से अधिक किसानो के चेहरे पर चिंता की लकीरे होंगी, जब वे खुशहाल नहीं होंगे तो देश कैसे खुशहाल रह सकता है, इस बात की कल्पना हम स्वयं कर सकते हैं । महोदया, आज स्थिति यह है कि एक तरफ तो विलासिता की वस्तुएं खरीदने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध हो रहा है, लेकिन जब किसान अपने लिए ट्रेक्टर खरीद रहा है, कृषि उपकरण खरीद रहा है तो उसके लिए ऋण पर ब्याज की दर, विलासिता की वस्तुओं जैसे कि कार आदि से, बहुत ज्यादा है । इसी कारण आज भारत का किसान निराश और हताश हो गया है । वह व्यापारियों के शोषण का शिकार हो गया है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी मे कहीं किसी प्रकार की कंजूसी नही की जानी चाहिए । जब हम से अधिक विकसित देशों मे किसानो को ज्यादा सब्सिडी दी जाती है तो हमारे देश में भी उस मे कोताही नही बरती जानी चाहिए । यह इसलिए और भी जरूरी है क्योंकि हमारे देश का किसान प्रकृति पर आश्रित है । हमारे किसान को सूखे और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप हमेशा झेलना पड़ता है । महोदया, जहां एक ओर सूखे और बाढ़ जैसे दैवी प्राकृतिक प्रकोप से किसान को राहत नही मिल रही है, दूसरी ओर बजट ऐसा प्रस्तुत किया गया है जिस कारण इस मानव निर्मित आपदा से भी किसानो की स्थिति बहुत दयनीय कर दी गयी है । यह हमारे लिए अत्यंत ही चिंताजनक बात है ।

महोदया, मै अपनी बात समाप्त करने से पहले 3-4 बातें कहना चाहूंगा कि जहां आज देश मे "रेन वाटर हार्वेस्टिंग" की जरूरत है, वहीं "ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइटेशन" को भी रोकने की बहुत जरूरत है । इसके लिए देश की तमाम नदियो के पानी के समुचित उपयोग के बारे मे भी गंभीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत है । महोदया, हमारे देश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जहां एक क्षेत्र में पानी अपार मात्रा में है, दूसरे क्षेत्र में अत्यंत कम मात्रा मे है । तो ऐसी योजनाएं बनाने की आवश्यकता है कि जहां विपुल मात्रा मे जल उपलब्ध है और जहां कम उपलब्ध है - उन में समानता लाने की जरूरत है ताकि सभी लोग देश मे उपलब्ध जल का उपयोग कर सकें । आज देश का किसान जो दैवी प्रकोप पर आश्रित है, उस के लिए ऐसी योजनाएं बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि वह मानसून पर आश्रित न हो बल्कि उसके लिए जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओ ने कहा, आधुनिक टैक्नॉलोजी उपलब्ध कराने की ओर ध्यान देने की जरूरत है। महोदया, जब हम किसानो की बेहतर हालत की बात करते हैं तो बायो-टैक्नॉलोजी के डवलपमेंट की बात भी होनी चाहिए । किसान मानसून की स्थिति के आधार पर ऐसी फसल उगाए जिससे कि उस की फसल का नुकसान न हो, जैसे अगर सूखा पड़ने की संभावना है तो उस क्षेत्र के किसानो को कौन सी फसल उगानी है यह जानकारी उन्हें देना बहुत जरूरी है । महोदया, मैं मध्य प्रदेश से आता हूं जो कि सोयाबीन बाहुल्य क्षेत्र है और मैं उस भोपाल संभाग से आता हूं जहां कि ज्यादातर सोयाबीन की फसल होती है, लेकिन किसान को यदि बताया जाए कि सोयाबीन पैदा करना ठीक नही रहेगा क्योंकि सूखा पड़ने वाला है बल्कि अमुक फसल पैदा करना उचित होगा तो वहां का किसान उस प्रकार की विपदा का शिकार नही होगा । आज स्थिति यह है कि ऐसा न होने से इस देश का अन्नदाता आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है । वह व्यापारियो और बिचौलियो के चंगुल मे फंस चुका है । साथ ही वह सरकारी उपेक्षा का भी शिकार हो रहा है जो कि निश्चित रूप से उस की गंभीर स्थिति की ओर संकेत करता है । इसलिए हमे विचार करना होगा कि जब हमारे देश के 76 प्रतिशत लोग खुशहाल नही होंगे तो देश खुशहाल नहीं हो सकता है क्योंकि ये 76 प्रतिशत वे लोग हैं जो कि कृषि पर आधारित हैं । इसलिए आज हमें देश के किसान को आत्म-निर्भर करना होगा और जब भारत का किसान आत्म-निर्भर होगा तो भारत देश आत्म-निर्भर होगा, मैं ऐसा मानता हूं । इस के लिए जरूरी है कि किसान को उस की पैदावार का उचित मूल्य मिले, इस के लिए जरूरी है कि किसान के हित के लिए ऐसी नीति निर्मित की जाए जिससे किसान अपने आपको असहाय न महसूस न करे ।

किसान को जिन खास दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनमें सिंचाई के साथ-साथ बिजली भी है। बिजली की स्थिति यह है कि किसान को 24 घंटे मे केवल दो या तीन घंटे ही बिजली मिल पाती है। इसलिए, महोदया, इस पर भी विचार करने की जरूरत है।

महोदया, राजीव गांधी जी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में तिलहन उत्पादों के संवर्धन के लिए एक टैक्नोलोजी मिशन बनाकर एक क्रांतिकारी कदम उठाया था और जिससे देश मे तिलहन का उत्पादन लगभग 75 प्रतिशत बढ़ गया था, लेकिन आज की केन्द्र की सरकार, यह जो एनडीए की सरकार है, जो एनडीए की सरकार न होकर केवि सरकार हो गई है यानि किसान विरोधी सरकार, इनका ध्यान तिलहन के उत्पादन की ओर नही जा रहा और इससे देश में तिलहन का उत्पादन काफी कुछ कम होता जा रहा है। देश मे प्रति व्यक्ति जो कृषि भूमि की उपलब्धता है वह भी कम होती जा रही है। इसलिए जरूरी है कि हमारे देश मे जो किसान की बदतर स्थिति दिन-प्रति-दिन होती जा रही है, उसके बारे मे हम लोग गंभीरता से विचार करे।

महोदया, किसान जहां एक ओर जैविक प्रोद्यौगिकी का इस्तेमाल करे, बायो-टैक्नोलोजी का इस्तेमाल करे, एडवांस टैक्नोलोजी का इस्तेमाल करे वहीं जो हमारे पुरखो की दी हुई चीजे हैं, जो टैक्नोलोजी है उसका भी इस्तेमाल करे। मैं यह मानकर चलता हूँ कि इन सब बातो को जब गंभीरता से लिया जाएगा तो किसान भी आत्मनिर्भर होगा और हमारा देश भी आत्मनिर्भर होगा। धन्यवाद।

†SHRI R. KAMARAJ (Tamil Nadu): Madam, Deputy Chairperson, on behalf of AIADMK, I rise to put forth my views on the working of the Ministry of Agriculture. To put the plight of agriculture in the country in a nutshell, we can say, "operation successful but the patient died", This is the plight of agriculture today. Agriculture is thriving but the farmers are becoming poorer. We have attained self-sufficiency in the production of foodgrain, milk and sugarcane. We have also registered surplus in the production of some crops. Yet even, it is a fact that there was stagnancy in agricultural growth during the Ninth Plan period. I will come to the reasons for this little later. There is no denying the fact that repeated failure of monsoon affected the farmers adversely.

The Government has been asserting that agricultural schemes are devised on the basis of the National Agricultural policy. But I wish to point out as to how some of the policies of the Centre have affected the farmers. An American Company known as Monsanto Corporation introduced Bt Cotton variety in our country. The Centre also approved this. It was said that this variety of cotton is pest-resistant and would yield more. Farmers bought seeds of this Bt Cotton paying exorbitant price and sowed it. But, the unfortunate farmers have suffered huge loss because of crop failure. Had the Agriculture Ministry approved this variety of cotton after enough tests and deliberations, our farmers would not have faced this miserable situation.

The Centre has also been saying about doubling the crop yield and going in for cash crops to benefit the farmers. But what happened in actuality? Recently, the States of Tamil Nadu, Maharashtra, UP and Punjab had bumper tomato crops. But 1kg tomato was sold for just 50 paisa. There were no takers even for that rate. So farmers had fed the cattle with tomatoes and dumped tomatoes on wayside. This is the situation our farmers live in. Sugarcane growers are adversely affected because the

† English translation of the original speech in Tamil.

Government did not control the movement of sugar in the market. Farmers have been pushed to the wall wherein they have begun feeling that it is better not to raise crops rather than produce and perish.

I wish to make a specific point here. I come from an agrarian family and see the fields and farmers every day. That is why I want to make this point. It will be disastrous for the country if farmers choose not to raise crops and let the lands lie barren. Then Tenth Plan shall remain only a plan on paper. From self-sufficiency we have to go abegging. It is for this reason that the Government should be very careful while taking decisions on agriculture related issues.

It is my duty to point out as to how agriculture in Tamil Nadu suffered because of the indifferent attitude of the Centre. Tanjore region, known as the granary of Tamil Nadu, is in a pathetic plight not being able to raise paddy. Because the monsoon failed repeatedly and Cauvery water turned out to be a mirage. It is because of the perseverance and the firm step taken by the Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Puratchi Thalaivi Amma that the Supreme Court directed release of some water to Tamil Nadu. I wish to emphasise that the Centre should take a decision on the share of water to the basin States impartially and on the basis of requirement taking into account the traditional rights of States.

As demanded by our Hon'ble Chief Minister, Dr. Puratchi Thalaivi Amma, the scheme to link peninsular rivers should be expedited.

Madam, to provide relief to the farmers in Tamil Nadu, the Hon'ble Chief Minister Amma has launched many welfare schemes. Even last month, relief schemes to the tune of Rs. 350 crores have been launched. For reclamation of saline land in 21 districts in the State over a period of 5 years, Tamil Nadu Government demanded Rs. 96 crores from the Centre. But the Centre has allocated only Rs. 6.9 crore for 2003-04 and 2004-05 for reclamation of 5000 hectare. I request the Hon'ble Minister to sanction 96 crore rupees as demanded by Tamil Nadu Government.

Madam, under the crop Insurance Scheme, if the claim amount is more than the premium amount, then the State and Central Governments have to share that. I request the Hon'ble Minister to see that this excess amount is also paid by the Insurance Company. Now compensation to

farmers is paid on the basis of the threshold yield calculated at the circle level. This should be calculated at the revenue village level and the compensation to the farmers should be paid accordingly. I request the Hon'ble Minister to reply to this point. But when crops suffer due to pest attack and vagaries of nature, then the affected area should be taken as a unit for paying compensation. Because, this kind of crop loss may not be spread over an entire circle. Therefore, it is necessary to localise to assessment and pay compensation accordingly.

I also appeal to the Centre to approve the South Pennai Catchment Area Scheme and New Irrigation Area Schemes proposed by Tamil Nadu Government. Thank you.

PROF. M. SANKARALINGAM (Tamil Nadu): Madam Deputy Chairperson, our economic and industrial growth is dependent on production and productivity in agriculture, which is the largest private sector in India. Despite fifty years of development in planning, rainfed agriculture continues to be the largest and the most important segment of the crop production in India. India is endowed with regional diversities, with uneven economic and agricultural development. Sustainable development depends on the prudent use of natural resources, namely, soil, water, livestock, plant genetics, fisheries, forestry, climate, rainfall and topography and an acceptable technology management. Rural development is a process of sustained growth of rural economy. Small and marginal farmers, traditionally the backbone of Indian agriculture, are now under threat. Though this sector provides employment to 56.7 per cent of the country's workforce, and agriculture accounts for about 14.7 per cent of the total export earnings, the budgetary allocation is not commensurate with the contribution of this sector to the development of the economy. Any change in this sector, positive or negative, has a multiplier effect on the entire economy of our country. The Departments of Agriculture and Cooperation were allocated Rs.9293 crores during the Ninth Plan, out of which Rs.7673.70 crores were utilised and Rs.1619.30 crores were surrendered. For the Tenth Plan, an amount of Rs.13300 crores was allocated by the Planning Commission. At this juncture, I wish to bring to the notice of the Government that the implementation of the scheme evolved was mainly the responsibility of the State Government. Agriculture is a State Subject; the Budget Estimates and the funds allocated are not sufficient to meet the needs of development in agricultural sector in each State. With the reduced

allocation of funds, the State Governments are not able to contribute their share in this development. Unless they give their share, the Planning Commission or the Central Government would not release their share also. So, ultimately, the poor agriculturalist, just because of certain technicalities between the Centre and the States, as also because of certain norms prescribed by the Planning Commission, are affected very much. Though this is a State Subject, the involvement of the Union Government started from 1950 with the take-over of the foodgrains trade and the Intensive Agricultural District Programme in 1961, the Intensive Agricultural Area Programme in 1964, and with the establishment of the Agricultural Prices Commission in 1965. But the removal of the Quantitative Restrictions on the import of agricultural products from other countries is a real challenge to the poor farmers.

The vagaries of monsoon play havoc to the routine - line of our rural farmers. Removal of concessions like electricity free use, subsidy on manure and other subsidies really affect the poor farmer and our economy also. We should have a mechanism to make the full utilisation of the allocated amount by the States. There must be an incentive grant for the States who utilise the allocated funds fully. There should be some other mechanism to discourage non-utilisation of the Plan funds allocated to the States. There should be a mechanism to monitor all these things, and sufficient interaction between the States and the Centre should be there. The import of all the commodities, including agricultural produce from April 1, 2001 for observing compliance with the WTO guidelines affected the prices of agricultural products adversely, and thus affected our farmers and our country's economy also. As on 1st April, 2002, the unspent balances were Rs.279 crores. During the year 2002-03, Rs.1064 crores more were allotted to the States. As on date, Rs.774 crores are lying unspent with the States. This shows the inefficient mechanism in the States. So, the Central Government should find out a mechanism to monitor these schemes. What I feel is, they are allocating lesser amounts because in the last year's Plan period, if the States were not able to fulfil the targets, then this year they are curtailing the allocations. This will create a detrimental effect not on the States but on the people of our country. In the financial year of 2003-04, the Department of Agriculture and Cooperatives demanded Rs.89.26 crores for seed development, but the Planning Commission accepted only Rs.27 crores on the pretext that they had not utilised the full amount in the previous Plan period.

**श्री आर.पी. गोयनका** (राजस्थान) : कृषि मंत्री तो हैं नहीं और उनके जो डिप्टी, असिस्टेंट हैं वह दूसरी दुनियां में हैं। वह सो रहे हैं मैडम।

**उपसभापति** : सुन रहे हैं। आंख बंद करके ज्यादा कंसंट्रेशन होता है।

**श्री आर.पी. गोयनका** : आंख बंद करने से अगर ज्यादा गंभीरता दिखाई देती हो तो हम लोग भी सोते रहेंगे।

**प्रो. राम देव भंडारी** (बिहार) : मैडम, कहावत है आंख बंद करना.....

**उपसभापति** अगर आप आंख बंद करने की कोशिश करें तो कृपया खर्राटे मत लीजिएगा। Then it becomes unparliamentary.

**श्री आर.पी. गोयनका** : वह तो खर्राटे नहीं भर रहे थे।

**उपसभापति** : वह ठीक कर रहे थे, मतलब जवाब तो देना ही पड़ेगा।

PROF. M. SANKARALINGAM: Madam, for plant protection, the projected amount by the Agriculture Ministry is Rs.47.85 crores, but the accepted amount by the Planning Commission is only Rs.25 crores. So also for horticulture the projected amount is Rs.478.70 crores, but the accepted amount is only Rs.277 crores. I can quote a number of items, but due to time constraint, I am leaving it. This is mainly due to the bankruptcy of the State finances. The Central Plans could be implemented only by mobilising States due funds first. Since the major task of restructuring the agriculture falls in the share of the State Governments, their financial capability needs to be enhanced

This can be done by making all the Union taxes shareable. When the division of taxes between the Union and the State Governments was made, the service economy was very small in terms of its share of the GDP. Now it accounts for 50 per cent of the GDP. But the taxes are not shared with the States. If all the taxes of the Union Government are shared with the States, the fiscal position may improve and they can contribute their mite for the development of our country. Our Finance Minister in his Budget Speech for 2003-2004 mentioned the agriculture and related aspects, including irrigation, as one of the *Paanch* Priorities for the economic security of the country. I am thankful for his remarks and for his recognition that agriculture is one of the five priorities.

The seasonal vagaries are due to the monsoon failure. Every year we are facing this problem in one part or the other part of the country. We must preserve and store water by constructing new dams and also linking our rivers and utilising the rainwater which is going waste into the sea. Madam, 75 per cent of our rainwater goes into the sea without being utilised. It shows our weakness in planning and implementation. ...(*Interruptions*)... My approach is different. ...(*Interruptions*)... Your approach may be different. ....(*Interruptions*)...

SHRI N. JOTHI (Tamil Nadu): Madam, some of the States are not willing to share water with their neighbouring States. They may rather allow it to go into the sea than sharing it with their neighbouring States. We have got one proud State like that. ...(*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: If it goes into the sea from your State, then you should stop it. ...(*Interruptions*)...

SHRI N. JOTHI: Madam, we are using it fully. We are not allowing even a single drop of water to go into the sea. But our neighbouring State is happy to allow it to go into the sea than giving it to us. This is the greatness and unity of India. ...(*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

PROF. M. SANKARALINGAM: Madam, I will make one or two more points. Madam, the crop insurance should be made compulsory.

SHRI H.K. JAVARE GOWDA (Karnataka): Both the AIADMK and the DMK always say that Karnataka is doing injustice. But it is not correct. ...(*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I was expecting your comments. ...(*Interruptions*)...

PROF. M. SANKARALINGAM: Madam, my time has been taken by both of them.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Your time is already over. ...(*Interruptions*)...You are rather exceeding it.

PROF. M. SANKARALINGAM: I am patiently hearing them because they are expressing their views. ...*(Interruptions)*...Madam, the Minimum Support Price should be fixed for all agricultural produce. The problems of the sugarcane growers should be solved. Madam, 25 per cent of the sugar production is purchased by the Central Government. It is done in order to give help to the sugarcane growers. But it is not so in some parts of the country. The Central Government must come to their rescue. Similarly, various diseases affect coconut and other plants and the miserable agriculturists are in a precarious position. If you go to Coimbatore and other areas, you will see that the tops of the coconut trees fall down. Therefore, we must have some intercropping system. If coconut crop fails, then some other crops should be given to the farmers. I feel that will help them. One of our hon. Members was mentioning that tomato is thrown on the road because we do not have any cold storages. We have no process of preserving it for a long-term use. So, all these things have to be done. We in Tamil Nadu have cotton weavers and cotton mills. We have to purchase cotton from the North or the Central India. When cotton is brought to South India, the Railways give no concession.

With these words, I conclude, Madam.

**उपसभापति** : प्रो. राम देव भंडारी । कृपया करके आप सब लोग समय का ध्यान रखें।

**प्रो. राम देव भंडारी** : मैडम, आप जो आदेश करेंगी, मैं उस आदेश का पालन करूंगा।

THE DEPUTY CHAIRMAN : Everybody is exceeding his time. ...*(Interruptions)*...We have to sit here all the time. ...*(Interruptions)*...

**प्रो. राम देव भंडारी** : आपका आदेश मान्य है, मैं उसी आदेश पर चलूंगा।

**उपसभापति** : आप मेरा आदेश मानकर सात मिनट बोल दीजिए।

**श्री बालकवि बैरागी** (मध्य प्रदेश) : मैडम, यह मामला दूसरा है। राम देव बोल रहे हैं, हुक्मदेव सुन रहे हैं। देवता से देवता की बात हो रही है, आप क्यों बीच मे पड़ रही हैं?

**प्रो.राम देव भंडारी** : माननीय उपसभापति महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने कृषि जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया है। महोदया, पहले गांवों में एक कहावत कही जाती थी - "उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान।" पहले खेती को सबसे सम्मानित काम समझा जाता था और जो किसान खेती से जुड़े होते थे, समाज मे उनकी

बड़ी प्रतिष्ठा होती थी मगर आज स्थिति बदली हुई है। आज यह स्थिति है कि अगर आपसी बातचीत में कोई यह कह दे कि मैं खेती करता हूं, मैं किसान हूं तो जो सामने वाला होता है, वह सोचता है कि इसके पास कोई दूसरा काम नहीं है, इसलिए खेती कर रहा है।

महोदया, वैसे भी भारत का किसान कर्ज़ मे जन्म लेता है और कर्ज़ में ही मरता है। हम अपने देश को कृषि प्रधान देश कहते हैं । इसलिए कहते हैं कि इसकी लगभग तीन-चौथाई आबादी कृषि से जुड़ी हुई है। हम यह भी कहते हैं कि इस देश का किसान, इस देश की रीढ़ की हड्डी है। मगर बड़े दर्द के साथ, बड़े दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आज किसानो की वित्तीय स्थिति किसी भी क्षेत्र मे काम करने वाले की वित्तीय स्थिति से दयनीय है। आज भी किसान अपना खून-पसीना बहाकर खेती करता है, उत्पादन करता है मगर स्थिति यह है कि आज उसकी उपज का खरीदार नही है। सरकार समर्थन मूल्य की घोषणा करती है, एफ.सी.आई. के माध्यम से कुछ क्रय केंद्र खोलती है मगर जब किसान अपनी उपज को लेकर बैलगाड़ी मे, ट्रैक्टर मे क्रय केंद्र पर जाता है तो कोई न कोई बहाना बनाकर उसे लौटा दिया जाता है। बिहार में एफ.सी.आई. के कई केंद्र खुले हैं मगर मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि एक बार आप इस बात का मुआयना कर ले कि उन केंद्रो मे खरीद का प्रतिशत क्या है? महोदया, उन केंद्रो मे खरीदारी नही की जाती है बल्कि किसान वहां से लौटते हैं। औने-पौने दामों मे किसानो को अपनी उपज बेचनी पड़ती है। एक ओर हम कहते हैं कि इस देश मे अनाज का बड़ा भारी भंडार है मगर दूसरी ओर लोग भूखे मरते हैं। यह शर्मनाक स्थिति है कि किसान आज आत्महत्या कर रहा है, अपनी फसल को खेतो मे जला रहा है। उनका गन्ना खेत मे जल रहा है। जो मिले हैं, जो मिल-मालिक हैं, ये उनका गन्ना नहीं लेते हैं और अगर लेते भी हैं तो औने-पौने दाम मे लेते हैं और उनको पैसा भी नही देते हैं। करोड़ो रुपया मिल-मालिकों पर बाकी है। किसानो को दोहरी मार सहनी पड़ती है। एक ओर डीज़ल का दाम बढ़ता है, सरकार डीज़ल का दाम बढ़ाती है और दूसरी ओर प्राकृतिक विपदाओ से उन्हे भारी मार झेलनी पड़ती है। 14 राज्यो मे सूखा पड़ा और बिहार के बीस जिलों मे इस बार बाढ़ आई थी, भारी बाढ़, जो हर साल आती है। यहां राज्य मंत्री बैठे हुए हैं। हम लोग एक ही जिले से हैं। उनका जिला दरभंगा है जहां से राज्य मंत्री जी आते हैं। मैं मधुबनी जिले से हूं और राज्य मंत्री जी मधुबनी जिले से लोक सभा मे प्रतिनिधि हैं। ये अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तरी बिहार में हर साल भयंकर बाढ़ आती है और हम लोग लगातार इस सदन मे और दूसरे सदन मे भी इसकी चर्चा करते रहते हैं। जब बाढ़ आती है तो फसल ही नहीं उससे जान-माल का भारी नुकसान होता है। हजारो, करोड़ रुपए का नुकसान होता है। उस नुकसान को किसानो को झेलना पड़ता है। बिहार सरकार, जो आर्थिक रूप से स्वयं ही कमजोर है, किसानों की सहायता नहीं कर पाती। जब भी समय आता है हम यहां केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगते हैं। विशेष कैटेगोरी मे बिहार राज्य को रखने की मांग करते हैं। मगर इस समय तक केन्द्र सरकार का कोई भी ध्यान बिहार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की ओर नहीं गया है। महोदया, किसान बैंकों से कर्ज लेता है, दूसरे स्रोतों से भी कर्ज लेता है। जब उसकी फसल नही होती है, उसकी फसल मारी जाती है तो वह कर्ज नही लौटा पाता है और बदले मे उसकी जमीन चली जाती है। उसके और भी बहुत सारे काम हैं- बच्चो की पढ़ाई करानी है, शादी -ब्याह करना है, नाते-रिश्ते निभाने हैं। इसके लिए उसे पैसों की जरूरत पड़ती है। कर्ज के लिए, बैंको भी उसे काफी दौड़-धूप करनी पड़ती है। उसके बावजूद थोड़ा बहुत कर्ज मिलता है। महोदया, आप जानती हैं, सभी जानते हैं कि बैंको मे किसानो को कर्ज

लेने के लिए कमीशन देना पड़ता है। इसके बावजूद उनकी जमीन चली जाती है। यही कारण है कि आज गांवो से लाखो की संख्या में लोग दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता जैसे शहरो मे आते हैं। वे मजबूरी मे आते हैं। वे मन से नहीं आते हैं। इसलिए कि गांव में उनके पास काम नही है। जो छोटे-छोटे काम थे। जो छोटे-छोटे गृह उद्योग थे, जो छोटे-छोटे कुटीर उद्योग थे, वे भी बन्द हो गए हैं। जो कुदाली बनती थी, जो खुर्पी बनती थी या अन्य कृषि का सामान बनता था, वह सामान भी अब गांव में नही बनता। इसीलिए आज गांवो में किसान खेती छोड़कर भाग रहे हैं। चपरासी की एक नौकरी मिल जाए तो पच्चीस एकड़ वाला किसान घर की खेती छोड़कर नौकरी करने चला जाता है। यह किसान की जो दयनीय स्थिति है, मैं इसके बारे मे चर्चा कर रहा हूं। महोदया, जल प्रबन्धन की स्थिति सबसे खराब है। वर्षा का पानी नदियो के माध्यम से समुद्र में चला जाता है। उसको आप व्यवस्थित नही कर पाते। दूसरी तरफ छोटे-छोटे कुएं, तालाब या छोटे-छोटे बांध बनाकर, छोटी-छोटी सिचाई योजनाएं बनाकर अगर हम जल प्रबन्धन की व्यवस्था कर सके तो वह खेती मे बड़ा काम आता है। महोदया, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उस क्षेत्र मे तालाबो की भरमार है। मेरे घर के दो सौ मीटर पर चारों तरफ चार-पांच तालाब हैं। राज्य मंत्री जी मेरे घर पर कई बार गए हैं । हम लोग एक ही पार्टी में थे, बहुत सीनियर हैं। हम लोग इनका भाषण कराते थे, इनका भाषण सुनते थे। मेरे गांव मे कम से कम चालीस -पचास तालाब हैं। महोदया, उन तालाबों में मछली पालन होता था। बीस-पच्चीस, किलो की मछली उन तालाबों मे होती थी। इसके अलावा मखाना उपजाया जाता था। मेरे क्षेत्र में पहले बगीचों की भरमार थी, तरह-तरह के आम होते थे। मगर आम जाएगा कहां, क्योंकि मार्केटिंग की कोई व्यवस्था नही है। इस वर्ष भी काफी आम आया है मगर मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं है। किसानों को उसका उचित मूल्य मिलना चाहिए वह मूल्य नहीं मिलता है। इसीलिए लीची की फसल हो, आम की फसल हो उससे दूसरे प्रोडक्ट बनाने के लिए उसी क्षेत्र में कारखाने लगने चाहिएं और बाहरी क्षेत्र में भेजने के लिए मार्केटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। वह व्यवस्था किसानों के लिए नहीं हो पाती है। नकदी आमदनी का स्त्रोत किसानों के पास नहीं है। बाढ़ रोकने की व्यवस्था होनी चाहिए। बाढ़ से राहत की व्यवस्था होनी चाहिए। मिट्टी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि बाढ़ में भारी तादाद मे पानी के साथ बालू आता है। जो नदियां नेपाल से आती हैं वे सिर्फ पानी ही नही लाती बल्कि पानी के साथ-साथ भारी तादाद में बालू भी लाती हैं। वे सैकड़ों, हजारों एकड़ जमीन को बालू से भर देती हैं। जो तीन-चार फसल देने वाली जमीन है उसमें बालू भर जाता है। ऐसे मे एक फसल उगाना भी मुश्किल है। इसलिए आज मिट्टी के संरक्षण की व्यवस्था की भी आवश्यकता है। पानी के प्रबन्धन की व्यवस्था, मिट्टी के संरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। किसानों को सस्ती दर पर डीजल उपलब्ध कराया जाए, खाद उपलब्ध कराई जाए, बीज उपलब्ध कराया जाए।

महोदया, बिहार में, सिंदरी में खाद का एक कारखाना था। सिर्फ एक कारखाना था। इस कारखाने में हजारों लोग काम कर रहे थे लेकिन इस कारखाने को भी केंद्रीय सरकार ने बंद कर दिया है। इस सदन में, बिहार विधानसभा और दूसरी संस्थाओं से, हमारी पार्टी की ओर से लालू जी ने भी इसके लिए मांग की है। बिहार विधानसभा ने भी मांग की है कि उस कारखाने को बंद नही किया जाए। लेकिन सरकार कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं हुई और उस कारखाने को बंद कर दिया गया । महोदया, अभी-अभी मैं कहना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)... मैं खत्म कर रहा हूं । मैं कहना चाहता हूं कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और जब से झारखण्ड बिहार से अलग हुआ है तब से तो बिहार मे सिर्फ कृषि रह गई है । सारे कल-कारखाने, मिनरल, माइन्स,

झारखण्ड मे चले गए हैं । बिहार सिर्फ एक कृषि प्रधान राज्य है। जब तक कृषि का बिहार में विकास नहीं होगा तब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता है।

महोदया, पशुपालन भी किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए एक बहुत अच्छा जरिया है। पशुपालन के जरिए भी किसान अपनी आर्थिक उन्नति कर सकता है । पशुपालन के लिए उसे अच्छे नस्ल के पशु की जरूरत है। मैं पुन: दोहराना चाहता हूं कि भारत का किसान अपना खून-पसीना बहाकर अभी भी देश के विकास में एक बड़ा योगदान कर सकता है। मगर उन्हें जो सुबिधाएं चाहिए, उनकी जो आवश्यकता है, आप उन्हे मुहैया कराएं ।

**[उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) पीठासीन हुए]**

पशुपालन के क्षेत्र में उन्हे अच्छी नस्ल की गाय, भैंस तथा और भी दुधारू पशु हैं, उन्हें मुहैया कराएं। पशुपालन के माध्यम से भी वे अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सकेंगे ।

महोदय, कहने को तो किसानों के लिए देश में सैकड़ों संगठन हैं, कभी-कभी छोटे-मोटे आंदोलन भी चलते हैं मगर पूरे देश में कोई ऐसा संगठन नहीं है जो एक आवाज में किसानो की समस्याओ को सरकार के सामने लाए। यही कारण है कि सरकार किसानो की आवाज पर ध्यान नहीं देती है । सकल उत्पादन में लगभग छब्बीस प्रतिशत योगदान किसानो का है। बजट मे किसानों के लिए नगण्य राशि का प्रावधान किया है । क्या आप कृषि के लिए समुचित कोष की व्यवस्था करेंगे ? आप बजट मे प्रावधान नहीं करेंगे तो किसान उत्पादन को कैसे बढ़ाएगा? महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी सरकार को किसानों की जो समस्याएं हैं, उनकी ओर ध्यान देना चाहिए । अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है । आजादी के पचपन वर्षों के बाद भी आज किसान वहीं खड़ा है जहां वह आजादी से पहले खड़ा था।

**उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक)** : कृपया समाप्त कीजिए।

**प्रो. राम देव भंडारी** : महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करते हुए सरकार से कहना चाहूंगा कि कृषि क्षेत्र, सबसे उपेक्षित क्षेत्र है, भारत का किसान, उपेक्षा का शिकार रहा है, पचौरी जी मंत्री जी के संदर्भ मे कह रहे थे कि किसानों की कोई लॉबिंग नही है । फाईव स्टार होटलों में बैठ कर किसानो की समस्याओं पर चर्चा करते हैं । किसानो का सच्चा प्रतिनिधि किसानो की समस्या पर चर्चा नही करता । वे जो अपने आपको किसानो का सब से बड़ा शुभचिंतक कहते हैं, हितचिंतक कहते हैं, जो किसानो के संबंध मे नीति बनाते हैं, उन्हे जमीनी सच्चाइयों का कुछ पता नही होता और किसानो की सच्ची समस्याओं को वे नही जानते । महोदय, किसानो की समस्याओं पर विचार करने के लिए किसानों की एक समिति सरकार बनाए जो सही मायनो मे किसानो की नुमायंदगी करती हो। अभी सौभाग्य से दोनों मंत्री किसान परिवार से आते हैं । राज्य मंत्री जी स्वयं भी किसान हैं, मैं जानता हूं, वे लगातार खेती करते रहे हैं, पंचायत के मुखिया रहे और जनता की सेवा करके वे मुखिया से मंत्री तक आए हैं । वे समाजवादी पार्टी मे लगातार काम करते रहे हैं । अब समाजवादी पार्टी के उलट बीजेपी में हैं । उन्हे पूरी जानकारी है । मगर सरकार में वे कितनी अपनी बात रख पायेंगे

और सरकार कितनी उनकी बात मानेगी, यह दोनों मंत्रियों पर निर्भर करता है । मगर किसानों की समस्या देश के तीन-चौथाई लोगों की समस्या है । इस समस्या पर सरकार को ध्यान देना चाहिए । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

**उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक)** : माननीय जे. चितरंजन ।

**श्री हरेन्द्र सिंह मलिक** (हरियाणा) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मुझे एक काम से जाना है । अगर आप अनुमति दें तो पहले बोल लूं ?

**उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक)** : नहीं, माननीया उपसभापति जी ने कहा है कि आपको थोड़ा पहले समय दे दें, लेकिन अभी माननीय चितरंजन जी बोलेंगे, उसके बाद आप बोलना । माननीय चितरंजन जी।

SHRI J. CHITHARANJAN (Kerala): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am grateful to you for having permitted me to speak on this important issue, that is, working of the Ministry of Agriculture. Everybody says that agriculture is the most important sector of our economy. But, unfortunately, from June 1991 onwards, that is, for the last more than 11 years, this sector is being neglected. This is the period when we were implementing the conditionalities regarding the structural readjustment of our economy and also new economic policies. The implementation of those policies has brought so many adverse reactions in various sections of our society, even among majoirty of the people and the most hard-hit area has been the agriculture sector. Now, in the agriculture sector, production is declining. Productivity is going down. The fertility of the land is going down. Prices of various agricultural commodities are falling down heavily. Peasants are greatly indebted. As a consequence, many of the peasants have committed suicides and several peasants are selling away their land and leaving this occupation. As a result, the number of landless peasants is increasing year after year. The number of small peasants is also increasing. The number of unemployed agricultural labourers is increasing. Under-employment among the agricultural workers is also increasing. This is the situation. Of course, we could claim that we have successfully implemented the Green Revolution, and we have become surplus in our food production, but if the present-day conditions continue and if things go on like this, within a very short time, we will have to face the reverse situation. We will have to face even a food deficit; and, not only that, it will also affect the economy very badly. If this condition prevails, that will be the best breeding ground for

anti-social elements. Our villages will be the best breeding ground for the recruitment to these terrorist groups. It will also be the breeding ground for various anti-social elements including *mafias*. And, if things go on like this, the situation in India will become very difficult, the social life itself will become difficult. My complaint is that neither the Government nor the Ministry is taking into consideration all these realities, and putting forth sufficient solutions for tackling the situation. That is my main criticism about it. For example, one of the main issues that the peasants are facing, at the moment, is the fall in prices. Previously, in the case of foodgrains, the minimum support prices were being declared, and, to some extent, the surplus foodgrains that were available with the peasants were being purchased. Of course, there were criticisms about that. I do not go into that. But, now, the Government is gradually trying to get out of it. That will not be there in the near future. Now, the Government has come forward with another proposal, namely, introducing a price stabilisation fund for finding solutions to the problems faced by the growers of coffee, tea, rubber and tobacco, say, certain particular items. Sir, even with regard to this, this will not even touch the fringe of the problem. It will not be a solution for the whole problem. But even looking at the problems affecting these particular sectors, I have got my own doubts as to whether this scheme will be effective at all. What is the idea? It is said that the stabilisation fund would be of Rs. 500 crores. Perhaps, the Government may allot Rs. 500 crores in the beginning. But the whole idea is that the peasants themselves will have to pay the money. If this year the prices are lower, then the minimum support price would be declared, and the balance will be given over to the peasants. But in the next year, if the prices are higher, the peasants will have to return back. I do not think that things will happen like this. In the present-day conditions, when the dollar is dominating the international trade and conditions of the W.T.O. are there, and the multi-nationals are holding the markets and the prices, I do not think that things will take place like this, that there will be an increase this year, and the next year, there will be a fall. Therefore, I do not think that this is a workable proposition. It is just to create an illusion. Anyhow, let them come out with the modalities of the scheme, then, we shall form an opinion about it.

Sir, another question is this. Take the case of coffee and tea estates. Several estates have been closed. In Kerala, one estate having 10,000 acres of land, a bigger estate, is lying closed, virtually closed. Then, several other estates, 15 or 16 estates, having about 3000 acres, are also

**5.00 P.M.**

lying closed and more are on the verge of closure. What is the solution? The Government is closing its eyes to it. The Government will have to make some provisions, it will have to take some steps to see that such estates are being revived.

Supposing they are not revived at the moment, what will happen? These estates will finish and then if at all you want to rebuild them, then it will be very, very difficult for you, and for that very huge investment will be required. Therefore, that problem should be attended to.

The second problem that I would like to raise is about irrigation. Even though we have passed 50 years, we have not irrigated even 50 per cent of the cultivable area and according to the scheme of the Government, even after 25 years, the position will be that only half the cultivable area will be irrigated. Then in that case, how will a solution be found? In 1996-97 a programme called the ABVP was adopted. Now what happens? Seven years have elapsed but much progress has not taken place. Therefore, irrigation also is not being properly attended to and enough of investment is not made.

My third point is regarding the credit facility. Sir, there also the peasants are not only neglected, but also cruelly discriminated. For example, during the last two or three years, the Government was reducing the interest rate in phases. But that benefit was not given to the agriculturists. Why can't they? They are thinking of giving it just now. What is the credit facility? Even now if you make an enquiry, you can find that majority of persons who are meeting their own demands, they are depending on *hundies*; paying an interest rate as high as 40 per cent, 50 per cent, 60 per cent and all that. What is the solution for that? (*Time bell*) I do not take too much time. My point is that the Government has not ...(*Interruptions*)...

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu) : He is retiring today. Please be considerate and let him continue. ...(*Interruptions*)...

SHRI J. CHITHARANJAN: I don't want to take more time. The main point is regarding serious problems that the agriculture sector is facing at the moment. They are not being seriously attended to. Proper solutions

have not been found out; proper investments have not been proposed. This is the situation. Therefore, my suggestion is that the Government and the Ministry will have to seriously think about it.

**श्री हरेन्द्र सिंह मलिक** : धन्यवाद, उपसभाध्यक्ष महोदय, जो आपने मुझे कृषि जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, यह किसान वर्ष है और इस मुल्क का किसान आज भी तबाही के कगार पर है। आजादी के बाद से कृषि का उत्पादन तो बढ़ा है, लेकिन उसमें सरकारों का कोई योगदान नहीं रहा है। उस गरीब, लाचार, बेबोलते किसान ने सावन और भादो की काली रात में, सांप और बिच्छू के डर से मुक्त होकर और ठिठुरते जाड़े में अपने खेतों में अपने दस साल से लेकर नब्बे साल के परिजनों का पसीना बहाकर इस मुल्क के लिए खाद्यान्न पैदा करने का काम किया है, लेकिन आज भी किसान दुखी है। दुर्भाग्य तो यह है कि इस किसान वर्ष में, जहां केन्द्र सरकार ने बड़े बड़े विज्ञापन छापे कि इस वर्ष को किसान वर्ष मनाया जाएगा वहीं इस मुल्क के सब हिस्सों में किसान ने या तो अपनी फसले जलाई हैं या उसने आत्महत्या की है।

मान्यवर, आप खुद किसान हैं। मैं जानता हूँ कि आप चरण सिंह वादी हैं। आज तो चरण सिंह जी के नाम को बेचा जाता है, चरण सिंह जी के नाम को भुनाने का काम किया जाता है। जो आदमी सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवी लाल के सपनों को नहीं देख सकते हैं, वे इस तरह की बात करते हैं। मान्यवर, यहां राज्य मंत्री जी बैठे हैं, इनकी विभाग में तो कोई मानता नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा इनसे अनुरोध है कि जो सत्य है उसे स्वीकार करें क्योंकि आप खुद किसान हैं, आप गांव के सरपंच से उठकर के यहां तक आए हैं, आपका राजनैतिक जीवन सत्यता का प्रतीक है और आप ईमानदार भी हैं। परन्तु उसके साथ-साथ यह कालिख जो आपके यहां लग रही है, इसको साफ करने का काम भी करेंगे।

मान्यवर, मैं दो बिन्दुओ पर चर्चा करना चाहता हूं - किसान के मामले पर और कृषि मंत्रालय के क्रियाकलापों पर। किसान तो तबाह-ओ-बर्बाद है। आज गन्ने का किसान अनिश्चितता में जी रहा है -- उसने पहले सूखे की मार झेली, अपना गन्ना खेत में जलाया, आज उसे अनिश्चितता है। 40 रुपए क्विंटल भाव मिल रहा है। इस्मा जो सुप्रीम कोर्ट में गई, दुर्भाग्य यह है कि उसने जहां दूसरी चीज़ क्वोट की वहीं इसके साथ-साथ भारत के कृषि मंत्री का एक बयान भी क्वोट किया, जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना मूल्य उत्पादन लागत 43 रुपए प्रति क्विंटल मात्र आती है, मेरे पास यह सबूत है। आखिर क्यों उठाया गया किसान के साथ इतना दुर्भाग्यपूर्ण कदम? क्या 43 रुपए क्विंटल लागत आती है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि 43 रुपए क्विंटल का बयान दिया गया है इसी राज्य सभा में। इस्मा ने यह कहा। मेरा माननीय सदस्यों से भी अनुरोध है, सब कहते हैं कि यह कृषि मंत्री किसान के बेटे हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूं कि क्या इन्होंने कभी खेत की मुंडेर पर चलकर देखा है? क्या इन्हें जानकारी है कि माह-पोह के पाले में गेहूं की फसल को कोर किस तरह दी जाती है? क्या इन्हें जानकारी है कि खेत में आलू कहां बोया जाता है? मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस किसान वर्ष को, जो चौधरी चरण सिंह की जन्मशताब्दी के नाम पर मनाया गया है, इस वर्ष में हमारे और आप जैसे करोड़ों किसानों की भावनाओं के

साथ खिलवाड़ न किया जाए और इन बिन्दुओं की जांच की जाए कि आखिर किसान को लूटने के लिए जो इस्मा को लाभ पहुंचाने का यह बयान दिया गया है, यह किस कारण दिया गया है।

दूसरे मान्यवर, यही से आपकी पीठ से ही निर्देश होना चाहिए कि जब तक इस देश के किसान का गन्ना खेत में खड़ा रहेगा तब तक शूगर मिलें चलेंगी। क्योंकि आज एक दूसरा षड्यंत्र हो रहा है कि किसान का गन्ना खेत में खड़ा है और मिलें बंद होने जा रही हैं, किसान अपना गन्ना 40 रुपए क्विंटल बेच रहा है। मैं अनुरोध करूंगा कि आप निर्देश दें और केन्द्र सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि जब तक किसान का एक भी गन्ना खड़ा रहेगा तब तक शूगर मिलें चलेगी। कृषि मंत्रालय यह कहता है कि गन्ना मेरा विभाग नहीं है। हमने चार बार इस माननीय सदन मे यह मामला उठाया, यह सर्वोच्च सदन है, लेकिन एक बार भी कृषि मंत्रालय की तरफ से जवाब नहीं आया। हो सकता है पढ़ाई-लिखाई में एक-आध दर्जे हम नीचे हों लेकिन इतना जरूर है कि हमने जमीन पर खेती अपने हाथों से की है और उन महापुरुषों के चरणों की धूल अपने माथे पर लगाकर राजनीति की है, जिनका नाम बेचने का काम रोज किया जाता है। कांग्रेस के हमारे साथी खुश हो रहे हैं।

मान्यवर, दूसरा मामला तासीर के मुताबिक आता है। आलू के किसान की बात अगर मैं करूं तो आज आलू का किसान आत्महत्या कर रहा है। मैंने इसी सदन में कहा था कि आगरा का भगवान सिंह नधेऊ का रहने वाला और इसलिए आत्महत्या कर गया कि उसका आलू नहीं बिक पाया। घनश्याम सिंह जीवन-मरण से जूझ रहा है। पिछले साल धारवाड़ में पांच आलू के किसानो ने आत्महत्या की। आखिर क्यों?, क्या जरूरत थी कृषि मंत्रालय को या माननीय कृषि मंत्री जी को यह बयान देने की कि आगरा को आलू का एक्सपोर्ट जोन बनाया जाएगा? सारी दुनिया का आलू आ गया। क्या जरूरत थी नाफेड का 200 करोड़ रुपया दूसरी जगह डाइवर्ट करने की? मान्यवर, हम इस सम्मानित सदन में बात कहते हैं लेकिन उसकी जांच नहीं होती। मैंने इसी सम्मानित सदन में कहा था और आप ही उस दिन पीठ पर विराजमान थे, आप ही सुशोभित थे, मैंने आपसे अनरोध किया था और मेरा अनुरोध आज भी है कि एनसीडीसी, नाफेड, नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड, एनडीआरआई, इनके गत तीन साल के क्रियाकलापों की संसदीय समिति बनाकर जांच कराई जाए क्योंकि इसमें गरीब किसान का पैसा लगा है। अगर किसान के हितार्थ लगा है तो जांच से क्यों घबराते हैं? हम तो कहते हैं कि हमारे राजनीतिक जीवन की पूरी जांच कराई जाए। क्यो जांच नहीं कराई जाती, क्या कारण है? मान्यवर, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि एनसीडीसी जैसी जगह, जहां भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर से कम का अधिकारी नियुक्त नहीं हो पाता था, मैं माननीय अरुण शौरी जी से अनुरोध करूंगा कि वे गौर करें वहां 85 बैच का अलाइड सर्विस का एक अधिकारी बैठा दिया गया, एनडीआरआई के डायरेक्टर के पद पर, जहां गाय और भैंस का काम होता है। मखदूमपुर से लाकर एक ऐसा आदमी बैठा दिया गया जो भेड़-बकरी से ज्यादा कुछ जानता नहीं। मैंने माननीय प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा था और माननीय प्रधान मंत्री जी ने कृषि मंत्रालय को शायद इस आशय के साथ भेजा होगा कि वे सदस्य की भावनाओं का कुछ संमाधान करेंगे, लेकिन मुझे कृषि मंत्रालय से ऐसा पत्र प्राप्त हुआ जैसे की एनडीआरआई उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति हो। उसमें लिखा है कि That was an administrative decision." यह क्या मखौल है? मान्यवर, यह मैं नही कह रहा, आज मैं कह रहा हूं माननीय शौरी जी, कल आप कहेंगे क्योंकि पिछले दो

महीने मे जितनी आलोचना पचौरी जी ने या प्रणव मुखर्जी जी ने नही की होगी, उतनी आलोचना आपकी सरकार की माननीय कृषि मंत्री जी ने की है। मुझे तो अफसोस होता है कि इनका स्वभाव आलू जैसा है। जैसे आलू हर सब्जी मे ढलता है, वैसे ही ये भी हर सरकार में रहते हैं लेकिन उसके बाद भी ये आलू के किसान को नहीं बचा पाए। यह क्या हो रहा है? यह क्या मखौल है? हम चाहते हैं कि आप सरकार को निर्देशित करें, इसमें संकोच न करे। इस सदन मे आना एक सौभाग्य की बात है। यह भारत का सर्वोच्च सदन है। आज आप पीठ पर आसीन हैं। मैं किसी को आरोपित नही कर रहा हूं, संसदीय समिति बनाकर इसकी जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।

मान्यवर, महाराष्ट्र के अंगूर के किसान का क्या हाल हुआ? कर्नाटक के अंगूर के किसान का क्या हाल हुआ? कपास के बारे मे यहां बार-बार चर्चा होती है। आज भी एक माननीय सदस्य ने स्पैशल मैंशन के माध्यम से वह बात यहां उठाई। क्या कारण है कि BT Cotton को परमीशन दे दी गई और 20 रुपए किलो का बिनौला 300 रुपए किलो मे बिक गया और उसकी पेरेटल लाइन तक नही पूछी गई? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर किसान को जिंदा करना है तो कम से कम इस मुल्क मे जो मल्टी-नेशनल कंपनीज़ आई हैं, चाहे वे पैस्टिसाइड्स की हो, चाहे वे सीड्स के क्षेत्र में हों, उनको परमीशन देने के बारे मे जांच कराई जानी चाहिए।

मान्यवर, मैं बड़े अदब के साथ, बड़े सम्मान के साथ यह आशा करते हुए कि एन.डी.ए. की सरकार एक साफ-सुथरी सरकार रहेगी, यह बताना चाहता हूं कि BT Cotton में 3 करोड़ रुपए का लेनदेन हुआ है और यह मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। आप जांच कराइए, तथ्य सामने आ जाएगा। क्या कारण है कि आप इसकी जांच नही कराते?

मान्यवर, उत्तरांचल के टमाटर के किसान का क्या हाल है? जब उसका टमाटर किसी ने नही खरीदा तो वह ट्राली खाली करके सड़क पर डालकर चला आया और नेफेड क्या कर रही है? इसका काम क्या था? दिल्ली मे आज ट्रको की हड़ताल की बात छोड़ दीजिए, इससे पहले भी दिल्ली मे आलू 4 रुपए या 5 रुपए किलो था, जब कि उत्तर प्रदेश मे आलू 50 पैसे प्रति किलो बिक रहा है। यह असमानता क्यो है? क्या कारण है कि नीतियां गलत हो रही हैं?

मान्यवर, अब मैं दिल्ली मिल्क सप्लाई की बात करना चाहता हूं। मेरा आपसे अनुरोध है, मैं बहुत छोटा सा अनुरोध कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि शौरी जी इस पर गौर करेंगे। दिल्ली मिल्क सप्लाई मे पिछले 4 सालो मे जिन लोगो का दूध आपूर्ति के लिए लगा है, उसकी जांच कराइए कि किस तरीके से लगा है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, मेरी यह जानकारी है कि उसमें भी लेनदेन हुआ है। क्यो हुआ है? किसके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं? जो लोग आज दूध की आपूर्ति कर रहे हैं, वे तालाब का पानी मिलाकर उसको भारी कर देते हैं ताकि मिल्क मीटर यह कह दे कि दूध ठीक है। वे तो शुद्ध पानी तक उसमे नही डालते।

मान्यवर, इस सरकार की दोषपूर्ण नीतियो के कारण हमारा उत्पादन गिरा है। मैं थोड़े से तथ्य आपकी अनुमति से यहां रखना चाहता हूं। फूडग्रेन्स का उत्पादन 2001-2002 मे 212.02 मिलियन टन हुआ और 2002-2003 में जब मल्टी नेशनल कंपनीज़ यहां आई और जब फाईल मे कुछ पहिए लगने का काम शुरू हुआ तो वह उत्पादन घटकर 183.17 मिलियन टन रह

गया। ऑयलसीड्स का उत्पादन 5 मिलियन टन गिरा। शूगरकेन का उत्पादन 15 मिलियन टन गिरा और कॉटन का उत्पादन पहले जहां 10.09 मिलियन टन था, वह घटकर 8.94 मिलियन टन रह गया। यही नही, अगर हम प्रति हैक्टेयर उत्पादकता की बात करें तो मैं कहना चाहूंगा कि कृषि मंत्रालय हमारे लिए सफेद हाथी है। कोई नयी वैरायटी लागू नहीं होती। इनकी नीतियो मे कही कोई तालमेल नहीं है। ये तो केवल मल्टी नेशनल कंपनियों के liaison का काम कर रहे हैं। यह एक तथ्य है। मैं तथ्य के आधार पर यह कह रहा हूं कि USA मे प्रति हैक्टेयर भूमि में 7,037 किलो चावल पैदा होता है लेकिन भारत में प्रति हैक्टेयर भूमि मे केवल 3,008 किलो चावल पैदा होता है। इसी तरह प्रति हैक्टेयर भूमि मे केवल 7,856 किलो शूगरकेन पैदा होता है ...**(समय की घंटी)**...

मान्यवर, अभी तो मैंने बोलना शुरू किया है। मेरे मन मे पीड़ा है। हम रोज लुट रहे हैं और किसान के नाम पर लुट रहे हैं। हम जिनके कारण लुट रहे हैं, वे बयान दे देते हैं कि कृषि नीति वे लोग बना रहे हैं जो एयर कंडीशंड कमरो में बैठकर काम करते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम लोग सड़क पर जाकर काम करते हैं। यही नहीं, हम लोगो को अपमानित करने का काम भी किया जाता है और पब्लिक मीटिंग्स मे भाषण भी दे दिए जाते हैं कि कोई भी माननीय सदस्य कृषि पर चर्चा नही करना चाहता। इसका क्या कारण है? मान्यवर, फसलो का उत्पादन गिरा है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये ज़ो बयान दे देते हैं, उसके कारण कृषि मंत्रालय को नुकसान भी हुआ है। इन्होने 25 हजार करोड़ रुपए मांगा और उन्हें तेरह हजार दो सौ करोड़ मिला। चूंकि इनकी आस्था आदरणीय प्रधान मंत्री जी में नहीं थी इसलिए इनको यह मिला। आज बार-बार चर्चा हो रही है इंकम टैक्स की। इंकम टैक्स इस मुल्क के किसानो पर कोई लगाने नहीं जा रहा है। यहां लोकतंत्र है, किसान की वोट बहुत है इसलिए उन पर इंकम टैक्स नही लग रहा है। पर सत्यता यह है, हम भी चाहते हैं कि उन लोगो को चिन्हित किया जाए जो किसान के नाम पर फार्म हाउस बना करके, बड़े-बड़े फार्म लेकर के खेती कर किसान को कलंकित करने का काम करते हैं, जो अपने हाथ से खेती नहीं कर सकते। यह धरती मां है और मां का पुत्र वह होता है जो उसकी सेवा करता है, धरती की सेवा उसका पेट चीर करके उसमे खाद्यान्न बोने का काम करने का है। जो आदमी खुद खेती नही कर सकता वह किसान कहलाने का हकदार इस मुल्क मे नही होना चाहिए, किसान के नाम पर उसे लूट की अनुमति नही मिलनी चाहिए। मान्यवर, बजटीय सहायता का 1.3 प्रतिशत मात्र इन्हें प्राप्त हुआ। क्रियाकलाप इनके और नुकसान उठाए पूरे मुल्क का गरीब किसान। मान्यवर, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। मान्यवर, एक्सपोर्ट की बात कही जाती है। क्या तंत्र है हमारे कृषि मंत्रालय के पास? कब किस मुल्क मे, किस क्वालिटी का, किस तरह का खाद्यान्न जाएगा, कृषि का प्रोडक्ट जाएगा इसके बारे मे क्या समुचित सूचना है? आप कह रहे हैं कि इंटरनेट से जोड़ दिया, सत्य है। माननीय मंत्री जी ने सही कहा है। यह लोग तो ए.सी. में बैठ करके सोचते हैं, जोड़ते हैं। इन्हे यह पता नही है कि गांव मे इंटरनेट क्या टी.वी. भी नही है बहुत से गांवों मे। हम गांव से आते हैं। हम लोगो ने दर्जे-8 तक पांच किलोमीटर की दूरी पर जाकर के पैदल जाकर के पढ़ाई की और ग्रेजुएशन व पोस्ट ग्रेजुएशन मे जाकर के स्कूल के दर्शन किए। इंटरमीडिएट तक देहात मे पढ़े हैं। इन्हे हिन्दुस्तान की भौगोलिक जानकारी नही है। हमने बहुत ढोया है जब हम ले जाकर के खेत के किनारे खड़े कर दिया करते थे और कहा करते थे कि जल्दी चलो, जल्दी चलो। दुर्भाग्य है तथा प्रभु भी अजीब निर्णय लेता है। कुछ पता नही

क्या बात है, बड़े सक्षम भी लगते हैं माननीय मंत्री जी। जब अपना हित साधना होता है तो 180 डिग्री के कोण पर तुरन्त घूम जाते हैं। परन्तु एक दुर्भाग्य सबसे बड़ा यह है हमारे सामने कि जिस मंत्रालय को इन्होंने हाथ लगा दिया उस मंत्रालय का विनाश हो गया, जिस पार्टी को हाथ लगा दिया उसका विनाश हो गया। अब एग्रीकल्चर से हम लोगों को बचाने का काम करें। यही हमारा आपके माध्यम से अनुरोध है। मान्यवर, जहां तक कृषि मंत्रालय की नीतियों का सवाल है, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि ...**(व्यवधान)**... माननीय शौरी जी के नेचर के प्रतिकूल है यह एग्रीकल्चर का मामला। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिन-जिन बिन्दुओं पर लगा है, यह रोज-रोज बोलने का काम न रहे। क्या कारण है? हमने इंकम टैक्स के बारे में माननीय प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा। पर मैं जानता था कि मेरे राष्ट्रीय नेता की आस्था प्रधान मंत्री जी में है, एन.डी.ए. में है। तो हम उसको प्रेस के संज्ञान में नहीं लाए। ये केबिनेट में बैठ करके दूसरी बात करते हैं और प्रेस में जाकर के दूसरी बात करते हैं। अभी माननीय पचौरी जी ने पढ़ करके सुनाया, एक नहीं हजार हैं, आज ही मैंने समाचार पत्र में पढ़ा कि तबादलों में लेन-देन हो रहा है। एक महात्मा के पास एक आदमी गया कि मेरा लड़का बड़ा गुड़ खाता है। तो महात्मा ने कहा कि परसों आना। वह परसों गया तो उससे कहा कि आठ दिन बाद आना। आठ दिन बाद गया तो उसने कहा कि -बेटा, गुड़ खाना छोड़ दे। उस आदमी ने पूछा कि अगर आपको यही कहना था तो दस दिन पहले कह दिया होता। तो महाराज जी ने कहा कि मैं सबसे ज्यादा गुड़ खाता था, पहले मैंने गुड़ खाना छोड़ा तब मैं दूसरे को कह रहा हूं। अगर भ्रष्टाचार की इन्हें शिकायत है तो सबसे पहले इनके मंत्रालय के ट्रांसफर, पोस्टिंग, नोमिनेशंस और इनकी नीतियों की संसदीय समिति बना करके जांच कराई जाए। 99 परसैंट मामलों में लेन-देन का मामला प्रकाश में आएगा, यह मैं दावे और चुनौती के साथ कहना चाहता हूं। मैंने यह चेयर से अनुरोध किया, अच्छा रहता मैं माननीय मंत्री जी के समक्ष यह बात करता और सम्मानित सदन के संज्ञान में यह बात लाता ताकि जवाब साफ-साफ आ जाता।

**उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक)** : एन.डी.ए. की बैठक में कर लीजिएगा।

**श्री हरेन्द्र सिंह मलिक** : मान्यवर, एन.डी.ए. की बैठक में मेरा जाने का सौभाग्य नहीं होता। मैं एन.डी.ए. में तो हूं, पर मान्यवर, यहां किसान की हैसियत से हम लोग बोलते हैं और राज्य सभा का एक सिस्टम रहा है कि यहां राजनीतिक दलों से ऊपर उठ करके लोग बड़ी स्वतंत्रता से अपनी बात कहते हैं। इसलिए ...**(व्यवधान)**...

**श्री सुरेश पचौरी** : दिल से दिल की बात कह रहे हैं।

**श्री हरेन्द्र सिंह मलिक** : दिल से दिल की बात कह रहा हूं, हां, पीड़ा है। आपको भी पीड़ा है, आप न बोलें आपकी कुर्सी की मजबूरी होगी। जिस दिन आप लोगों ने राज्य सभा में वोट दी थी आपके मन में यह भावनाएं नहीं रही होंगी।

मैं आपके माध्यम से पुनः अनुरोध करना चाहता हूं कि कृषि मंत्रालय के क्रियाकलापों पर गंभीरता से, सतर्कता से निगाह रखी जाए। ये क्रियाकलाप किसान के हित में नहीं हैं। तंबाकू का किसान, आलू का किसान, अंगूर का किसान, टमाटर का किसान, गन्ने का किसान बर्बादी के

कगार पर है, वह रोज मर रहा है। मान्यवर, मेरा आपसे अंतिम अनुरोध है कि कम से कम एक निर्णय तो आप दे ही दें कि जब तक गन्ना किसान के खेत में गन्ना रहेगा, चीनी मिल को बंद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। महोदय, 40 रुपये क्विंटल गन्ना बिक रहा है। शादियों का सीज़न चल रहा है। आप मेरे साथ चलकर देखें, हर गांव में सौ-सौ लड़कियां ऐसी मिल जाएंगी जो इंतजार करती हैं कि उनके हाथ पर मेंहदी कब लगेगी? उसके मां-बाप रो-रोकर कहते हैं कि इस बार गन्ना नहीं बिक रहा है, अगली बार गन्ना बिकेगा, तब जाकर शादी हो पाएगी। आगरा मंडल हो, मुरादाबाद मंडल हो, मेरठ मंडल हो और चाहे फरूखाबाद हो, कहीं का हो, हर जगह किसान परेशान हैं। मान्यवर, जिन बयानों के कारण नुकसान हुआ है, वे बयान किस परिस्थिति में दिये गये, इसकी भी जांच होनी चाहिए। मान्यवर, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद किन्तु मैं एक अनुरोध करूंगा। यह सर्वोच्च सदन है, कुछ कह तो दें, कुछ निर्णय तो दें। धन्यवाद।

**श्री सुरेश पचौरी** : आपकी बात पर हुक्मदेव जी सिर हिला रहे थे। अब ये हुक्म के पत्ते नहीं रहेंगे। आप चिंता मत करिए।...**(व्यवधान)**...

**उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक)** : चीनी मिलों के संबंध में जो आपने बात कही है, सरकार उसको सुन रही है और मैं समझता हूं कि सरकार उस पर सही प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी।

**श्री भूल चन्द मीणा** (राजस्थान) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज की चर्चा का विषय कृषि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कृषि हमारे देश की आर्थिक स्थिति की रीढ़ की हड्डी है। हमारे देश की आर्थिक स्थिति की आत्मा भी कृषि है। आज देश की 72 प्रतिशत जनता कृषि पर आधारित है। जीवन का साधन भी कृषि से ही उपलब्ध होता है। कृषि एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है कि देश का किसान आर्थिक रूप से मजबूत होगा तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत और शक्तिशाली बनेगी। माननीय मंत्री महोदय ने देश के किसानों के लिए 2000 में एक कृषि नीति की घोषणा की थी। इस कृषि नीति में कृषि की उत्पादन वृद्धि दर चार प्रतिशत रखी गयी थी। आपने उत्पादन वृद्धि दर तो चार प्रतिशत रखी लेकिन इसके अंदर, इस नीति के अंदर यह व्यवस्था नहीं की कि इस चार प्रतिशत को कैसे प्राप्त किया जाएगा? आपकी कृषि नीति के अंदर किसानों को कैसे बिजली मिलेगी, कैसे खाद उपलब्ध होगी, कैसे खेती के लिए पानी उपलब्ध होगा, इसके लिए व्यवस्था नहीं की गयी। आज देश के अंदर किसान के ऊपर राजनैतिक राज का प्रकोप हो चाहे प्राकृतिक प्रकोप हो - मुझे याद आता है जब सरकार के चुनाव हो रहे थे, उस समय जयपुर की सभा के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी बात कह रहे थे कि यदि हमारी सरकार दुबारा आयी तो मैं किसान की बहबूदी करूंगा, किसान का डीज़ल सस्ता करूंगा, किसान की खाद सस्ती करूंगा। मैं भी सुन रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ कह रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री जी और इस सरकार में बैठे हुए लोग किसानों से धोखे की बात करके किसानों का वोट जरूर प्राप्त करते हैं। किसान का वोट तीन तारीख को पेटियों में बंद हो गया, रातों-रात डीजल के दाम बढ़ा दिये गये। किसान को पता लगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है। डीज़ल के भाव बढ़ने के बाद भी इस सरकार को तसल्ली नहीं हुई और किसान को दुखदायी करने के लिए खाद पर जो सब्सिडी की व्यवस्था इस देश के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी ने की थी, उस सब्सिडी

को भी हटा दिया। खाद महंगी हुई, किसान त्राहि-त्राहि करने लगा, तब जाकर विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने इस देश के प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी कि प्रधान मंत्री जी, आपने चुनाव मे वादे कुछ किए, चुनाव मे लोगो के सामने विश्वास कुछ दिलाया और अब उलटा काम इस देश के किसानो के साथ कर रहे हैं! किसान के डीजल के भाव बढ़ा दिए, किसान की खाद से सबसिडी हटा ली और किसान जो पैदावार करे, उस पैदावार का मूल्य भी आप नहीं दे रहे तो क्यो नहीं कांग्रेस को आंदोलन करना पड़ेगा किसानो के लिए? तब जाकर प्रधानमंत्री जी की आंख खुली कि शायद कांग्रेस आंदोलन कर दे, देश मे किसान आंदोलन कर दे, देश मे एक आंदोलन की लहर चल जाए, मेरी सरकार को शायद संकट आ जाए इसलिए प्रधानमंत्री जी ने समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी।

मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कृषि मंत्री जी कि इस देश के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी, 1996 तक डीज़ल का भाव क्या था? साढ़े सात रुपए लीटर। खाद का मूल्य सस्ता था, खाद पर सबसिडी थी और पैदावार का मूल्य क्या था? इस देश मे सरसो पैदा होती है, सरसो 2500 रुपए क्विंटल थी, गेहूं 900 रुपए क्विंटल था। आज डीज़ल का भाव बीस रुपए हो गया है साढ़े सात रुपए से और पैदावार का मूल्य - सरसो का मूल्य लगभग आधा, 1200-1300 रुपए क्विंटल हो गया है और गेहूं का मूल्य 600 रुपए क्विंटल। कहां तो किसान की बहबूदी की बात कर रहे थे, कहां किसान के विकास की बात कर रहे थे? आपकी सरकार ने किसान को दी जाने वाली सबसिडी का बहुत शोर मचाया कि यह सबसिडी गलत है, लेकिन आपको पता है, आज दुनिया में यदि हिंदुस्तान के किसान की सबसिडी की तुलना की जाए तो वह ऊंट के मुंह मे जीरे के बराबर है। कृषि मंत्री जी, यूरोपीय यूनियन मे तीस देश आते हैं, उन तीस देशो मे वहां के किसान को क्या सबसिडी दी जाती है? जापान में 6915.6 डॉलर एक हेक्टेयर पर सबसिडी है। यूरोपीय यूनियन के तीस देशो मे 1061 डॉलर सबसिडी प्रति हेक्टेयर है। न्यूज़ीलैंड मे 317.1 डॉलर एक हेक्टेयर पर है। अमेरिका जैसे राष्ट्र में जहां एक प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं, 184.8 डॉलर प्रति हेक्टेयर है और अब हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान मे 17.8 डॉलर सबसिडी है प्रति हेक्टेयर। इस सबसिडी को खत्म करने के लिए आपकी सरकार ने बहुत शोर किया। क्या आप किसान के विकास की बात करते हैं? किसान की बहबूदी की बात करते हैं? ऐसा लगता है कि आपकी सरकार का दृष्टिकोण किसान के प्रति ठीक नहीं है, इसको ठीक करना पड़ेगा। आज देश का किसान मेहनत मज़दूरी करने के बाद जब कृषि की उपज पैदा करता है तब जो लागत लगती है, वह लागत पूरी नहीं हो रही है। इस कारण किसान लागत प्राप्त नहीं कर रहा है। आज देश के कई राज्यों में उपज का सही मूल्य नहीं मिलने के कारण उसने जो बैंकों से कर्ज़ ले लिया या किसी और से कोई कर्ज़ ले लिया, वह चुका नहीं पा रहा है। इसलिए वह आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है। इसकी ओर आपको ध्यान देना पड़ेगा, किसान की रक्षा करनी पड़ेगी नही तो इस देश की आर्थिक स्थिति कभी मजबूत नहीं हो सकती। जब तक किसान गरीब रहेगा तब तक यह देश गरीब रहेगा। ...**(समय की घंटी)**...

**उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक)** : आपके दल के केवल बारह मिनट शेष थे जिसमें अभी दो और माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

**श्री मूल चन्द मीणा** : कृषि मंत्री जी, मैं आपका ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं। उपसभाध्यक्ष महोदय, आप बोल रहे थे कि कृषि की उपज का निर्यात करने की कुछ बात इस

सरकार ने की है। आपको पता है मंत्री महोदय, बहुत बड़ा घोटाला आपकी सरकार ने किया है कृषि निर्यात के नाम पर। आपने बी.पी.एल. के रेट के आधार पर कुछ एजेंट, कुछ कंपनियो को गेहूं दिया। चावल दिया कि आप निर्यात करिए। उन कम्पनियों और एजेंटो ने निर्यात नही किया। सस्ती दर पर गोदामो से गेहूं उठा लिया और मंडी मे बेच दिया गया। मैं आप से जानना चाहूंगा कि करोड़ों टन गेहूं इस प्रकार से बेचा गया है। आपके एग्रिकल्चर के अधिकारी और आपके ये एजेंट जिनको नियुक्त किया है, इन्होने मिलकर घोटाला किया है। यह बता दीजिए कि आपने करोड़ टन गेहूं और चावल निर्यात किया है तो किस देश को गया है, कितना गया है? इसकी जांच करा लीजिए करोड़ों का घोटाला निकलेगा। कृषि अधिकारियों और उन एजेंटो ने मिलकर खाया है इसका मैं आपसे जवाब चाहता हूं कि आप क्या जवाब देते हैं। क्या आप इसकी जांच करेंगे?

**उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक)** : माननीय मंत्री जी, यह बहुत गंभीर मामला है। इस पर विचार करें।

**श्री मूल चन्द मीणा** : आज जब कृषि पर चर्चा हो रही है तो मैं राजस्थान की बात कहना चाहता हूं। आपने एपीएल और बीपीएल गेहूं की सारे देश के अंदर एक नीति बनाई है। लेकिन जब हम राजस्थान की तुलना करते हैं तो एपीएल और बीपीएल मे कोई तुलना ही नहीं हैं वहां पर। चार साल से कंटिन्यू अकाल है। सब लोग एक जैसे हैं। चाहे वे गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाले हो, चाहे वे जमीन जोतने वाले हों, सब की दयनीय स्थिति है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इसमें राजस्थान के लिए छूट दे दें। बीपीएल की तरह ही जो एपीएल के परिवार हैं उनको बीपीएल की तरह गेहूं मिले,उनको सहायता मिले। इस प्रकार की नीति आप राजस्थान के प्रति बना दें। जिससे वहां चार साल से अकाल से पीड़ित जनता को फायदा हो सके। मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता होती है जैसा कि पचौरी जी कह कह रहे थे। लेकिन आज पानी का जल स्तर देखे जिन कुंओ से सिंचाई हुआ करती थी, आज उन कुओं मे पीने के लिए पानी नही है। किसान की क्या स्थिति होगी? आप बता दीजिए कि किसान के कितने कुएं सूख गए। आज उन कुओं को गहरा नहीं कराया गया या उन कुओ के जल को बढ़ाने के लिए एनिकट्स बनाकर, नदियो को रोक कर या नदियां जोड़ने की आपकी योजनाएं हैं, यदि ये राजस्थान के किसानो के लिए नहीं की गईं, यह जल स्तर ऊपर नहीं आया तो सारे कुएं सूख जाएंगे। किसान की स्थिति बहुत दयनीय है और यह कर्ज भी चुकाने की स्थिति मे नही है। मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि जब आप कृषि नीति बनाते हैं तो इस ओर ध्यान क्यों नही देते? करोड़ों रुपए इंडस्ट्री वाले खा जाते हैं, पैसा वापस नही देते हैं। उनको छूट दे दी जाती है और किसान यदि पम्प सैट लेने के लिए पन्द्रह हजार ले ले, ट्रैक्टर खरीदने के लिए पैसा ले ले या कृषि के यंत्र खरीदने के लिए थोड़ा बहुत कर्ज ले ले और वह चुक नही पाता है क्योंकि प्राकृतिक आपदा आती है, तो वह किसान के ऊपर आती है। चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे पाला पड़ जाए, चाहे सूखा पड़ जाए, ओले पड़ जाएं तो किसान के ऊपर सारी आपदा आती हैं, इसलिए इससे छुटकारा दिलाने के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब चार-चार साल तक खेती नहीं होगी तो किसान कर्ज देगा कहां से? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि राजस्थान के किसान के साथ यदि न्याय करना चाहते हैं तो उनका कर्ज माफ कर दें। जवाब चाहता हूं कि आप क्या जवाब देते हैं। क्या आप इसकी जांच करेंगे?

**उपसभाध्यक्ष (श्री रम्मा शंकर कौशिक)** : कृपया मीणा जी समाप्त कर दें।

**श्री मूल चन्द मीणा** : महोदय, हमारी पार्टी का टाइम कम है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की ओर ध्यान देते हुए राजस्थान का जो किसान चार साल से खेती नहीं कर पाया है, उस पर कर्जे का जो बोझ है उसको आप समाप्त कर दें। इससे वहां के किसान को बहुत बड़ा लाभ और न्याय मिलेगा, यही मैं कहना चाहता हूं।

SHRI H.K.JAVARE GOWDA (Karnataka): Sir, when we discuss the working of the Ministry of Agriculture and its demand and the facts about agricultural production and the incentives and the drawbacks to the farmer, are all to be seen. We are boasting ourselves that India is self-sufficient in food production, we have sufficient stocks and even though we suffer drought conditions continuously, we are capable of feeding the masses. In reality, it is not correct because production rate is coming down. In days to come, we have to suffer because of the low growth. One is that this country's main occupation in earlier days was agriculture. Now, agriculture is no more a profitable employment occupation. In every village, the youth, the future generation, feel that there is no meaning in doing agriculture. Because, first of all, there is no water; power there is no rain; there is no Minimum Support Price and there is no market price. Under these circumstances, one section of the society, living in cities, affluent families, in the sense that they are working as employees in the Government and private institutions, are enjoying the fruits of the society. But, 70 per cent of the population and their children, who are living in rural areas, who depend on agriculture, they are seeing that they are suffering while on the other hand, some people are enjoying the fruits of society. Under these circumstances, the notion prevailing in the society is that Government are giving a lot of benefits and subsidies to the agriculturists. It may be so apparently, but intrinsically, whether they are able to generate some income out of these subsidies, is a matter to be seen. I am pressing this point because every day, the prices of agricultural products are coming down. Look at the situation five or ten years back. Sugarcane production was giving remunerative prices to the agriculturists. But, now, they are not getting the remunerative prices. They have to put the sugarcane in the factories, but even the factories are not in a position to pay their due amount. Whom should we blame? Should we blame the Government or the factory or the condition of the society as such? As many of the speakers have just now spoken, the mites have caused the fall of coconut production and destruction of trees. Even efforts made by the Central

Government or the State Government, have not stopped the effect of the mites. Now, there is no coconut whatsoever. Whatever the yield is, it is getting very meagre returns. Under these circumstances, how can our farmer get his income from agriculture? And, apart from that, how are we using our water resources? Are we able to use the water technically or are we in a position to use the available water resources in this country in such a way as to feed the entire agriculture in this country? No. Why? The latest propaganda or the scheme we are talking about is inter-linking of rivers. We have already started getting hitches, stating that 'there are environmental problems' and 'if we are going to give our water in future, we are not going to get water also', and 'there is no money for the investment'. These are all the main problems. Still, inter-linking of rivers is to be done. Otherwise, if there is no water, we are not going to provide water to the agricultural field. Definitely, we have not made any progress in the agriculture sector.

The second important point is that even after 55 years of independence, we have provided irrigation to only 20-22 per cent of our farmers, and the rest of them are dependent on monsoon. We all know the vagaries of monsoon, as a result of which we are not able to have sustained agricultural development. Also, we have not evolved a policy or programme to grow agricultural products in dry lands. Now, what is happening? The underground water is depleting alarmingly. Again, what is being done to draw water from under the ground? We have heard several times in the House that a lot of subsidy is being given to the power sector; it goes up to Rs.27,000 crores in a year. That is all right. But to whom are we giving this subsidy? Even after giving Rs.27,000 crores by way of subsidy in a year, are we able to raise the income of the agricultural families? This is a matter for consideration. Even if you are going to give Rs.55,000 crores, would you be able to uplift the agricultural families? That is not happening. But to the outside world, we are saying that we are giving a lot of subsidy to the farmers by way of power subsidy. Even then, what is the quality of power that they are getting? With the present power capacity, they are not able to draw water from 400-500 feet deep. This is the main problem. Even though we are giving subsidy in power, the farmer is not in a position to use that because of low voltage. Now, what is your effort for giving full voltage power so that the farmers can get water from underground?

The next point that I would like to make is regarding fertiliser subsidy. All right; you are giving fertiliser subsidy. But to what extent? Who is actually benefiting out of it? Even after giving subsidised manures, so to say, fertilisers, what is the yield that we are getting and what is the rate you are getting for your sales in the market? It is a fact.that you are not getting proper prices. Under these circumstances, what is the plan of the Government? What would these farmers do to educate their children and to repay their debts? This is the problem that we have to address. Otherwise, we will not be able to provide employment, food to the nation and security to the farmers.

Another important point is regarding crop insurance. In Karnataka, crop insurance was introduced last year, particularly, for potato and other crops. Eight months have passed by. All assessments have been made, but the insurance company has not made any payment. On the one hand, we are saying that the Central Government has not released its share. But on the other hand, the State Governments are saying that they are not be in a position to give their share. Now, who is the ultimate sufferer? It is the farmer who is suffering. With whatever little money he had, he paid the premium amount. But the insurance money has not been paid. Who is responsible for this?

The next important point is regarding watershed programmes which have been taken up all over the country. I would like to request the hon. Minister; kindly go and inspect these watershed programmes. We are giving crores of rupees in Plans. But are we ensuring that the sanctioned amount reaches a particular project or not? In reality, what is happening is that out of, say, Rs.50,000 sanctioned for a particular project, work is done only to the extent of Rs.25,000-30,000 and the rest of it is swallowed by the middle men. This is the problem being faced in this country.

We may plan, we may distribute and we may sanction projects allocate amount. But this is the main disease in our society, which is killing the farmers, is corruption in executing programmes. There is an important point that I want to ask from the Disinvestment Minister, because I feel, if there is a problem, he will apply his mind and try to tackle it. I want to know from him whether the agricultural sector -- almost 99 per cent of which is in the private sector -- is getting any minimum returns of profit. This should be looked into. Eighty-five per cent of the rural people, who are depending upon agriculture, get satisfied with the barest minimum food and

basic necessities of life, with just two or three shirts and dhoties in a year and minimum education for their children. This is the condition of every villager. We cannot take the example of big landlords or some persons who are doing business and are also agriculturists. We cannot take them into account. It is the duty of the society and the Government, irrespective of what type of Government or which party is in power. It is our responsibility to look after the average farmer. Is he getting the Minimum Support Price? The hon. Prime Minister has announced the MSP of Rs.15 or so per tonne after the UP sugarcane farmers' agitation. I am not going to blame this Government or the Prime Minister, because if you have not formulated any policy, if you do not have the money, you cannot suddenly pay to farmers. But this problem has been continuing in our country for the past 55 years. Successive Governments have been making announcements and telling farmers over the years that they are for them, that they are making a lot of schemes, giving subsidies, benefits and everything, but the standard of living of our farmers has been going down. There are no employment opportunities. Why I am stressing this aspect of employment opportunities is because in the days to come, people are going to give up their agricultural operations since agriculture will no longer continue to be a profitable occupation.

**उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक)** : कृपया अब आप समाप्त करें ।

SHRI H.K. JAVARE GOWDA: Drought is a natural calamity. For tackling drought situations, the Government should release adequate funds and foodgrains. The Food for Work Programme should be reviewed. What is happening? In Karnataka, the release of foodgrains under the Food for Work Programme is taking place only between the contractors and the officials, and not for the manual labour. Even if the manual labour is there, it is only 5 or 10 per cent. The rest of the job is being done by the machinery. In papers, they show many names, with their left hand and right hand thumb impressions for purposes of accounts. What I want to say is that the corruption in the society has gone to the extent of swallowing of the provisions made for various schemes, with the result, that those foodgrains and allocations do not reach the common people or the targeted people. For these things, we have to come forward with a result-oriented approach and see to it that these things do reach the common man.

Then, there is an important point about the Indian Meteorological Department. Sir, the predictions made by the Department last year did not come true. Of course, they are human beings. But what is the cost that farmers are forced to pay because of wrong predictions being made by the Meteorological Department? You should collect and analyse all the data and information and utilise satellite services, and then make predictions. If farmers know that your predictions, let us say, about drought, are going to come true, they will not come forward to sow seeds, use manure, fertilisers and other things. Wrong predictions made by the Meteorological Department have caused huge losses and sufferings to farmers. I would urge upon the hon. Minister to see to it that the Indian Meteorological Department is modernised with the latest machinery, equipment and other things.

**उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक)** : कृपया आप आसन ग्रहण करें। श्री ईसाम सिंह।

SHRI H. K. JAVARE GOWDA : With these words, Mr. Vice-Chairman, Sir, I conclude.

**श्री ईसाम सिंह** (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, कृषि नीति के संदर्भ में आपने जो मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। विशेषकर कृषि नीति के संबंध में मैं सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। जहां तक हमारे देश की व्यवस्था की बात है, मेरे से पूर्व वक्ताओं में किसी ने हमारे देश के अंदर सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के क्षेत्र से हिस्सेदारी 22 परसेंट बताई है और किसी ने 23 परसेंट बताई है। इसी के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र से 27 परसेंट की हिस्सेदारी बैठती है और सामाजिक सेवाओं के माध्यम से यह हिस्सेदारी 49 परसेंट सकल घरेलू उत्पाद में बैठती है। अगर मुख्य बिंदु हमारे देश का लिया जाए तो विशेषकर कृषि क्षेत्र के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देश को मिल सकता है। उसका कारण यह है कि 77 प्रतिशत भूमि हमारे देश के अंदर प्लेन है और 23 प्रतिशत भूमि हिली है, जिसको पहाड़ी क्षेत्र कहते हैं।

मान्यवर, मैं एक ही उदाहरण देना चाहूंगा, विशेषकर जापान का, कि जापान में 15 प्रतिशत भूमि प्लेन है और 85 प्रतिशत भूमि हिली है। दो दशक तक भूमि के माध्यम से उन्होंने अपने विकास दर का जो टारगेट रखा, वह 7 और 8 परसेंट का रखा और उसको उन्होंने हासिल भी किया। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे देश के अंदर 77 प्रतिशत भूमि खेती योग्य होने के बावजूद भी हम अपनी विकास दर की बात करते हैं 4 परसेंट की, मैं कोई आलोचना नहीं करना चाहता बल्कि सुझाव देना चाहता हूँ। हमारे देश के अंदर वैसे तो 77 प्रतिशत जो भूमि प्लेन है, उसमें केवल 1/3 भूमि के ऊपर हल चलता है और 2/3 भूमि चाहे वह गवर्नमेंट के पास है या जमींदारों के पास है, वह खाली पड़ी है, उसमें खेती नहीं हो रही है। अगर इस 1/3 भूमि, जिसके ऊपर हल चलता है, उसका औद्योगीकरण कर दिया जाए तो आज

की तारीख में जो 23 परसेंट सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी है यह तीन गुना बढ़ जाएगी और यदि 77 प्रतिशत भूमि में खेती के हिसाब से उसका औद्योगीकरण कर दिया जाए तो आज की तारीख में हमारे देश के अंदर जो सकल घरेलू उत्पाद है उससे दुगुनी राजस्व आय हम केवल भूमि से प्राप्त कर सकते हैं।.तो मेरे कहने का मकसद यह है कि जहां तक व्यवस्था की बात है, व्यवस्था तो गवर्नमेंट ही करती है, चाहे वह कोई भी गवर्नमेंट हो, तो मेरा सुझाव है कि हमारे देश के अंदर हम लोगों को विशेषकर चाइना और जापान का अध्ययन करना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे उन्होंने एक दशक तक खेती के माध्यम से, भूमि के माध्यम से 7-8 परसैंट विकास की दर हासिल की, जबकि हमारे पास, हमारे देश के अंदर इतनी अच्छी लैंड होने के बावजूद हम वह दर हासिल नहीं कर पा रहे हैं। दुनिया में सबसे अच्छी उपजाऊ भूमि यदि किसी देश के अंदर है तो वह भारत में है। मैं हाऊस में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विश्व बैंक की जब रिपोर्ट आती है तो उसमें कहा जाता है कि सबसे ज्यादा गरीबी रेखा से नीचे के लोग भारत में निवास करते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट आती है कि सबसे ज्यादा अगर भिखमंगे कहीं हैं तो वह हमारे देश में हैं। मैं इसलिए सुझाव दे रहा हूं कि यदि इस देश में हम कुछ न करें बल्कि केवल कृषि को उद्योग का दर्जा ही दे दिया जाए तो आज जो विश्व बैंक की रिपोर्ट आई है कि भारत के अंदर 40 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं, उनको भी उसमें रोजगार की गारंटी दी जा सकती है।

मान्यवर, मेरे से पहले वक्ताओं ने यहां कुछ बातें कही हैं। महानगरों में झुग्गी-झोपड़ियों की बात कही है, उनको इससे रोजगार दिया जा सकता है। हिमाचल में चले जाइए, 100-100 किलोमीटर तक प्लेन जमीन पड़ी है गवर्नमेंट के पास। मध्य प्रदेश में, गुजरात में या यू0पी0 में चले जाइए, यही हाल है। तो मेरा सुझाव है कि कृषि को हमारे देश के अंदर उद्योग का दर्जा दिया जाना अनिवार्य है।

दूसरे मैंने तमिलनाडु और केरल का अध्ययन किया है, वहां पर काफी का उत्पादन होता है। 33 परसैंट काफी का उत्पादन केरल में होता है और भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर 600 मीटर से लेकर 900 मीटर तक की हाइट पर काफी की फर्स्ट क्लास की किस्म का उत्पादन किया जा सकता है। ...**(समय की घंटी)**... मैं केवल एक मिनट और लूंगा। तो मेरा सुझाव यह है कि मुझे जब उत्तरांचल में जाने का मौका मिलता है, तो मैं देखता हूं कि वहां का क्षेत्र ऐसा ही है जहां कि 600 से 900 मीटर की हाइट पर बहुत अच्छी किस्म की काफी का उत्पादन किया जा सकता है। मैं इस तरफ सरकार का ध्यान इसलिए आकर्षित करा रहा हूं ताकि सरकार इस तरफ भी ध्यान दे ताकि हम इंटरनेशनल मार्किट के माध्यम से भारत को राजस्व हासिल करा सके।

जहां तक उत्पादन की बात है, हमारे पूर्ववक्ताओं ने उत्पादन की बात कही है, भंडारण की बात भी कही है कि गेहूं सड़ता है या इस तरफ ध्यान दिलाया है कि किसानों को गन्ने का वाजिब रेट नहीं मिलता है, आलू के उत्पादन का वाजिब रेट नहीं मिलता है। इस बारे में मेरा यह सुझाव है कि यदि हमारे पास उत्पादन ज्यादा होता है तो हमको अंतर्राष्ट्रीय मार्किट में जगह बनाने पर भी विचार करना चाहिए।

**6.00 P.M.**

अंत में, उपसभासध्यक्ष जी, आपने मुझे मौका दिया, मैं उसके लिए आपका आभारी हूं। कम समय में ही सही, मैंने अपने सुझाव यहां रखे हैं। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

**उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक)** : श्रीमती एन.पी. दुर्गा। माननीया श्रीमती एन.पी. दुर्गा जी, आपके बोलने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके दल का केवल एक मिनट ही शेष है, आप कृपया अपनी बात तीन मिनट में समाप्त कर दें।

SHRIMATI N.P. DURGA (Andhra Pradesh): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for having given me this opportunity to speak on a subject which is very dear to my heart. It is dear to me because I hail from an agricultural family. The hon. Finance Minister has rightly said in his Budget Speech that our country has the largest irrigated and arable landmass in the world. Our gross arable land is only second to the USA. It is true. It is our greatest reserve. We have to preserve it. But what is the real picture? What is the real plight of our farming community? It is the other way round.

Sir, first I come to the socio-economic conditions of our farmers and agricultural labourers. Agriculture contributes nearly 25 per cent of our GDP and about 70 per cent of the country's population depends on agriculture for their livelihood. But, still, our peasants are in pathetic condition. There are starvation deaths reported every year and many farmers are committing suicides. This is happening in spite of 70 million tonnes of foodgrains rotting in our godowns. It is estimated that harvest and post-harvest losses in agricultural commodities are to the tune of over 65 million tonnes a year. The second point to improve the socio-economic conditions of the farming community is to guide them meticulously about the diversification of agriculture at two levels. The first one is from food crops to cash crops and the second is from agriculture to allied activities like livestock and fisheries.

A new threat to our country's agriculture is from the international competition. The prices of farm products at the international and Indian markets are being moving in opposite directions. The prices of many of the farm products in the international markets are on the decline whereas in Indian markets these are on the upswing. There are two reasons behind it. The first one is rapid progress in the field of biotechnology, which made

available highly productive seeds to farmers in the developed countries. And, the second one is sophisticated farm machinery that is considerably reducing the cost of production.

Sir, coming to subsidy, I would say that the subsidy that the Government of India is giving to its farming community is minuscule. For example, the USA is giving US $ 2,000 subsidy per hectare to its farmers, whereas Japan is giving $ 7,000 and the European Union countries are giving about $ 1,100. There are many other countries which are giving subsidies to their farmers. And, you look at what the Government of India is giving. The Government of India is giving US $ 17.8 per hectare. I am not asking you to give 70 per cent or 75 per cent subsidy, I am only pleading that let there be a level-playing field.

The other point I wish to make is that we should prepare our farmer psychologically, mentally and technologically about the WTO and its implications. Once he is fully aware of the WTO and once he gets proper guidance and support from the Government, he will definitely do miracles for us. Don't forget the Green Revolution. It is this farmer who did it for us. Don't forget the White Revolution. It is this farmer who did it for us. If you push him a bit, I am sure, he will bring 'Gene Revolution' for us as well.

Sir, now, with your permission, I come to the issue of loans that are being given to our farming community. The total credit flow required in the agricultural sector... (*Time bell*) in the 10th Plan, to achieve the targeted growth rate of four per cent, is estimated to be Rs.7,36,570 crores.

Sir, in this context, I demand implementation of the National Agricultural Policy with 20 per cent budgetary support and 25 per cent of the total loans should be earmarked for the agricultural sector by the commercial banks.

Sir, I agree with the hon. Finance Minister that even after 55 years of our Independence we have not really come out of the flood-drought-flood syndrome. This is affecting our agriculture the most. I need not tell this august House as to what is happening in the country due to uneven distribution of water. We all know that. So, here, I emphasise the need for linking all the major rivers in the country to begin with. The Government has given an undertaking before the Supreme Court that it would be done

by 2016. I am happy about it. But, at the same time, I also request the Government to invite private participation in this as well.

Sir, the other point I would like to know from the hon. Minister is whether it is true that the Department of Science and Technology is funding a project for compilation of Atlas of India between 1800 and 2000. I think the idea behind this is to document the agro-climatic zones of India, monsoons, weather changing trends, patterns of climate and rainfall. This is a very good idea. (*Time bell*) Sir, I once again thank you for giving me this opportunity to express my views on this subject. Thank you, Sir.

**उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक)** : माननीय श्री बालकवि बैरागी, चर्चा का समापन भाषण है आपका।

**श्री बालकवि बैरागी** : धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय। बड़ी कृपा है आपकी और मुझे आपने बड़ा आश्वस्त कर दिया क्योंकि आपने अभी दुर्गा बहन जब बोल रही थी तो उनको तिगुना समय दे दिया, तो मैं आपकी उदारता का दुरुपयोग नहीं करूंगा।

**उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक)** : धन्यवाद।

**श्री बालकवि बैरागी** : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय । मैं पहले तो आपका आभार मानता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं कृषि मंत्री जी की अनुपस्थिति को रेखांकित करता हूं कि उन्हें यहां होना चाहिए था क्योंकि हम लोग लम्बी बातचीत कर रहे हैं। मेरी खुशकिस्मती यह है कि मैं कृषि मंत्रालय की उस बातचीत में भाग ले रहा हूं जिसकी शुरूआत आप ही ने की थी और अब आपके आसन पर विराजमान होने के समय ही हम इसका समापन करेंगे। शायद सरकार की ओर से उत्तर मेरे बाद आएगा। चार-पांच-छः बाते मेरे मन में हैं, दिमाग मे हैं, सारी बातें सामने आई हैं, कुछ बातें मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। एक तो इस सरकार से मुझे यह कहना है कि पांच साल की उपलब्धियों का अभी बहुत ज्यादा हल्ला मचाया गया पूरे देश में -यह किया, यह किया, यह किया। इसके बड़े-बड़े विज्ञापन आपने भी देखे, मैंने भी देखे, और लोगों ने भी देखे। यह सरकार उन उपलब्धियों मे एक चीज भूल गई है और यदि वह भी उसमे जुड़ जाती तो मुझे अच्छा लगता। यदि कहीं बातचीत पहले हो जाती तो मैं बताता कि एक उपलब्धि इस सरकार की गए पांच साल मे अकेली इस सरकार की है जो किसी सरकार की नही है। यह एक ही सरकार है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की, एन.डी.ए. वाली सरकार जिसने पांच सालो में पांच कृषि मंत्री दिए हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हर साल का एक मिलता है। आप देखेगे कि दो बार तो नीतीश कुमार जी, तीसरी बार श्री सुन्दर लाल पटवा जी, चौथी बार स्वयं प्रधान मंत्री जी और पांचवीं बार आज अनुपस्थित कृषि मंत्री श्री अजित सिंह जी। जो सरकार पांच साल नें पांच कृषि मंत्री दे उससे हम कृषि नीति की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? कहां है वह कृषि का पेपर जिसका बहुत ज्यादा ढिंढोरा पीटा गया था, हल्ला मचाया था और इसी सदन में कहा गया था कि हम पहली सरकार

हैं जिसने कृषि का पेपर दिया है। जो भी मंत्री आता है वह शायद किसी दूसरे मंत्री के सिरहाने या पैताने उस पेपर को रख करके चला जाता है और परिणाम यह होता है कि इस देश मे गए पांच सालो मे किसानों ने जितनी आत्म हत्याएं की उतनी किसी वर्ष में आत्म हत्याएं नही हुई। यहां तक कि अनुपातिक स्तर में भी दहेज के मामलों में बहुओ ने भी आत्म हत्याएं नही की होंगी जितनी कि किसानो ने की है। यही इस सरकार की उपलब्धियां हैं और हम इस सदन मे बैठ करके यही काम करते रहते हैं। आप भी झकझोरते हैं, हम भी झकझोरते हैं। लेकिन शुतुरमुर्ग जैसी इस सरकार की कब तक आप रेत में से इसकी मुंडी पकड़ करके बाहर इसकी चोंच निकालेंगे। शुतुरमुर्ग का करेक्टर है इस सरकार का। हम कहते हैं तूफान आ रहा है, हम कहते हैं मर जाएंगे, तो धीरे से प्रधान मंत्री सहित सब लोग बोलते हैं कि हमारी तो मुंडी रेत मे फंसी हुई है। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ग्लानि के साथ कह रहा हूं, बहुत पीड़ा के साथ कह रहा हूं यहां पर खड़े होकर इस देश के प्रधान मंत्री जी ने एक वाक्य कहा था। मैं उस वाक्य को आज तक भूल नहीं पाया और आप भी यहां थे तथा स्वर्गीय कृष्ण कांत जी यहां पर विराजमान थे। यहां के प्रधान मंत्री जी ने खड़े होकर कहा था कि माननीय सभापति महोदय, हमारी सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो यह यह है कि "किसानों ने बहुत पैदा कर दिया है हम कहां रखें?" जिस देश मे किसान का उत्पादन प्रधान मंत्री की समस्या बन जाए, मैं जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी उत्पादन को हतोत्साहित कर रहे हैं या प्रोत्साहित कर रहे हैं। यदि हम हतोत्साहित कर रहे हैं तो दुर्भाग्य है। किन्तु उनकी नीतियों के कारण इनके अमलीकरण के कारण इस सरकार की शुतुरमुर्गी प्रवृत्ति के कारण इस देश का किसान निराश है, उदास है, हताश है और आज बिल्कुल मशान घाट की कगार पर बैठा हुआ है। मैं भी जाता हूं, आप भी जाते हैं प्रमुख अतिथि बन करके स्कूलों में। मैं बहुत ही बौद्धिक स्तर के मंत्री के सामने यह बात कह रहा हूं मेरे प्रिय श्री अरुण शौरी जी मेरे सामने बैठे हुए हैं। मैं एक स्कूल में मुख्य अतिथि बन कर के गया। वहां छोटे-छोटे बच्चे थे, किसानों का गांव था, हमारा अपना चुनाय क्षेत्र का सिलसिला था। मैंने बच्चों से पूछा कि बताओ बच्चों, पढ़ने के बाद आप इस देश में क्या बनना चाहेंगे? तो सन्नाटा छा गया। मैंने कहा कि अच्छा बताओ, कितने कलक्टर बनना चाहते हैं? एक-दो ने हाथ ऊंचा किया। फिर मैंने कहा कि बताओ, कितने लोग इंसपेक्टर बनना चाहते हैं पुलिस के? तो तीन-चार ने हाथ ऊंचा कर दिया। मैंने पूछा कि कितने लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं? इस पर दो-तीन ने हाथ ऊंचा कर दिया। मैंने पूछा कि कितने डाक्टर बनना चाहते हैं। तो तीन-चार ने हाथ ऊंचा कर दिया। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जब मैंने पूछा कि तुम में से कितने किसान बनना चाहते हैं तो किसी एक बच्चे ने भी हाथ ऊंचा नहीं किया। किसानों का देश और किसानों के बच्चे इस देश में किसान बनने को तैयार नहीं हैं।

मैं कल रात की कहानी आपके सामने दोहरा रहा हूं। मैं मध्य प्रदेश से लौटकर आ रहा था। जिस ट्रेन में मैं आ रहा था, उसकी छत पर कम से कम 2,3 या 4 हजार लड़के बैठे हुए थे। ट्रेन छः घंटे लेट सराय रोहिला पहुंची। मैं आज उससे उतरा हूं। वे सब किसानों के बच्चे थे। वे कहां गये थे? वे राजस्थान में पुलिस में सिपाही का इंटरव्यू देने के लिए गये हुए थे। किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, इस मोड़ पर लाकर इस सरकार ने इस देश को खड़ा कर दिया है। उत्पादन करने को अभिशाप माना जाता है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि अभिशाप है कि हमारे यहां किसान ने ज्यादा पैदा कर दिया है। किसान कहां जाएगा? वह इतना बर्दाश्त करता है, इतना सहता है कि या तो राम के भरोसे चल रहा है या प्रकृति के भरोसे चल रहा है,

देव के भरोसे चल रहा है। आपने सही पीड़ा व्यक्त की है। क्या कहा इस मंत्रालय के बारे मे? हम कितना लम्बा बोले? एन.डी.ए. के एक घटक के प्रतिनिधि ने अभी अभी, इसी वार्ता मे भाग लेते हुए इस संपूर्ण मंत्रालय पर संसदीय समिति से जाँच की मांग की है, अभी इसी सदन मे और आप स्वयं इसके गवाह हैं। वह चाहता है, एन.डी.ए. का एक घटक चाहता है। करप्शन के, भ्रष्टाचार के मामले कितने उठाए जाएं? भाई मूल चन्द मीणा जी ने जो मुद्दा उठाया, वह छोटा मुद्दा नही है। वह करोड़ो का मामला है, एक-दो का मामला नही है। गेहूं आपका कहां चला जाता है? हर चीज मे गिरावट के बावजूद सारा का सारा उस बाजार में आ जाता है। आपका पक्षपात इस सीमा तक बढ़ गया है कि राजस्थान तड़प रहा है, मध्य प्रदेश तड़प रहा है, छत्तीसगढ़ तड़प रहा है और आप वहां पर क्या कर रहे हैं? हम अनाज मांग रहे हैं और माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, ये वहां त्रिशूल बांट रहे हैं और कहते हैं कि अनाज तो नहीं है, त्रिशूल ले लो। इस तरह से देश को चलाया जा रहा है, किसान को चलाया जा रहा है, किसानो को शामिल किया जा रहा है। स्वयं रामबख्श जी ने आपके सामने अभी कहा है, वे इस समय सदन मे मोजूद हैं, उन्होने कहा कि किसानो को क्रेडिट कार्ड तो दिये हैं लेकिन उनमे लेनदेन हुआ है। यह उनकी अपनी पार्टी के इस सदन के एक बहुत जिम्मेदार सदस्य का वक्तव्य है। इस दिशा मे हम जानना चाहेगे कि सरकार का क्या उत्तर हो सकता है, सरकार कितनी तैयार है? मैं अगर आपके सामने दे दूं तो एक लम्बी लिस्ट मेरे पास है और मैं इस बात को जानता हूं कि हमारे साथ कभी भी इंसाफ नही हो पाता है। आप देखिए कि खेतिहर मजदूरों की क्या स्थिति है? आपके स्वयं के प्रश्न के उत्तर मे यहां सरकार ने कहा था । खेतिहर मजदूर जिसका योगदान 27 प्रतिशत था, जब मैं बोल रहा हूं तब 13 प्रतिशत रह गया है, 14 प्रतिशत खेतिहर मजदूर सड़क पर आकर खड़े हो गये हैं। वह न तो पढ़ा हुआ है, अधपढ़ा है, उसके पास उम्र नही है, उसके पास काम करने की शक्ति नही है और आज वह आपकी कृपा से सड़क पर खड़ा हुआ है। जो किसान कल तक अपनी जमीन का मालिक था, वह आज उसी खेत मे मजदूरी करके अपना गुजर बसर कर रहा है। आप 180 दिन का काम देने की बात करते हैं, उसके बाद आपके पास काम नही है। आज तीन-चार साल से यहां सूखा है और सूखे मे सब दूर तक सन्नाटा खिचा हुआ है लेकिन किसी को फुरसत नही है। महोदय, मैं एक प्रश्न करूं? माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, चार-पांच साल से मुझे भी आपके आर्शीवाद से इस सदन में बैठने का मेरे नेताओ ने, श्रीमती सोनिया जी ने मौका दिया है, मैं कांग्रेस का आभारी हूं। लेकिन जब अखबार देखते हैं तो इस देश के प्रधानमंत्री महोदय कहां बैठे हुए मिलते हैं? उद्योगपतियों में। जिन लोगो के बीच में प्रधानमंत्री जी ने बैठने का समय निकाला, उनकी बड़ी कृपा है, लेकिन आज तक किसानो के बीच मे जाकर बैठने का समय इस देश के प्रधानमंत्री ने पांच साल मे नही निकाला है और उसके बाद भी कहते हैं कि हम सरकार को ठीक से चला रहे हैं। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, क्या कहा जाए। ऐसा लग रहा है कि किसी एक इंजन में ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, सबकी बोगियां शंट कर दी गयी हैं। डीरेलमेंट तो होगा ही। कैसे चलेगा? सारी बोगियां आप एक इंजन मे शंट कर देंगे तो कैसे चलेगा? छोटे-बड़े जितने लोग बैठे हुए हैं, एन.डी.ए. के जितने घटक हैं, उनकी क्या स्ट्रैथ है? उनकी एक ही स्ट्रैथ है कि सरकार में बने रहना है और बनाए रखने के लिए उन्हे एक व्यक्ति मिल गया है जिसके सहारे पर इस देश मे किसान के मूल्य पर सब कुछ हो रहा है। जो कुछ इस देश में हो रहा है, किसान के मूल्य पर हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं खाद, पानी, बिजली, बीज और अंतत: मंडी का भाव - किसान कहां है? प्रत्येक सदस्य ने इस पीड़ा को यहां पर व्यक्त किया है। हर सदस्य इस बात

पर बोला है। समय पर खाद नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है और जैसे तैसे करके जब किसान मंडियो मे घूमता है तो वहां भाव नहीं है। केवल भारतवर्ष का किसान ऐसा है। मैं नही जानता कि दूसरे देशों मे क्या स्थिति है लेकिन केवल भारतवर्ष का किसान ऐसा है जो अपने उत्पादन का मूल्य स्वयं तय नहीं करता है। कार बनाने वाला कार का मूल्य खुद तय करता है, जूता बनाने वाला जूते का मूल्य खुद तय करता है, पॉलिश बनाने वाला पॉलिश का मूल्य खुद तय करता है, मशीन बनाने वाला मशीन का मूल्य खुद तय करता है लेकिन माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इस देश के किसान को हम यह अधिकार भी नही देते है कि वह अपने उत्पाद का मूल्य स्वयं तय कर पाए। यह बात अभी चल रही थी यहां पर। आप फलो की बात कर रहे हैं, आप देखते हैं संतरे फेंके जा रहे हैं, आप देखते हैं लहसुन फेका जा रहा है, आप देखते हैं हर चीज़ फेकी जा रही है सड़को पर। यह तो गनीमत है। मैं कहना चाहता हूं हुक्मदेव जी से, ये मेरे मित्र हैं, सामने बैठे हुए हैं - गनीमत है कि इस देश मे मंदिर बहुत हैं और जन्म से लेकर मृत्यु तक नारियल काम आता है वरना माननीय मंत्री महोदय, ये नारियल का उत्पादक किसान इन नारियलो को आपके और हमारे सिर पर फोड़कर बता देता। इंदिरा गांधी ने इस देश मे हरित क्रांति की और आप उसे रक्त क्रांति की तरफ मोड़ते चले जा रहे हैं, यह इलज़ाम नहीं, मेरा विवेचन है और मैं एक विचारक के नाते कह रहा हूं आपसे कि कृपा करो, दया करो, इस देश के किसान को समझो। इस देश का 76 फीसदी व्यक्ति जब निरीह, असहाय, अनाथ मुद्रा मे आपके सामने खड़ा हो जाएगा तब देश आगे नहीं बढ़ सकेगा। सरकार तो आप चला लेगे लेकिन देश नही चल पाएगा। मैं एक बात कहकर आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे सिर्फ एक बात कहनी है। ट्रैक्टर का कर्ज़दार किसान ट्रैक्टर की किश्त देना चाहता है लेकिन ट्रैक्टर का अर्थशास्त्र उसके खिलाफ हो गया है। वह ड्राइवर नहीं रखता है। अपने ट्रैक्टर पर किसान कही भी ड्राइवर नहीं रखता है, उसकी पत्नी, उसकी बेटी, उसका बेटा, उसका चाचा, उसका भाई, कोई न कोई खुद ट्रैक्टर चलाता है। ड्राइवर की तनख्वाह देना शुरू कर दे तो वह मर जाएगा। डीज़ल का भाव आप बढ़ा रहे हैं, फसल का भाव आप गिरा रहे हैं, लागत बढ़ रही है, कीमत घट रही है। वह बैंक में चुकाना चाहता है लेकिन हैसियत तो उसकी खत्म हो गई है, परचेज़िंग पावर उसकी खत्म हो गई है, उसकी जेब शून्य हो गई है और जब किसान की जेब शून्य हो गई है तो दुकानों के शटर गिर गए हैं, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, चिमनियों ने धुआं उगलना बंद कर दिया है, आप स्वयं इस बात के गवाह हैं। जब बाज़ार ही नहीं खुलेंगे तो कहां होगा लक्ष्मी पूजन? क्या होगा सिलसिला? सारा का सारा इस धरातल पर आपको सोचना चाहिए, आपको विचार करना चाहिए और विचार करके शुतुरमुर्ग की मुद्रा में से अपनी मुंडी को महाराज बाहर निकालो, बाहर निकाल करके इस रेतीले तूफान का सामना करने के लिए अपनी हिम्मत जुटाओ। अपने प्रधानमंत्री जी को समझाओ और कहो अपने मंत्रिमंडल की बैठको मे कि श्रीमन्, बहुत ज्यादा हो गया, मैं आपसे एक मांग करना चाहता हूं और वह किसानो के हक मे करना चाहता हूं। हम जब भी किसान की बात करते हैं, तब अनाज की बात करते हैं लेकिन फलोद्यान की बात नहीं कर पाते हैं। हमारे यहां फलो में बहुत तरक्की हुई। फलों के मामले मे भारतवर्ष बहुत ऊपर उठा है। आपने देखा होगा कि किसान ने अपनी हिम्मत, अपनी तपस्या, अपने खून, अपने पसीने से सब कुछ किया है। आपका अपेक्षा भाव उसने बरदाश्त किया है और आपके उपेक्षा भाव को उसने स्वीकार कर लिया है। उसने मान लिया है कि सरकार मेरी तरफ ध्यान नही देगी, उसके बावजूद दूध के मामले में आज देश को सर्वोपरि करके उसने दिखा दिया। अनाज के मामले में आप देख रहे हैं कि भंडार भरे पड़े हैं और किसान को आप मूल्य दे

नही पा रहे हैं। शक्कर इतनी पडी हुई है कि जब मैंने सवाल किया, यहां पर भाई शरद यादव बैठे हुए थे, उनका सवाल था, मुझे पूरक प्रश्न दिया माननीय सभापति महोदय ने, तो मैंने कहा कि शक्कर इतनी पड़ी हुई है, आप उसे बेचकर हवाई जहाज़ खरीद रहे हैं क्या? तो आपके मंत्रिमंडल के एक मंत्री ने कहा कि पढ़ा तो मैंने भी है, पता मुझे कुछ नहीं। अजीब सा मंत्रिमंडल है! कहते हैं पढ़ा तो मैंने भी है पर पता मुझे कुछ नहीं है। उनके गोदाम में शक्कर है, वह बिकने वाली है, उसे बेचकर यदि आप हवाई जहाज़ खरीद रहे हैं तो बुरा नहीं कर रहे हैं लेकिन स्पष्ट हो जाना चाहिए, बात सामने आनी चाहिए।

एक निवेदन और करूं - दो विश्वविद्यालय है आपके पास फलोद्यान के। केवल दो विश्वविद्यालय हैं, एक सोलन में, हिमाचल प्रदेश में और दूसरा कोयम्बटूर में, तमिलनाडु मे। तीसरा विश्वविद्यालय, भारत का पूरा मध्य क्षेत्र, आप गुजरात से कामाख्या तक चले जाइए, सारा खाली पड़ा है। हॉर्टिकल्चर का, फलोद्यान का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। मध्य प्रदेश का मंदसौर ज़िला, मेरा अपना इलाका है। यहां डॉ.कैलाशनाथ काटजू के नाम पर एक इतना बड़ा सक्षम फलोद्यान का कॉलेज है, जिसे हम उद्यानिक महाविद्यालय कहते हैं। यहां आप केवल विश्वविद्यालय का उपकुलपति नियुक्त कर दीजिए ताकि देश का यह भाग जो तकनीकी दिशा से आगे बढ़ गया है... जब भी हम आपसे मांग करते हैं, आप कहते हैं, वेबसाइट पर आ जाइए, वेबसाइट पर आ जाइए। तो श्रीमन्, भगवन्, हमारे किसानों के पास कौन सा वेबसाइट है? जिस खलिहान मे वह बैठा है, उसके पास कोई टेलीविज़न नहीं है, उसके पास कोई कंप्यूटर नही है। एक विश्वविद्यालय आप दीजिए मध्य प्रदेश को, हमारी विधान सभा तैयार है, हमारी सरकार तैयार है। हम आपसे यह मांग रहे हैं और किसान के हित में मांग रहे हैं कि किसान ज्यादा पैदा करेगा। सबने निराश किया होगा माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, सबने निराश कर दिया होगा किंतु इस देश के किसान ने देश को कभी निराश नहीं किया। उसको कुछ मिला कि नहीं मिला, वह अपना काम करता रहा। सूखा है तो हल चल रहा है, गीला है तो हल चल रहा है, बाढ़ हो तो हल चल रहा है, सरदी हो तो हल चल रहा है, ऊपर वाला खुश तो हल चल रहा है, नीचे वाला नाराज़ तो भी हल चलता चला जा रहा है और यह बराबर मेहनत करता चला जा रहा है।

हम आप से यह प्रार्थना करना चाहते हैं, इस सरकार को यह कहना चाहते हैं, पंडित अटल बिहारी जी की, वाजपेयी जी की सरकार से यह आग्रह करना चाहते हैं। यदि एनडीए की सरकार है, चौबीस, पच्चीस या छब्बीस राजनीतिक पार्टियां मिलकर के भी यदि इस देश के किसान का हित नहीं कर पाईं तो माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय कौन सा जन्म ढूंढते फिरेंगे? मैं इन शब्दों के साथ आपका आभार मानता हूं, धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि अजित सिंह जी इस पीड़ा को समझेंगे और हुक्मदेव जी आप तो ज्यादा समझें कृपा करके क्योंकि अजित सिंह ही आए हैं, चले जाएंगे। सुन्दरलाल पटवा आए थे, चले गए। नीतीश कुमार जी रहे, चले गए लेकिन भगवन आप तो यहां के यहां बैठे हुए हैं, इसी विभाग में हैं। इसलिए विनती हम आपसे ज्यादा कर रहे हैं। आप नहीं हिले, सारी ईंटें खिसक गई लेकिन आप वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। हम आपसे विनती ज्यादा करते हैं कि आप कुछ करेंगे। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप थोड़ा सा विचार करेंगे इस दिशा में। इस देश के किसान की पीड़ा को समझकर, यह किसानों का देश है, यह सिद्ध करने में इस सरकार की भूमिका भी आप कुछ ठीक-ठीक कर सकेंगे। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और कोई विशेष आग्रह नहीं करके सिर्फ आपसे

इतना निवेदन करता हूं कि जोत छोटी होती चली जा रही है, किसान छोटा होता चला जा रहा है। यदि इस छोटी जोत मे किसानों को उसका बराबर मूल्य भी नहीं मिला तो किसान मर जाएगा और अगर किसान मर गया तो हिन्दुस्तान मर जाएगा। मैंने तो चिल्ला-चिल्ला कर नारा दिया है कि 'खेत सुखी, खलिहान सुखी, तो सारा हिन्दुस्तान सुखी और खेत दुखी खलिहान दुखी तो सारा हिन्दुस्तान दुखी'। आप दुख से रहना चाहते हैं कि सुख से रहना चाहते हैं, इसका फैसला आप करे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक)** : माननीय राज्य मंत्री जी। जवाब कल देगे।

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव)** : महोदय, हम कल जवाब देगे।

**उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक)** : अब हम लोग कल मंगलवार दिनांक 22.04.2003 तक 11.00 पूर्वाह्न तक के लिए उठते हैं।

The House then adjourned at twenty-two minutes past six of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 22nd April, 2003



MGIPRRND—3223 RSS/03—375 Copies.